सूर्योदय 6:20 सूर्यास्त 5:56

आज का तापमान

शिमला	14.0 न्यू	22.0 अधि
धर्मशाला	17.0 न्यू	24.5 अधि

बाजार

सेंसेक्स	72,472
निफ्टी	22,520

सोना 1,50,100 चांदी 2,21,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 24 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 166, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

उत्तराखंड से भाजपा के दिनेश आर्य निर्विरोध बने राज्यसभा सदस्य

एजेंसी, देहरादून। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार दिनेश आर्य राज्यसभा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। शुक्रवार को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में प्रभारी सचिव एवं रिटर्निंग ऑफिसर हेम चन्द्र पंत ने उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम सहित विधानसभा सचिवालय के अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिनेश आर्य को औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उनके निर्विरोध निर्वाचन से राज्यसभा में उत्तराखंड की संबंधित सीट पर भाजपा का प्रतिनिधित्व तय हो गया है।

ट्रक-बोलेरो की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत

एजेंसी, भुज। गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार सुबह ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर में सात मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हादसे के समय बोलेरो में 15 से अधिक मजदूर सवार थे। जानकारी के अनुसार, मजदूरों को लेकर बोलेरो खावड़ा के पास आरई पार्क मार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में सवार लोग वाहन के केबिन में फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को खावड़ा से भुज ले जाया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लॉरी-पिकअप वैन की टक्कर, पांच की मौत

एजेंसी, रायगंज। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर शुक्रवार तड़के लॉरी और पिकअप वैन की आमने-सामने टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार मजदूर और पिकअप वैन का चालक शामिल हैं। सभी मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस के अनुसार, पिकअप वैन सिलीगुड़ी से मुर्गियां उतारकर वापस लौट रही थी। सुबह करीब चार बजे बांका मोड़ के पास उसकी लॉरी से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वैन में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

मणिपुर में ग्रेनेड हमले में आरएएफ का हेड कांस्टेबल घायल

एजेंसी, इंफाल। मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले के न्यू लम्बुलेन इलाके में वीरवार रात अज्ञात उपद्रवियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) का एक हेड कांस्टेबल मामूली रूप से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार, गुरुवार रात करीब 10 बजे अज्ञात हमलावरों ने बी/107 आरएएफ के प्रवेश द्वार पर ग्रेनेड फेंका। यह घटना पोरोमपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। घायल जवान की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी हेड कांस्टेबल धनंजय राय के रूप में की गई है। हमले में शामिल लोगों की पहचान भी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीजेपी के प्रदर्शन से पहले सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार

सीजेआई सूर्यकांत बोले- 'मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं'

एजेंसी, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर ज्यादा सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा। उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए।



दरअसल सीजेपी के होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए से 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। वहीं नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कल कैंसिल रहेंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मेट्रो की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। अधिकारियों को मेट्रो और अन्य ट्रेनों की आवाजाही इस तरह नियंत्रित करने पर विचार करना होगा कि आम लोगों को परेशानी न हो। इस फैसले की जानकारी दी जाए और शहर में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एडवाइजरी अखबारों और वेबसाइटों पर भी प्रकाशित की जाए।

आम लोगों की सुविधा: आम नागरिकों को बेवजह परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बस इतना ही चाहते हैं। **सुरक्षा बनाम अधिकार:** रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे हैं और सरकार के पास सुरक्षा के दूसरे साधन भी हैं। आप उनका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आम नागरिकों को भी स्टेशनों पर जाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का पूरा हक है। **सख्त टिप्पणी:** 'क्या आप मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे?' **प्रदर्शन स्थल:** जंतर-मंतर बहुत छोटी जगह है, प्रदर्शन के लिए किसी बड़ी जगह पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन में परिवार के साथ शामिल होंगे केजरीवाल



आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वह 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन में अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। उन्होंने देशभर के लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की।

एक दिन पहले 'लाल हिट जनता पार्टी' का प्रदर्शन

जंतर-मंतर पर सीजेपी के बड़े प्रदर्शन से एक दिन पहले शुक्रवार को 'लाल हट जनता पार्टी' से जुड़े लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कथित हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने जनपथ पर प्रदर्शन किया। संगठन के प्रतिनिधि अयान भटनागर ने कहा, अगर कोई बाहरी व्यक्ति को भी गाली देता है तो हम उसे रोकते हैं। प्रधानमंत्री हमारे अपने परिवार का हिस्सा हैं और उनके खिलाफ ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं है।



प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से मिले, बातचीत कर जाना अनुभव



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चीन के शंघाई में हुई वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन 2026 में शामिन होने वाले प्रतिभागियों से अपने आवास पर मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा- इन शानदार युवाओं ने वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। लोक कल्याण मार्ग में उनसे मुलाकात की और उनके अनुभव भी जाने।

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी उन्होंने पोस्ट शेयर किया और लिखा- वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन 2026 में चमक बिखेरने वाले युवा साथियों का अभिनंदन!

एक आधिकारिक बयान में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन 2026 में भारत 6 सिल्वर और 20 उत्कृष्टता पदक जीतकर 10वें स्थान पर रहा। वहीं, 2024 में फ्रांस के ल्योन में हुए वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन भारत 13वें स्थान पर रहा था, जहां भारत ने चार कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक हासिल किए थे। मंत्रालय ने कहा कि अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए भारत के यह परिणाम वैश्विक मंच पर देश के कुशल युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

◆ **शंघाई में भारत ने जीते 6 रजत और 20 उत्कृष्टता पदक**

बता दें कि 22-27 सितंबर 2026 तक हुए इस छह दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 70 देशों के 1,400 से अधिक युवा प्रतियोगियों ने भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व अब तक के सबसे बड़े 70 प्रतियोगियों के दल ने किया, जिन्होंने उभरती टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, क्रिएटीविटी जैसे 63 फील्ड में भाग लिया था।

नाना पाटेकर के निधन मामले में केस दर्ज, मौत की जांच में जुटी पुलिस



एजेंसी, मुंबई। गोवा पुलिस ने अभिनेता नाना पाटेकर के निधन मामले में मेडिको-लीगल 'अप्राकृतिक मौत' का केस दर्ज किया है। पुलिस मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और परिवार के बयानों की जांच करेगी। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, गोवा पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत केस दर्ज किया है। पीएसआई नितिन नाइक इसकी जांच कर रहे हैं।

पणजी में दर्ज केस के मुताबिक, नाना पाटेकर को गुरुवार सुबह गोवा के डोना पाउला स्थित ओशन पार्क से मणिपाल अस्पताल, बांबोलिम लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देर रात पुणे के फार्महाउस में शव का अंतिम संस्कार किया गया।

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शेखर सालकर ने बताया कि नाना पाटेकर को अस्पताल में मृत अवस्था में ही लाया गया था। इसी वजह से पुलिस केस दर्ज कराना पड़ा और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर भेजा गया। डॉक्टर के मुताबिक प्राथमिक तौर पर यह कार्डियक अरेस्ट का मामला लगता है। उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर पहले से दिल की बीमारी के मरीज थे और उनका इलाज चल रहा था।

भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता: ज्योतिरादित्य सिंधिया

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। ये कंपनियां सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और निर्धारित मानक को पूरा करने के बाद अपनी सेवाएं शुरू कर सकती हैं।



नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2026 के 10वें संस्करण में प्रेस वार्ता के दौरान सिंधिया ने अमेरिका के उद्योगपति ऐलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सेवाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि एक 'खास' कंपनी की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तीन कंपनियों को उपग्रह संचार (सैटकॉम) लाइसेंस मिल चुके हैं और वे सुरक्षा संबंधी शर्तों तथा निर्धारित लक्ष्यों को अलग-अलग पूरा करने के बाद परिचालन शुरू कर सकती हैं।

सिंधिया ने बताया कि मस्क की स्टारलिंक, रिलायंस जियो की उपग्रह सेवा इकाई जियो सैटकॉम और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब को लाइसेंस मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अमेजन की कुइपर ने इस क्षेत्र में रुचि दिखाई है, उसे भी निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। तीन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं। सरकार जब राजस्व आधारित शुल्क व्यवस्था तय कर देगी, तब उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। इसके बाद जब वे अलग-अलग सुरक्षा शर्तों को पूरा कर लेंगी, तब परिचालन शुरू कर सकती हैं।

संचार मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) और दूरसंचार विभाग 'सैटकॉम स्पेक्ट्रम' की मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर अंतिम निर्णय के करीब हैं। राहुल गांधी और ऐलन मस्क के बीच 'एक्स' पर हुई बातचीत की पृष्ठभूमि में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कहा कि कांग्रेस को शुरुआत में एक खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने पर आपत्ति थी और अब उसे इस बात पर आपत्ति है।

नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार ने तोड़ा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रिकॉर्ड



एजेंसी, कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी/पुडुचेरी। प. बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की 5 विधानसभा सीटों और असम की एक लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को आ गए। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटें भाजपा ने जीत ली है। वहीं तमिलनाडु की दो सीटों पर टीवीके ने कब्जा किया।

उधर, पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की। वहीं, असम के नगांव लोकसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है।

नंदीग्राम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हसीरानी रथ 122753 वोटों से जीत गईं हैं। उन्हें कुल 164427 वोट मिले। हसीरानी ने इस सीट पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हसीरानी ने 1,22,753 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह 1967 के सीट के अस्तित्व में आने के बाद जीत का सबसे बड़ा अंतर है। इससे पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 2016 में शुभेंदु अधिकारी के नाम था। तब उन्होंने टीएमसी के टिकट पर सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया था।

◆ **उपचुनाव में 1.22 लाख वोटों से जीत; पुडुचेरी में एनडीए, तमिलनाडु की दोनों सीटें टीवीके जीती**

हरियाणा में जनशिकायतों के समाधान में ढिलाई बर्दाश्त नहीं: सीएम नायब सैनी



एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविरों, जनसंवाद पोर्टल और एसएमजीटी पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निपटारे में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए और सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्होंने शिकायतों की मौजूदा स्थिति और उनके निपटारे को लेकर अधिकारियों के साथ गंभीरता से चर्चा की। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनसेवा की दिशा में अहम कदम हैं। इनका उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समय पर समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना होगा। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों में न हो, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिले। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से समाधान शिविरों की नियमित निगरानी की जा रही है। शिकायतों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि समस्याओं के समाधान में होने वाली देरी को दूर किया जा सके।

बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों के निपटारे को प्राथमिकता देने और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यौन उत्पीड़न के आरोपों में कांग्रेस सांसद बिमोल जेएनयू से बर्खास्त

एजेंसी, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर एवं मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई यौन उत्पीड़न के आरोपों की आंतरिक समिति द्वारा जांच पूरी करने और उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई है। समिति ने संबंधित सेवा नियमों के तहत कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। प्रोफेसर अकोइजम के खिलाफ कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायतें दर्ज करवाई थीं। इसके बाद विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच शुरू की थी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया। अकोइजम मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं।

भारतवंशी नवनीतम पिल्लै को शांति नोबेल सम्मान

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष व न्याय के लिए मिला पुरस्कार

एजेंसी, ओस्लो। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2026 का शांति पुरस्कार भारतवंशी नवनीतम नवी पिल्लै को देने का ऐलान किया है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मीं पिल्लै ने रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला समेत कई लोगों की मदद की थी। पिल्लै को युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया है। नोबेल समिति ने कहा कि दुनिया में युद्ध और संघर्ष बढ़ रहे हैं। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना और उसे मजबूत करना बेहद जरूरी है।

पिल्लै को दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2026 में नोबेल पुरस्कार की राशि करीब 11.5 करोड़ रुपए है। नवनीतम नवी पिल्लै का जन्म 23 सितंबर 1941 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था।

उनका परिवार भारतीय तमिल मूल का है। उनके दादा 1890 के दशक में भारत से बंधुआ मजदूर बनकर दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां वे गन्ने के खेतों में काम करते थे। एक हादसे में उनके दोनों हाथ चले गए। परिवार की आर्थिक हालत खराब होने के कारण उनके बेटे नारायणसामी नायडू को महज 8 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा।

मंडेला समेत राजनीतिक कैदियों की मदद की

पिल्लै ने 1973 में याचिका दायर कर रॉबेन आइलैंड जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को वकीलों की मदद लेने का अधिकार दिलाया। इनमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। हालांकि कैदी के तौर पर उनकी मंडेला से कभी मुलाकात नहीं हुई। जब मंडेला राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 1995 में नवी पिल्लै को दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली गैर-श्वेत महिला थीं। पिल्लै के करियर का सबसे अहम पड़ाव रवांडा में नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई रहा। 1994 में रवांडा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था। इसमें तुत्सी समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण बनाया। 1995 में पिल्लै इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश नियुक्त हुईं। उन्होंने 1999 से 2003 तक इसकी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया।



मुख्यमंत्री धामी की पहल से विदेश में नौकरी का सपना साकार, 106 युवाओं को मिला रोजगार

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड के युवाओं का विदेश में नौकरी का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक प्रदेश के 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए उन्हें विदेशी भाषाओं में पारंगत बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जबकि उत्तरकाशी और टिहरी जनपद में भी जल्द ही विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री धामी की पहल पर मई 2023 में इस रोजगारपरक योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के क्रियान्वयन के लिए कौशल एवं सेवायोजन विभाग के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को वैश्विक जरूरतों के अनुरूप तैयार कर अधिक से अधिक संख्या में विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए देहरादून में जर्मन भाषा के 75 और जापानी भाषा के 45, अल्मोड़ा में जर्मन भाषा के 22 और बागेश्वर में जापानी भाषा के 16 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जनपद देहरादून में जर्मनी के लिए 04 बैच, जापान के लिए 02, जनपद अल्मोड़ा में जर्मनी के लिए 01 और जनपद बागेश्वर में जापान के लिए 01 बैच में भाषा प्रशिक्षण संचालित है। सरकार के प्रयासों से अभी तक 106 युवा विदेशों में रोजगार पा चुके हैं। इनमें 75 जापान, 01 जर्मनी और 30 युवा सऊदी अरब में हेल्थ, हॉस्पिटेलिटी और अन्य सेक्टर में कार्यरत हैं।

> **मुख्यमंत्री** कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना प्रदेश सरकार की कसौटी पर खरी उतरी है। योजना की सफलता को देखते हुए विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। युवाओं को वैश्विक मांग के अनुरूप आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। अधिकारियों को इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
>
> **पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड।**



यूपी कैबिनेट | सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर पीएम के सम्मान में नामकरण का प्रस्ताव पारित

अब नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा जेवर एयरपोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक बताया।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार के मुखिया रहते हुए 25 वर्ष पूरे किए। उन्होंने इस यात्रा को सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से जुड़ा बताया।



मुख्यमंत्री के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक ढांचे का विस्तार हुआ है।

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में करीब 2,483 किलोमीटर लंबे 42 राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। दादरी को ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रमुख जंक्शन बताते हुए उन्होंने कहा कि एक हजार किलोमीटर से अधिक फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 65 लाख से अधिक परिवारों को आवास मिले हैं और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करीब 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, प्रदेश में 9.50 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हुई हैं और 65 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है।

सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन पर भी दिया जोर

मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्विकास और प्रयागराज महाकुंभ जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। उन्होंने एक जिला-एक उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 'विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश में 110 मार्गों पर शुरू होगी ड्रोन से डाक और पार्सल की डिलीवरी

36 मार्गों पर ड्रोन सेवा शुरू, राष्ट्रीय डाक सप्ताह में तकनीक और नवाचार पर रहेगा विशेष जोर

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में डाक और पार्सल पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में जल्द ही 110 मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से डाक वितरण शुरू करने की योजना है। फिलहाल 36 मार्गों पर यह सेवा शुरू हो चुकी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने विश्व डाक दिवस के अवसर पर यह जानकारी दी।



उन्होंने बताया कि ड्रोन डिलीवरी से दुर्गम गांवों तक डाक पहुंचाने में लगने वाला समय कम होगा और सेवा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधार शाखा डाकघर तक 13 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की ड्रोन से डिलीवरी कर इस पहल की शुरुआत की गई थी।

हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में नौ से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम 'एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं' रखी गई है। इसका उद्देश्य आम लोगों और व्यवसायों के जीवन में डाक विभाग की भूमिका तथा सामाजिक और आर्थिक योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सप्ताह के दौरान तकनीक, नवाचार और नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रतिदिन होंगे विविध कार्यक्रम : राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत नौ अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाकघरों में बैनर, डिजिटल डिस्प्ले और वीडियो के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। 12 अक्टूबर को 'फन विद फिलैटली दिवस' पर विद्यार्थियों के लिए डाक टिकट प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, संग्रहालय भ्रमण और पत्र लेखन जैसी गतिविधियां होंगी।

13 अक्टूबर को वित्तीय समावेशन दिवस के तहत डाक चौपालों में बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 14 अक्टूबर को डाक एवं पार्सल दिवस पर बड़े ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के साथ बैठकें होंगी। 15 अक्टूबर को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दिवस पर तकनीकी प्रश्नोत्तरी और ड्रोन डिलीवरी पहल से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

प्रदेश में 2,797 डाकघरों का नेटवर्क : 30 सितंबर 2026 तक हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल में 18 प्रधान डाकघर, 452 उप डाकघर और 2,327 शाखा डाकघर हैं। इनमें से 2,684 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इस विशाल नेटवर्क के संचालन में 2,485 विभागीय कर्मचारी और 6,473 ग्रामीण डाक सेवक जुटे हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 7,08,7142 सक्रिय डाकघर बचत बैंक खातों के अलावा 7,94,403 नए खाते खोले गए। डाक जीवन बीमा के तहत 41,943 नई पॉलिसियां जारी की गईं, जिनकी कुल बीमा राशि 1,730.65 करोड़ रुपये है। इस अवधि में 20.69 लाख डाक वस्तुओं से 12.18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 50 प्रतिशत अधिक है। डाक विभाग ने आधार सेवाओं के तहत 2,00,197 नामांकन और अद्यतन किए, जबकि डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों ने 25,632 आवेदनों का प्रसंस्करण किया। प्रदेश में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 8.80 लाख खाते हैं। डाक परिमंडल मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के साथ ई-कॉमर्स पार्सल वितरण, आधुनिक डाकघरों और राज्य सरकार के विभागों के साथ साझेदारी पर काम कर रहा है।

मुकेश अग्निहोत्री ने सादगी से मनाया जन्मदिन

अमित शाह सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, हरोली। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। इस अवसर पर ऊना जिले के गोंदपुर बुल्ला स्थित सामुदायिक पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक उन्हें बधाई देने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। दिनभर उन्हें शुभकामनाएं देने वालों का सिलसिला जारी रहा।



◆ गौसेवा से दिन की शुरुआत, रक्तदान शिविर आयोजित मुख्यमंत्री सुक्खू और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं

मुकेश अग्निहोत्री ने अपने जन्मदिन की शुरुआत जखेवाल स्थित सिद्ध बाबा बालकनाथ गौशाला में गौसेवा के साथ की। उन्होंने गौमाता को चारा खिलाया और संत बाबा ढांगू वाले अनूप जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सेवा और आस्था से जुड़े भाव के साथ दिन की शुरुआत की।

युवाओं ने लगाया रक्तदान शिविर : जन्मदिन के अवसर पर गोंदपुर बुल्ला के सामुदायिक पार्क में स्थानीय युवाओं की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सेवा से जुड़े ऐसे प्रयास समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। रक्तदान जैसे कार्य जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ लोगों में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करते हैं।

अमित शाह और मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी बधाई : मुकेश अग्निहोत्री को जन्मदिन पर देशभर से शुभकामना संदेश मिले। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने फोन कर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, विभिन्न राज्यों के राजनीतिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों ने भी फोन कॉल और सामाजिक माध्यमों के जरिए शुभकामना संदेश भेजे। क्षेत्र में लोगों की मौजूदगी और बधाई देने के लिए पहुंचने का सिलसिला दिनभर बना रहा।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जन्मदिन पर मिले स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों के इस अपनत्व को अपने लिए विशेष बताया।

हिमाचल में 80 शिक्षा अधिकारियों को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का दिया गया प्रशिक्षण

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पीएम श्री योजना के तहत प्री-प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) के लिए पांच दिवसीय राज्य स्तरीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छह जिलों के लगभग 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।



◆ छह जिलों के 80 अधिकारियों को खेल आधारित शिक्षण और बाल विकास का प्रशिक्षण दिया गया

कार्यक्रम में प्री-प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए रुचिकर और गतिविधि आधारित शिक्षण वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधारभूत चरण से जुड़े प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। खेल, कहानी, कविता, गीत, चित्र और बातचीत के माध्यम से बच्चों को सिखाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। इन गतिविधियों से बच्चों की भाषा, संख्या ज्ञान, तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित करने पर बल दिया गया।

हिमाचल के स्थानीय परिवेश को शिक्षा से जोड़ने के लिए 'हिमवाटिका' की भूमिका पर चर्चा की गई। इसके माध्यम से स्थानीय पौधों, मौसम और प्रकृति से जुड़े अनुभवों को शिक्षण का हिस्सा बनाने की जानकारी दी गई। वहीं, 'जादुई पिटारा' के तहत खिलौनों, पहेलियों और चित्रों जैसी सामग्री से सीखने को रोचक बनाने के तरीके बताए गए।

रामपुर में एचआरटीसी बस हादसे से 20 वर्षीय युवक की मौत, 24 घायल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एचआरटीसी की बस सड़क से नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना रामपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायशरण के पास सुबह करीब आठ बजे हुई। बस में चालक और परिचालक सहित कुल 25 लोग सवार थे।



पुलिस के अनुसार, बस सनेई से रामपुर जा रही थी। दुर्घटनाग्रस्त बस का नंबर एचपी 06ए-5159 है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने एक यात्री की मौत की पुष्टि की है। मृतक की पहचान वंश (20), पुत्र सुरेन्द्र सुरजन, निवासी कराली गांव, डाकघर डंसा, तहसील रामपुर के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद उसे खनेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घायलों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बस चालक व परिचालक भी शामिल हैं। अधिकांश घायल रामपुर के डंसा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ लोग भी घायलों में शामिल हैं। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और बस सड़क से नीचे कैसे गिरी, इसका पता जांच के बाद चलेगा।

28 फरवरी तक 3,000 हेक्टेयर में एचपी शिवा परियोजना पूरी करने के जगत सिंह नेगी ने दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने एचपी शिवा परियोजना के प्रथम चरण के तहत 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी गतिविधियां 28 फरवरी, 2027 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा तक कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को शिमला में सात जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।



◆ प्रथम चरण के 1,900 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा, शेष कार्य समयसीमा में करने के निर्देश

एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित यह परियोजना बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण के लिए निर्धारित 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 2,700 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जबकि 1,900 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा हो गया है। शेष क्षेत्र में जनवरी-फरवरी, 2027 तक पौधारोपण करने का लक्ष्य है। यहां मुख्य रूप से आलूबुखारा और पर्सिमन जैसी शीतकालीन फसलों के पौधे लगाए जाएंगे।

परियोजना के तहत 331 क्लस्टर तैयार किए गए हैं, जिनसे लगभग 10,646 किसान परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को सभी क्लस्टरों का काम पूरा कर उन्हें किसानों को सौंपने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि परियोजना के दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण जारी है। लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की जा चुकी है और 2,153 हेक्टेयर में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। करीब 1,500 हेक्टेयर क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए एशियाई विकास बैंक को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के बाद अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से निविदा प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। बागवानी मंत्री ने पौधों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में निम्न गुणवत्ता वाले पौधे नहीं खरीदे जाएं।

हर्षवर्धन चौहान 11-12 अक्टूबर को सिरमौर दौरे पर रहेंगे

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान 11 और 12 अक्टूबर को सिरमौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उद्योग मंत्री 11 अक्टूबर को सुबह लाणी बोराड और खलांडो में जनसमस्याएं सुनेंगे। इसके बाद वह शिलाई पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्याओं और मांगों से रूबरू होंगे। प्रवक्ता के अनुसार, मंत्री 12 अक्टूबर को भी शिलाई में रहेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इस दौरान क्षेत्रवासियों को अपनी शिकायतें और समस्याएं उनके समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। मंत्री के इस प्रवास के दौरान स्थानीय मुद्दों और जनसमस्याओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।

सिकंदर कुमार ने प्रवासियों से विकसित भारत में मांगा सहयोग

न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों से संवाद, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यसभा सांसद प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेशों में रह रहे भारतीय अपनी प्रतिभा, अनुभव, संसाधनों और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

प्रो. सिकंदर कुमार ने आठ अक्टूबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित संवाद सत्र एवं रात्रिभोज में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम भारत के महावाणिज्य दूत बिनय श्रीकांत प्रधान के आमंत्रण पर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने महावाणिज्य दूत बिनय श्रीकांत प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रवासी समुदाय को एक मंच पर लाने और भारत से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श का अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की।



◆ प्रवासियों से निवेश, नवाचार और ज्ञान के जरिए राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान

सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश के भीतर किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ विदेशों में रह रहे भारतीयों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत की संस्कृति, परंपराओं और उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव देश के विकास को नई गति दे सकते हैं।

उन्होंने पिछले दशक में भारत में हुए बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र और तकनीक से जुड़े बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है।

कार्यक्रम में मौजूद प्रवासी भारतीयों ने भारत की विकास यात्रा की सराहना की और देश की प्रगति में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान दिलाने के लिए वे अपनी बौद्धिक क्षमता, अनुभव और संसाधनों के माध्यम से योगदान देने के लिए तत्पर हैं।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने आपस में विचार साझा किए। रात्रिभोज के साथ संवाद सत्र का समापन हुआ। प्रो. सिकंदर कुमार ने प्रवासी भारतीयों से भारत के विकास में निरंतर भागीदारी निभाने का आह्वान किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

यूएई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर भर्ती, 14 अक्टूबर तक करें पंजीकरण

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी शिमला के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन और फिटर पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती वर्टिव गल्फ एलएलसी के लिए मुंबई की भर्ती एजेंसी एसीएमई एंटरप्राइजेज के माध्यम से होगी। चयनित अभ्यर्थियों को कम से कम दो वर्ष के अनुबंध पर रखा जाएगा। मासिक वेतन 1,100 से 1,300 दिरहम निर्धारित है। नियमानुसार अतिरिक्त कार्य का भुगतान, भोजन या भोजन भत्ता, शर्तों के अनुसार आवास और परिवहन तथा नियोक्ता की ओर से वीजा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष एक माह का सवैतनिक अवकाश और हवाई टिकट के लिए 2,700 दिरहम का वार्षिक भत्ता मिलेगा। आवेदन के लिए इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड में आईटीआई अथवा डिप्लोमा, 20 से 45 वर्ष की आयु और वैध पासपोर्ट आवश्यक है। नए और अनुभवी दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट नहीं होने पर चयन के बाद सात दिन में बनवाना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2026 है। साक्षात्कार 16 और 17 अक्टूबर को होंगे।

वन्यजीव अपराधों की जांच के लिए फील्ड गाइड का विमोचन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। वन्यजीव सप्ताह 2026 के समापन समारोह के अवसर पर वन विभाग की ओर से प्रकाशित पुस्तिका 'फील्ड गाइड—वन एवं वन्यजीव अपराधों की जांच और अभियोजन हेतु एक क्षेत्रीय मार्गदर्शिका' का विमोचन किया गया। यह पुस्तिका वन एवं वन्यजीव अपराधों की पहचान, जांच और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।



पुस्तिका के लेखक डॉ. संजय सूद, भारतीय वन सेवा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं वन बल प्रमुख तथा एन. रविशंकर, भारतीय वन सेवा, उप अरण्यपाल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वन विभाग के अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को वन एवं वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाना है।

इस मार्गदर्शिका में अपराधों की पहचान, जांच के दौरान साक्ष्यों के उचित संकलन, दस्तावेजीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया है। इससे वन कर्मचारियों को मामलों की जांच व्यवस्थित तरीके से करने और अभियोजन की प्रक्रिया में आवश्यक सावधानियां बरतने में सहायता मिलेगी।

वन एवं वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए साक्ष्यों का सही संकलन और उनका उचित दस्तावेजीकरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में प्रक्रियागत कमियों से बचने और कानूनी कार्रवाई को मजबूत बनाने में यह पुस्तिका उपयोगी साबित हो सकती है।

वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में गणमान्य अतिथियों और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इसका विमोचन किया गया। विभाग की यह पहल वन एवं वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू की राजनीतिक गतिविधियों पर राकेश जम्वाल ने उठाए सवाल, सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर मांगा जवाब

हिमाचल के संसाधन कांग्रेस हाईकमान को खुश करने के लिए नहीं : जम्वाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो चुका है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को स्वयं राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में उतरकर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस संगठन अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है या मुख्यमंत्री पर पार्टी हाईकमान को खुश करने का दबाव है।

राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और उनसे विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति तथा जनसमस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन, उनके अनुसार, मुख्यमंत्री सुक्खू बार-बार राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होकर अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारियों से ध्यान भटका रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री और सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिकाओं में अंतर होता है। यदि प्रदेश कांग्रेस का संगठन मजबूत है तो उसे अपने आंदोलनों और राजनीतिक कार्यक्रमों का नेतृत्व स्वयं करना चाहिए। मुख्यमंत्री का हर राजनीतिक मोर्चे पर आगे आना सरकार और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।



सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर उठाए सवाल : भाजपा विधायक ने दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर के कथित इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार भी सीमित संसाधनों की बात करती है। ऐसे में जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया, यात्रा का खर्च किस मद से वहन हुआ और क्या निर्धारित नियमों का पालन किया गया।

जम्वाल ने कहा कि हिमाचल के संसाधन प्रदेश की जनता की अमानत हैं, किसी राजनीतिक दल या उसके हाईकमान की निजी संपत्ति नहीं। यदि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किया गया है तो सरकार को खर्च और नियमों के अनुपालन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का उपयोग जनहित को प्राथमिकता देते हुए होना चाहिए, न कि राजनीतिक हित साधने के लिए।

संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखने की मांग : राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की मर्यादा के साथ अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और संस्थाओं का सम्मान भी बनाए रखना चाहिए। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन संवैधानिक पदों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। असहमति जताते समय मर्यादा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना जरूरी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेकर हाईकमान के सामने सक्रियता साबित करने पर ध्यान देना चाहिए। जम्वाल ने मांग की कि सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों और खर्च का विवरण सार्वजनिक किया जाए। साथ ही, मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए प्रदेश के संसाधनों और संवैधानिक पद की गरिमा को राजनीतिक हितों से ऊपर रखें।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं शशि पाल (48) पुत्र श्री सुन्दर सिंह निबासी गाँव चाम्बी डा0 मढ़ी तहसील धर्मपुर जिला मण्डी (हि.प्र.) घोषणा करता हूं कि मेरे आई. टी. बी. पी. में नौकरी के रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम मधु ठाकुर दर्ज है। जबकि मेरी पत्नी के सभी दस्तावेंजों में मधु कुमारी दर्ज है। अतः मेरी सर्विस रिकार्ड में भी मधु कुमारी दर्ज किया जाए।

Gram Panchyat Lambri
Dev.Block Sujanpur Tihra Distt. Hamirpur(H.P.)

Quotation

(1.) Providing and fixing 3 No Almira. 19mm Ply Board. size 2½×3×1.5 or 4x2½ x 15 With High Qulity mica 710 No. 1 mm . (2.) Providing and fixing 10 No Lib Table 19mm Ply Board. with High Qulity mica 710 No. 1mm. (3.) fixing wall Pannelling with P.V.C 6mm. (4.) P I fixing Pannelling with P.V.C. 8 mm with All accesseries. कुटेशन प्राप्ति 08/10/2026 To 12/10/2026 13/10/2026 को open

Secretary, Gram Panchyat Lambri
Dev. Block Sujanpur Tihra Distt. Hamirpur (H.P.)

उत्तराखंड में हर महीने की नौ तारीख को बजेगा भूकम्प चेतावनी का सायरन

भारतेन्दु संवाददाता,देहरादून। उत्तराखंड में भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली की कार्यक्षमता परखने के लिए शुक्रवार को परीक्षण किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे हुए इस परीक्षण के दौरान राज्य में स्थापित 112 सायरनों पर अलर्ट जारी हुआ। भूदेव मोबाइल ऐप के माध्यम से भी परीक्षण चेतावनी भेजी गई। हालांकि, कुछ स्थानों पर सायरनों के संचालन में तकनीकी खामियां सामने आईं, जिन्हें दूर करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के वैज्ञानिक जुटे हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से हुए परीक्षण की निगरानी सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने की। उन्होंने बताया कि परीक्षण काफी हद तक सफल रहा। सामने आई तकनीकी समस्याओं का आकलन कर उन्हें दूर किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सायरन किसी वास्तविक भूकम्प की चेतावनी के लिए नहीं, बल्कि निर्धारित परीक्षण के तहत बजाए गए थे।

वर्तमान में राज्य में भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली के तहत 169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के निर्देश पर अब प्रत्येक माह की नौ तारीख को सुबह 11 बजे प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। सुमन ने लोगों से भूदेव ऐप का अद्यतन संस्करण रखने और उसे स्थान संबंधी अनुमति देने की अपील की।

चमोली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, तीन लाख 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

अनिल थपलियाल



चमोली। जनपद चमोली में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ क्षेत्र में देर रात से बारिश जारी रही, जबकि हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ धाम और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पहाड़ियां सफेद चादर में लिपटी नजर आईं। सुबह मौसम साफ होने और धूप खिलने के बाद बर्फ से ढकी चोटियां चांदी की तरह चमकती दिखाई दीं।

हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद पूरे क्षेत्र का नजारा मनमोहक हो गया। गुरुद्वारा परिसर और आसपास की ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक गईं। चारों ओर फैली सफेदी और पहाड़ियों पर पड़ती धूप ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता को और निखार दिया। बर्फ से ढकी चोटियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं।

गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से एक दिन पहले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हुई। इसके बावजूद श्रद्धालुओं में दर्शन को लेकर उत्साह बना रहा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक तीन लाख 70 हजार से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं।

हेमकुंड साहिब और औली में बढ़ी ठंड

मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने फिर दस्तक दे दी है। सुबह और देर शाम ठंड बढ़ने के कारण लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। बारिश और बर्फबारी से बदरीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब तथा औली के आसपास के क्षेत्रों की सुंदरता और बढ़ गई है। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदल सकता है।

आनंद बर्द्धन ने केदारनाथ रोपवे परियोजना में तेजी लाने के दिए निर्देश

अनिल थपलियाल



बैठक करते हुए।

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के अंतर्गत उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान केदारनाथ रोपवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने केदारनाथ रोपवे से संबंधित वन स्वीकृति के प्रस्ताव शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। साथ ही, चिह्नित प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का समानांतर रूप से दोबारा सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना की निर्धारित रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक गतिविधि का विस्तृत कार्ययोजना चार्ट तैयार कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन स्थानों पर राजस्व भूमि पर टावरों का निर्माण होना है और वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, वहां टावरों की नींव का काम शुरू किया जाए। इसके अलावा उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण से जुड़े कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने प्रत्येक टावर के निर्माण कार्य के प्रारंभ और पूरा होने की तिथि निर्धारित करते हुए कैलेंडर तैयार करने को कहा। उन्होंने गौरीकुंड और सोनप्रयाग के निकट पार्किंग, जनसुविधाओं तथा आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए उचित योजना बनाने के निर्देश भी दिए। इसके लिए आवश्यक भूमि चिह्नित कर कार्य शुरू करने पर जोर दिया।

धामी ने किया सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ

बाल विज्ञान महोत्सव में जुटे छह जिलों के 240 बाल वैज्ञानिक

अनिल थपलियाल



कुमाऊं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बागेश्वर के मंडलसेरा स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पंचम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय महोत्सव में चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 240 चयनित बाल वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव और संबंधित कार्यक्रमों के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने राज्य की विज्ञान प्रयोगशालाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जोड़ने, सभी विकासखंडों में एक-एक चलित प्रयोगशाला स्थापित करने और प्रदेश के सभी जिलों में विज्ञान एवं नवाचार केंद्र खोलने की दिशा में कार्य करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक से जोड़कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने महोत्सव में शामिल बाल वैज्ञानिकों से संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर दिए। साथ ही विद्यार्थियों को खूब पढ़ने, सवाल पूछने और नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के बाल वैज्ञानिक ही भविष्य में देश के प्रमुख वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता बनेंगे तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

धामी ने कहा कि सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं। इनसे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और नवाचार की भावना विकसित होती है।

विज्ञान शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

उन्होंने विद्यार्थियों से पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालयी शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक को शिक्षा से जोड़ने तथा महिला विकास एवं विज्ञान विषय पर सम्मेलन आयोजित करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि देहरादून में साइंस सिटी और चंपावत में साइंस सेंटर विकसित किया जा रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षिका कविता हरकोटिया और शिक्षकों दीप चंद जोशी, हरिमोहन ऐठाणी तथा ख्याली दत्त को सम्मानित किया गया। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उत्तरकाशी में छूटे पात्र मतदाताओं के पंजीकरण को विशेष अभियान जारी

भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद निर्वाचक नामावली में छूटे पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए जनपद की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को अभियान के दूसरे दिन विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने वर्तमान मतदाता सूची का पुरानी निर्वाचक नामावली से मिलान कर छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान की। साथ ही नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को भी पंजीकरण के लिए जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए।

एसएसपी दून के निर्देशों पर लगातार जारी है दून पुलिस का सत्यापन अभियान

दून पुलिस द्वारा पटेलनगर क्षेत्र मे वृहद स्तर पर चलाया सत्यापन अभियान





एसएसपी, देहरादून

- बाहरी व्यक्तियों के साथ साथ पूर्व में आपराधिक घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तों का किया गया भौतिक सत्यापन

विकास बलूनी

देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र में रह रहे किरायेदारों, बाहरी व्यक्तियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान ब्रह्मपुरी, लोहियानगर, आइएसबीटी और ट्रांसपोर्ट नगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने जांच की। इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

पुलिस टीमों ने अभियान के दौरान करीब 300 किरायेदारों और बाहरी व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया। इसके साथ ही पूर्व में आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहे, मामलों में प्रकाश में आए और जमानत पर चल रहे 15 अभियुक्तों का भी सत्यापन किया गया। पुलिस ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सत्यापन अभियान के दौरान किरायेदारों और घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराने तथा अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर 45 भवन स्वामियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इन भवन स्वामियों पर कुल चार लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की कि वे अपने यहां रहने वाले किरायेदारों और घरेलू सहायकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं तथा निर्धारित नियमों का पालन करें।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मिस उत्तराखंड अंजलि असवाल का सम्मान, कुर्मांचल परिषद ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

विकास बलूनी



मिस उत्तराखंड अंजलि असवाल को सम्मानित करते हुए परिषद के सदस्य।



देहरादून। उत्तराखंड की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने की दिशा में कुर्मांचल परिषद की माजरा शाखा ने मिस उत्तराखंड अंजलि असवाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने अंजलि असवाल को गुलदस्ता भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। सम्मान समारोह का आयोजन छावनी परिषद क्लेमेनटाउन के उपाध्यक्ष एवं गौ सेवा विभाग के राज्य मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह कंडारी के कार्यालय, क्लेमेनटाउन में किया गया। समारोह में कुर्मांचल परिषद, माजरा शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्री गंभीर सिंह रावत, श्रीमती कुंती रावत, प्रेमा तिवारी, हेमा परिहार, राधा भट्ट, तनुजा कन्याल, मनोज सिंह, अनीता, मीना और भावना पांडे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

लेन नंबर दो, माजरा निवासी अंजलि असवाल को मिस उत्तराखंड के रूप में मिली पहचान पर परिषद के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। इस सम्मान समारोह के माध्यम से समाज में उभरती प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाने और युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने आशा व्यक्त की कि अंजलि असवाल भविष्य में भी अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करेंगी तथा उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी।

थराली-वाण मार्ग पर मलबे का कहर

भारतेन्दु संवाददाता, चमोली। जनपद के देवाल विकासखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते थराली-वाण मोटर मार्ग पर भूस्खलन की समस्या गंभीर होती जा रही है। शुक्रवार सुबह गमरी गाड़ नामक स्थान पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पानी का तेज बहाव सड़क पर आ गया, जिससे एक वाहन मलबे में फंस गया। मलबा आने के कारण मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर लगातार भूस्खलन होने के कारण सड़क बार-बार बंद हो रही है। बारिश होते ही पहाड़ी से मलबा और पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे आवागमन ठप हो जाता है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। थराली-वाण मोटर मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, लेकिन लगातार सामने आ रही इस समस्या का अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

रेशम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का जायजा लेने पहुंचे यूपी के निदेशक



अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय के निदेशक आनंद कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहसपुर स्थित क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र का तकनीकी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा रेशम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का जायजा लिया।

भ्रमण के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के सहयोग से विकसित आदर्श एवं किफायती रेशम कीटपालन गृह आकर्षण का केंद्र रहा। केंद्र प्रभारी डॉ. पवन सैनी ने बताया कि इसमें लगभग 100 डीएफएल क्षमता के रेशमकीट पालन की व्यवस्था है। यहां शरद ऋतु में पालन का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है।

निदेशक को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शहतूत वृक्षारोपण की परियोजना की जानकारी दी गई। यह पहल रुड़की, नजीबाबाद और सितारगंज-खटीमा के राजमार्ग खंडों पर संचालित की जा रही है। इसके अलावा कृषि आधारित शहतूत वृक्षारोपण मॉडल के बारे में बताया गया, जिसमें शहतूत के पौधों की कतारों के बीच उपयुक्त फसलों की खेती की जा सकती है। इससे किसानों को रेशम उत्पादन के साथ अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं।

श्री शुक्ला ने केंद्र परिसर स्थित रेशम संग्रहालय का भी अवलोकन किया और विकसित तकनीकों की सराहना की। भ्रमण का उद्देश्य वैज्ञानिक रेशम उत्पादन तकनीकों का प्रसार तथा अनुसंधान संस्थानों और संबंधित विभागों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना रहा।

कितना कारगर रहा 'ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025'?

नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प, लेकिन धरातल पर कितनी बदली तस्वीर?

विकास बलूनी



एआई निर्मित चित्र।

- कार्रवाई के आंकड़े या बदलाव के प्रमाण?
- स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचा जागरूकता अभियान?
- नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है?
- नशामुक्ति के लिए जवाबदेही भी जरूरी
- देवभूमि को नशामुक्त बनाने के लिए संकल्प से आगे बढ़ना होगा

देहरादून। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह वह प्रदेश है, जहां की पहचान आध्यात्मिक परंपराओं, देवस्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत जीवनशैली से जुड़ी रही है। लेकिन जब इसी देवभूमि की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने की आशंका से जूझती है, तो सवाल केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य का भी बन जाता है। इसी चुनौती से निपटने के उद्देश्य से शुरू किए गए 'ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025' के सामने आज सबसे बड़ा सवाल है—इस अभियान से धरातल पर कितना बदलाव आया?

सरकार का उद्देश्य नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना और युवाओं को नशे से दूर रखना है। लेकिन किसी भी अभियान की सफलता केवल उसके शुभारंभ, बैठकों, छापेमारी या गिरफ्तारियों की संख्या से तय नहीं होती। असली कसौटी यह है कि क्या नशे की उपलब्धता घटी? क्या युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए प्रभावी उपचार मिला? क्या स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता बढ़ी? और क्या नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर स्थायी चोट पहुंची?

कार्रवाई के आंकड़े या बदलाव के प्रमाण?अक्सर नशे के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आती हैं। पुलिस नशीले पदार्थों की बरामदगी करती है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और अभियान की उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। ये कदम जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे नशे की समस्या की जड़ तक पहुंचा जा रहा है?

यदि एक तस्कर गिरफ्तार होता है और उसकी जगह दूसरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, तो केवल गिरफ्तारियों से समस्या समाप्त नहीं होगी। जरूरत उस पूरी आपूर्ति-श्रृंखला पर प्रभावी कार्रवाई की है, जिसके माध्यम से नशीले पदार्थ युवाओं तक पहुंचते हैं। साथ ही, यह भी देखना होगा कि कार्रवाई के बाद संबंधित मामलों में जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ी।

मिशन की वास्तविक उपलब्धियों का आकलन करने के लिए वर्ष 2025 के निर्धारित लक्ष्यों, उनके मुकाबले हासिल परिणामों और वर्तमान स्थिति के तुलनात्मक आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। बिना ठोस आंकड़ों के न तो अभियान को पूरी तरह सफल कहा जा सकता है और न ही विफल।

स्कूल-कॉलेजों तक पहुंचा जागरूकता अभियान? नशे की समस्या से लड़ाई केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नशे के दुष्परिणामों को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए? क्या युवाओं को मानसिक दबाव, बेरोजगारी, संगति और अन्य सामाजिक परिस्थितियों से निपटने के लिए उचित मार्गदर्शन मिल रहा है? क्या अभिभावकों को समय रहते नशे के संकेत पहचानने की जानकारी दी जा रही है?

जागरूकता अभियान केवल औपचारिक कार्यक्रम बनकर नहीं रहना चाहिए। उसे युवाओं के जीवन से जोड़ना होगा। खेल, कौशल विकास, रोजगारपरक प्रशिक्षण, परामर्श और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियां भी इस लड़ाई का हिस्सा बननी चाहिए। नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है?

नशे की समस्या का एक पहलू तस्करी है, तो दूसरा पहलू नशे की लत से जूझ रहे लोगों का उपचार और पुनर्वास। नशे की लत से पीड़ित हर व्यक्ति को केवल अपराधी की नजर से देखना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जहां अपराध और तस्करी के मामलों में कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई जरूरी है, वहीं नशे की निर्भरता से जूझ रहे लोगों को चिकित्सकीय सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और समाज में दोबारा स्थापित होने का अवसर भी मिलना चाहिए।

नशामुक्ति के लिए जवाबदेही भी जरूरी

'ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025' को लेकर सरकार और संबंधित विभागों को अब उपलब्धियों के साथ चुनौतियों का भी स्पष्ट विवरण देना चाहिए। क्या निर्धारित लक्ष्य पूरे हुए? किन जिलों में नशे की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ?

देवभूमि को नशामुक्त बनाने के लिए संकल्प से आगे बढ़ना होगा

उत्तराखंड को नशामुक्त बनाना केवल एक सरकारी मिशन नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इस लड़ाई में पुलिस की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, परिवार और समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सवाल सरकार की मंशा पर टिप्पणी करने का नहीं, बल्कि मिशन के परिणामों को प्रमाणों के आधार पर परखने का है। यदि अभियान ने सकारात्मक बदलाव किए हैं, तो उनके आंकड़े जनता के सामने आने चाहिए। यदि कमियां रह गई हैं, तो उनकी पहचान कर सुधार की समयबद्ध योजना बनाई जानी चाहिए।

अब वक्त है कि 'ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन-2025' की उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन हो और प्रदेश की जनता को बताया जाए—लक्ष्य क्या थे, हासिल क्या हुआ और आगे की राह क्या है?

क्योंकि देवभूमि को नशामुक्त बनाने का संकल्प तभी सार्थक होगा, जब उसका असर सरकारी विज्ञप्तियों से आगे बढ़कर युवाओं, परिवारों और समाज के जीवन में दिखाई देगा।

हरकीदून और केदारकांठा ट्रैक को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम तेज

अनिल थपलियाल

उत्तरकाशी। वन्यजीव सप्ताह के तहत हरकीदून और केदारकांठा ट्रैक को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। वेस्ट वॉरियर्स संस्था और गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान के दौरान ट्रैकिंग मार्गों से प्लास्टिक और अन्य कचरा एकत्र किया गया। अभियान के माध्यम से पर्यटकों, स्थानीय लोगों और ट्रैकिंग एजेंसियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया।

हरकीदून और केदारकांठा जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर हर वर्ष सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद प्लास्टिक कचरे की समस्या बनी हुई है। सांकरी, तालुका और सौड़ सहित प्रमुख आधार शिविरों तथा ट्रैकिंग मार्गों पर कचरा फैलने से प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसे देखते हुए अभियान में स्थानीय समुदाय की भागीदारी पर भी जोर दिया गया।

वेस्ट वॉरियर्स के आउटरीच प्रबंधक वीरपाल नेगी ने बताया कि संस्था पिछले पांच वर्षों से ट्रैकिंग मार्गों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। वहीं, पार्क की उपनिदेशक निधि सेमवाल ने पर्यटकों और ट्रैकिंग एजेंसियों से अपील की कि वे मार्गों पर कचरा न फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हिमालयी पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी की जिम्मेदारी जरूरी है।

एलपीयू हंगामे के बाद इंटरनेट मीडिया पर झूठी खबरों को लेकर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर



इंटरनेट मीडिया पर किसी ऐसी घटना की झूठी सूचना फैलाना, जो वास्तव में हुई ही न हो, गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हुई हिंसा के संदर्भ में यह चिंता जताते हुए सवाल किया कि ऐसी पोस्ट से हिंसा और जान-माल का नुकसान होने पर क्या केवल पोस्ट डालने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त है या संबंधित इंटरनेट मीडिया मंच की जवाबदेही भी निर्धारित होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मामले की जानकारी मिलने के बाद कहा कि जांच केवल पोस्ट साझा करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि सूचना कहां से आई और इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लोगों को अपनी राय रखने और आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन जानबूझकर ऐसी झूठी सूचना फैलाना, जिसका उद्देश्य लोगों की भावनाएं भड़काना और अशांति पैदा करना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान नहीं माना जा सकता।

अदालत ने एलपीयू और चितकारा में लगातार दो दिनों में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। चितकारा में 25 सितंबर को छात्राओं की आत्महत्या की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ था। इसके अगले दिन एलपीयू में एक पुरुष कर्मचारी द्वारा छात्रा से दुष्कर्म किए जाने की कथित झूठी सूचना इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई, जिसके बाद परिसर में तनाव और हिंसा की स्थिति बनी। इन घटनाओं के बीच संबंध होने के दावे की भी जांच की जा रही है।

सीबीआई जांच के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर टली सुनवाई

जस्टिस शील नागू के सुनवाई से हटने के बाद मुख्य न्यायाधीश नई पीठ को सौंपेंगे मामला

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में नई पीठ के समक्ष अपनी याचिका पर सुनवाई का इंतजार करना होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शील नागू ने खुद को मामले से अलग कर लिया। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर यह मामला दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

शुक्रवार को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि जस्टिस नागू इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते और इसे मुख्य न्यायाधीश दूसरी पीठ को सौंपेंगे। जस्टिस नागू पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे।

पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने बताया कि जस्टिस नागू ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए जनहित याचिकाकर्ता की कुछ याचिकाओं को खारिज करने के आदेश दिए थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी मौजूदा याचिका में उन आदेशों पर निर्भर नहीं है। इसके बावजूद जस्टिस नागू ने सुनवाई से अलग होने का निर्णय लिया। जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि मौजूदा समय काफी कठिन है और यह पता नहीं होता कि हमला कहां से हो सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 17 अन्य पीठ भी हैं।

यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पीठ ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। यह आदेश अधिवक्ता निखिल सराफ की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जानकारी और पत्राचार भेजे जाने के बावजूद पंजाब पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने नितिन गोहल नामक व्यक्ति से जुड़े आरोपों की ओर ध्यान दिलाया था। आरोप है कि वह पंजाब सरकार से विभिन्न लाभ हासिल करने के इच्छुक लोगों और संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। मामले में तबादले करवाने, गोपनीय सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच दिलाने और हथियार लाइसेंस हासिल कराने जैसी गतिविधियों के आरोप भी शामिल हैं। इन आरोपों की जांच होनी बाकी है और इन्हें अभी सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सरकार का तर्क है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66(2) के तहत ईडी से मिली जानकारी पर पुलिस को तभी कार्रवाई करनी चाहिए, जब उससे संज्ञेय अपराध का खुलासा होता हो। सरकार ने यह भी दलील दी है कि हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के विजय मदनलाल चौधरी मामले में दिए गए फैसले के अनुरूप नहीं है।

पंजाब सरकार ने मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। अब जस्टिस नागू के सुनवाई से अलग होने के बाद याचिका पर आगे की कार्यवाही नई पीठ के समक्ष होगी।

न्यूज ब्रीफ

पंजाब के स्कूलों में 31 अक्टूबर तक नया मिड-डे मील मेन्यू लागू

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन का नया साप्ताहिक मेन्यू जारी किया गया है। यह मेन्यू 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी) ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को कतार में बैठाकर भोजन प्रभारी की देखरेख में निर्धारित मेन्यू के अनुसार खाना परोसा जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे। नए मेन्यू के अनुसार सोमवार को माह-चने की दाल और रोटी, मंगलवार को राजमा-चावल और खीर, बुधवार को आलू मिले काले या सफेद चने के साथ पूरी अथवा रोटी, गुरुवार को कढ़ी-चावल और शुक्रवार को मौसमी सब्जी-रोटी दी जाएगी। शनिवार को साबुत माह की दाल, चावल और मौसमी फल परोसे जाएंगे। सप्ताह में एक दिन मीठे में खीर भी दी जाएगी। इसके अलावा 'तिथि भोजन' के तहत सरपंचों और दानदाताओं के सहयोग से विशेष अवसरों पर फल, मिठाई या अन्य पकवान देने के प्रयास किए जाएंगे।

जालंधर में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में एसएफजे के दो कथित सदस्य गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर जालंधर स्थित रेडक्रॉस भवन की बाहरी दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने का आरोप है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह के अनुसार, आरोपियों की पहचान गांव निहालुवाल निवासी सुखप्रीत सिंह और राजदीप सिंह के रूप में हुई है। 29 सितंबर को रेडक्रॉस भवन की दीवार पर नारे लिखे मिले थे। इसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने घटना से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने होशियारपुर के चब्बेवाल के निकट बरियां कलां गांव में डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा से तोड़फोड़ करने की बात भी स्वीकार की है। यह घटना 14 और 15 सितंबर की मध्यरात्रि की बताई गई है। इस संबंध में चब्बेवाल थाने में मामला दर्ज है।

जालंधर में जल परियोजना की बढ़ी समयसीमा सड़कें दोबारा खोदने की आशंका

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। जालंधर में चल रहे सरफेस वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लेकर नगर निगम कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आदमपुर में निर्माणाधीन 275 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र का दौरा कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित एजेंसी को 31 दिसंबर 2026 तक परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड को विभिन्न विभागों के बीच लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सहित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम में तेजी लाने की हिदायत दी गई। परियोजना की समयसीमा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है, जबकि अभी कई किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम बाकी बताया जा रहा है।

विदेश भेजने का झांसा देकर परिवार से ठगे 17 लाख

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर में विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि फर्जी ट्रैवल एजेंटों ने एक युवक को विदेश भेजने का सपना दिखाकर उसके परिवार से 17 लाख रुपये ऐंठ लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अमनदीप सिंह और गुरविंदर कौर के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता राज कुमार खुरमी के अनुसार, आरोपितों ने उनके बेटे तेजिंदर सिंह को वैध वीजा और कार्य अनुमति दिलवाकर विदेश भेजने का भरोसा दिया था। आरोपितों के वादों पर विश्वास करते हुए परिवार ने बेटे के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद में अलग-अलग किस्तों और माध्यमों से कुल 17 लाख रुपये उन्हें सौंप दिए। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद भी आरोपितों ने न तो तेजिंदर सिंह का वीजा लगवाया और न ही उसे विदेश भेजने की व्यवस्था की।

चंडीगढ़ निगम रिश्वत मामले में ज्वाइंट कमिश्नर समेत कई अधिकारियों की भूमिका जांच के घेरे में

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



चंडीगढ़ नगर निगम में 14 लाख रुपये की कथित रिश्वत के मामले में जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी और टिप्पर उपलब्ध कराने का काम करने वाले ठेकेदार प्रशांत भदौरिया ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को दी शिकायत में सैनिटरी इंस्पेक्टर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर पीसीएस बलबीर राज सिंह तक पर आरोप लगाए हैं। सीबीआइ अब शिकायत में नामजद अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

ठेकेदार के अनुसार, उसके बिलों का भुगतान करवाने के नाम पर सैनिटरी इंस्पेक्टर शक्ति शर्मा ने 14 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोप है कि शक्ति शर्मा ने रकम ऊपर तक पहुंचाने की बात कही थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि जब उसने इस बारे में ज्वाइंट कमिश्नर बलबीर राज सिंह से शिकायत की तो उन्होंने भी कथित तौर पर रिश्वत देने की बात कही और भुगतान रुकने तथा टेंडर रद होने की आशंका जताई।

भदौरिया ने अपनी शिकायत में एक अन्य सैनिटरी इंस्पेक्टर नितिन, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कुलबीर, एसएएस अकाउंट्स अधिकारी संदीप सेठी और ज्वाइंट कमिश्नर बलबीर राज सिंह का नाम भी लिया है। शिकायतकर्ता के आरोपों के मुताबिक, कथित रिश्वत की रकम इन अधिकारियों के बीच बांटी जानी थी। सीबीआइ इन आरोपों की जांच कर रही है।

सीबीआइ ने बुधवार को सेक्टर-11 की मार्केट में कार के अंदर ठेकेदार से पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सैनिटरी इंस्पेक्टर शक्ति शर्मा को गिरफ्तार किया था। वीरवार को उसे सीबीआइ की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

शिकायत के अनुसार, ठेकेदार की फर्म को नगर निगम ने लैंडफिलिंग साइट पर जेसीबी और टिप्पर उपलब्ध कराने का तीन साल का टेंडर दिया था। ठेकेदार का आरोप है कि शक्ति शर्मा जुलाई 2025 से हर महीने एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था और भुगतान में भी बाधा डाली जा रही थी।

चार साल बाद पंजाब को मिलेगा स्थायी डीजीपी, गौरव यादव के नाम पर मुहर

मुख्यमंत्री भगवंत मान की मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज, हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब पुलिस को करीब चार साल बाद स्थायी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिलने जा रहा है। 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी गौरव यादव को राज्य का नियमित डीजीपी नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया गया है। औपचारिक आदेश जारी होने के साथ ही वह नियमित डीजीपी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले हो रही है।

गौरव यादव जुलाई 2022 से पंजाब पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस दौरान स्थायी डीजीपी की नियुक्ति का मामला लंबे समय तक लंबित रहा। नियमित नियुक्ति के लिए पंजाब सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 14 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे थे। आयोग ने विचार-विमर्श के बाद तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। इसमें गौरव यादव के अलावा शरद सत्य चौहान और हरप्रीत सिंह सिद्धू के नाम शामिल थे। तीनों अधिकारी 1992 बैच के हैं।

शरद सत्य चौहान वर्तमान में पंजाब में सतर्कता प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 31 मार्च 2028 को निर्धारित है। वहीं, हरप्रीत सिंह सिद्धू विशेष पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। वह 31 मई 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। पैनल में शामिल इन अधिकारियों में से गौरव यादव के नाम पर सरकार ने सहमति जताई है।

स्थायी डीजीपी की नियुक्ति में देरी का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचा था। अधिवक्ता निखिल थमन की ओर से दायर जनहित याचिका में लंबे समय तक कार्यवाहक डीजीपी के जरिए पुलिस विभाग चलाने पर सवाल उठाए गए थे। यूपीएससी से पैनल मिलने के बाद भी नियुक्ति का निर्णय लंबित रहने पर मामला चर्चा में रहा।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 13 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा दी है। ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया को इस समयसीमा से पहले पूरा करने की संभावना जताई जा रही है। औपचारिक आदेश जारी होने के बाद पंजाब पुलिस को नियमित प्रमुख मिल जाएगा और जुलाई 2022 से चली आ रही कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

महंगाई भत्ते के बकाये पर पंजाब सरकार के दोहरे रवैये से हाई कोर्ट नाराज, मुख्य सचिव तलब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के बकाये से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की खामियां दूर नहीं करने और न्यायालय को गलत जानकारी दिए जाने पर नाराजगी जताई। शुक्रवार को पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा अदालत में पेश हुए। मुख्य सचिव की ओर से बिना शर्त माफी मांगे जाने के बावजूद अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक अवमानना के मामले पर सुनवाई निर्धारित रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ करेगी। मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।

कर्मचारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कौशल ने अदालत में दलील दी कि महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इसके विपरीत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार ने तत्काल अपील दायर की और उस पर सुनवाई भी निर्धारित हो गई। इस अंतर को लेकर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

संजय कौशल ने कहा कि लाखों सरकारी कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते के बकाये का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। वहीं, ईडी से जुड़े मामले में कुछ अधिकारियों को राहत दिलाने के लिए सरकार ने तेजी दिखाई। उन्होंने इस स्थिति को सरकार का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि इससे उसकी प्राथमिकताओं और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं।

पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का बकाया मौजूदा सरकार के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पिछली सरकारों के समय का है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में फैसला सुनाने से पहले अदालत पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण कर चुकी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है। सरकार को ऐसा करने से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन अपील दायर करने के बाद अदालत के समक्ष गलत जानकारी प्रस्तुत करना स्वीकार्य नहीं है।

हाई कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की खामियों को अब तक दूर नहीं किया। अदालत ने कहा कि मामले में अपनाई गई प्रक्रिया और दी गई जानकारी पर गंभीर सवाल हैं। इसी संदर्भ में अवमानना का नोटिस जारी किया गया था।

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से विकास सिंह ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि, अदालत ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर आगे का निर्णय संबंधित पीठ पर छोड़ दिया।

कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से 15 अक्टूबर से महंगी होंगी साइकिलें

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। साइकिल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उद्योग पर लागत का दबाव बढ़ गया है। स्टील के दाम पिछले एक महीने में करीब 7,000 रुपये प्रति टन बढ़ गए हैं। इसके अलावा प्लास्टिक दाना, कागज, तेल, पेंट, रसायन और अन्य जरूरी पुर्जों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके चलते साइकिल निर्माताओं ने 15 अक्टूबर से कीमतों में प्रति साइकिल 160 रुपये तक बढ़ोतरी करने की तैयारी की है।



◆ स्टील के दाम एक महीने में सात हजार रुपए प्रति टन बढ़े निर्माताओं ने लिया कीमतों में संशोधन का फैसला

इस संबंध में जी-13 एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से उद्योग के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। कारोबारियों ने कहा कि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री महंगी होने से लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा कीमतों पर साइकिलों की आपूर्ति जारी रखना निर्माताओं के लिए मुश्किल होता जा रहा है।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला प्रत्येक निर्माता अपनी उत्पादन लागत, बाजार की मांग और कारोबारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से करेगा। 160 रुपये तक की प्रस्तावित वृद्धि सभी साइकिलों पर समान रूप से लागू होना जरूरी नहीं है। कंपनियां अपने उत्पादों के अनुसार कीमतें निर्धारित करेंगी।

बैठक का उद्देश्य कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा करना और अच्छी गुणवत्ता वाली साइकिलों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार करना था। बैठक के दौरान एसोसिएशन की ओर से सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए।

पंजाब कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व से चुनावी जीत की तैयारी

मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला सामूहिक नेतृत्व से होगा, सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलेगी कांग्रेस

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने स्पष्ट किया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के दिशा-निर्देश में लड़ेगी। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उन्होंने सामूहिक नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं, जिनमें मुख्यमंत्री बनने की क्षमता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधायक सुखपाल सिंह खैहरा का नाम लेते हुए खुद को भी इस दौड़ में शामिल बताया।

परगट सिंह ने हालांकि किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के बजाय सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के कई नेता उनसे अधिक अनुभवी हैं और पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। इनमें से अधिकतर नेता पिछले 40 से 45 वर्षों से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, जबकि उनके पास करीब 10 से 12 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में उनका प्रयास सभी नेताओं के अनुभव और क्षमता का इस्तेमाल कर पार्टी को मजबूत करना होगा।

पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी और नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव की चर्चाओं पर परगट सिंह ने कहा कि पार्टी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव के दौरान सभी नेताओं की भूमिका उनकी क्षमता और अनुभव के अनुसार तय की जाएगी। पार्टी किसी एक चेहरे पर निर्भर रहने के बजाय सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रत्येक नेता को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। पार्टी का लक्ष्य सभी नेताओं को साथ लेकर चलना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। उनके अनुसार, चुनावी सफलता के लिए आपसी तालमेल और सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।

हॉकी के मैदान से राजनीति में आए परगट सिंह ने अपनी रणनीति को खेल से जोड़कर समझाया। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी वह स्ट्राइकर की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर फुल बैक की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। उन्होंने बाकी नेताओं से भी मैदान में उतरकर अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

परगट सिंह ने कहा कि टीम तभी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जब सभी खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी समझें और सामूहिक लक्ष्य के लिए काम करें। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद परगट सिंह पार्टी को एकजुट करने और चुनावी तैयारियों को गति देने में जुटे हैं। आठ अक्टूबर को पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के साथ उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेककर अपनी आगे की राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की।

इसके बाद पार्टी की ओर से विभिन्न जिलों में दौरे और चंडीगढ़ में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। परगट सिंह को उम्मीद है कि राहुल गांधी के दिशा-निर्देश, वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी।

लुधियाना में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 15 गिरफ्तार और 26 लोगों का पुनर्वास

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना



लुधियाना को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने तस्करों और नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने पिछले 24 घंटों में मादक पदार्थ निषेध अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत 14 मामले दर्ज कर 15 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। विभिन्न इलाकों में तलाशी और छापेमारी के दौरान हेरोइन, गांजा, नशीला पाउडर, गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, आरोपितों के कब्जे से 207.50 ग्राम हेरोइन, 400 ग्राम गांजा, 12.50 ग्राम नशीला पाउडर, 110 नशीली गोलियां और 30 कैप्सूल बरामद हुए हैं। इसके अलावा नशे के सेवन में इस्तेमाल होने वाले सात विशेष लाइटर और सिल्वर फॉयल भी जब्त की गई है।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो प्रमुख सप्लायरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं, चिह्नित सात स्थानीय पेडलरों में से दो को गिरफ्तार किया गया है। चार अन्य संदिग्धों की तकनीकी और वित्तीय जांच जारी है, जबकि एक आरोपित पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद है। पुलिस इनके अंतरराज्यीय नेटवर्क से संबंधों की भी जांच कर रही है।

नशे के खिलाफ अभियान के तहत हैबोवाल और कोचर मार्केट स्थित स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस ने ग्राम रक्षा समितियों और नशामुक्ति मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक कर स्थानीय स्तर पर निगरानी मजबूत करने पर भी चर्चा की।

पुलिस के मुताबिक, नशे की लत से जूझ रहे 23 लोगों को सरकारी ओओएटी केंद्रों में पंजीकृत कराया गया है, जबकि तीन लोगों को नशामुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है और कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे की अवैध बिक्री और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जा रही है। अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

बुरहान वानी को बलिदानी बताने पर पीडीपी नेता अब्दुल कबीर खान के खिलाफ मामला दर्ज

बयान पर भाजपा और नेकां ने जताई कड़ी आपत्ति, पीडीपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी को बलिदानी बताने के मामले में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता अब्दुल कबीर खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया। किश्तवाड़ जिले से संबंधित अब्दुल कबीर खान ने वीरवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में बुरहान वानी को बलिदानी बताया था। उन्होंने कथित तौर पर यह दावा भी किया था कि भाजपा के कुछ नेता बुरहान वानी के घर गए थे। उनके इस बयान के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया है।

पीडीपी नेता के बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर आतंकवाद का महिमामंडन करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस तरह के बयान देकर राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।



भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने पीडीपी नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के परिवारों से माफी मांगने की मांग की। वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने भी अब्दुल कबीर खान के बयान को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई। भाजपा नेताओं का कहना है कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी करते समय जिम्मेदारी बरतनी चाहिए और सुरक्षाबलों के बलिदान का सम्मान किया जाना चाहिए।

विवाद बढ़ने के बाद अब्दुल कबीर खान ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति को बलिदानी कहना या नहीं कहना उनकी निजी राय और स्वतंत्रता का विषय है। हालांकि, उनके बयान को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूछताछ के दौरान उनके बयान तथा उससे जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद ने भी पीडीपी नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे पीडीपी का दोहरा रवैया बताते हुए सवाल उठाया कि बलिदानी की परिभाषा क्या है। उनके अनुसार, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। इस मामले ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और उससे जुड़े राजनीतिक बयानों को लेकर बहस तेज कर दी है।

बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। वह आठ जुलाई 2016 को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। उसकी मौत के बाद घाटी के कई हिस्सों में व्यापक विरोध-प्रदर्शन और हिंसा हुई थी।

कश्मीर में ओलावृष्टि से फसलें और सेब के बाग हुए प्रभावित

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में वीरवार को मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। बांडीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल के विभिन्न क्षेत्रों में धान की फसलों तथा सेब के बागों को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि, अभी तक नुकसान का आधिकारिक आकलन नहीं हुआ है। बांडीपोरा में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हुईं, जबकि कुपवाड़ा में बारिश और ओलों ने धान के खेतों तथा सेब के बागों को नुकसान पहुंचाया। गांदरबल में भी फसलों और बागवानी को क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। श्रीनगर समेत घाटी के अन्य इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लाल चौक, रीगल चौक और पोलो व्यू सहित प्रमुख बाजारों में सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं से तिरपाल उड़ गए और पर्यटकों ने बारिश से बचने के लिए दुकानों तथा शेड का सहारा लिया। मौसम विभाग ने गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है।

कठिन ड्यूटी के लिए एसपीओ को मिलेंगे अतिरिक्त भत्ते

जम्मू-कश्मीर के 32 हजार एसपीओ के वेतन वृद्धि प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की मिली मंजूरी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



जम्मू-कश्मीर में तैनात करीब 32 हजार विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसपीओ का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद वेतन वृद्धि और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए अतिरिक्त भत्तों का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, बढ़े हुए वेतन की राशि और इसे लागू करने की तारीख के बारे में अंतिम आदेश जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

अधिकारियों के अनुसार, एसपीओ के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस विभाग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। सिफारिशों में इस बात पर जोर दिया गया कि एसपीओ सीमित वेतन के बावजूद आतंकवाद विरोधी अभियानों और अन्य पुलिस कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कई कर्मियों की तैनाती दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों और आतंकवाद प्रभावित इलाकों में होती है, जहां ड्यूटी के दौरान उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके वेतन और सुविधाओं में सुधार की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए वेतन बढ़ाने के साथ मुश्किल हालात में काम करने से जुड़े लाभ और अन्य भत्ते देने की सिफारिश की है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत एसपीओ को उनकी सेवा अवधि के आधार पर प्रतिमाह छह हजार से 18 हजार रुपये तक वेतन मिलता है। प्रस्तावित बढ़ोतरी से हजारों कर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन और पुलिस विभाग पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहे थे। अब प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास पहुंचने के बाद संबंधित कर्मियों की नजर अंतिम मंजूरी पर है। इसके साथ ही एसपीओ के कल्याण के लिए अतिरिक्त सुविधाओं और भत्तों पर भी विचार किया जा रहा है। नियमित पुलिस भर्ती में आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपायों को भी उनके हित में उठाए गए कदमों के रूप में देखा जा रहा है।

यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित जम्मू दौरे से पहले सामने आया है। उनके दौरे के दौरान एसपीओ के वेतन संबंधी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर पुलिस के बजट में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पुलिस को 9,925.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 9,097 करोड़ रुपये थी। अब एसपीओ को वेतन वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसके अलावा, प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वेतन वृद्धि और भत्तों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इससे एसपीओ को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों की स्थिति स्पष्ट होगी। दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात इन कर्मियों के लिए आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय के फैसले पर टिकी हैं, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

उमर अब्दुल्ला ने शेख नूरुद्दीन नूरानी के उर्स पर दी शुभकामनाएं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कश्मीर के महान सूफी संत आलमदार-ए-कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी (रह.) के उर्स के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने संत की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि उनकी आध्यात्मिक विरासत आज भी लोगों को शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश देती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी को नंद ऋषि और शेख-उल-आलम के नाम से भी जाना जाता है। उनकी शिक्षाएं कश्मीर की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके विचारों ने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे तथा सद्भाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शेख नूरुद्दीन नूरानी की शिक्षाएं आध्यात्मिकता, करुणा, शांति और मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं। उनका संदेश लोगों को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर मिल-जुलकर रहने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की प्रेरणा देता है। संत की विचारधारा कश्मीर की साझा सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक बनी हुई है।

बीएसएफ के सहायक कमांडेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

भारतेंदु संवाददाता, कुपवाड़ा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक सहायक कमांडेंट बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, सहायक कमांडेंट जिले के डोबन इलाके में बेहोश और अचेत अवस्था में मिले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल अधिकारी की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने और आवश्यक चिकित्सकीय रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

कश्मीर की झीलों में मखाना खेती से किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी शुरू

किसानों को मखाना उत्पादन की तकनीक और विपणन का दिया गया प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



कश्मीर की झीलों और आर्द्रभूमियों में मखाना उत्पादन की संभावनाएं तलाशने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के साथ जलीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इसी कड़ी में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपोरा-1 ने मखाना विकास योजना के तहत पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

बांडीपोरा के पोतुशाई स्थित केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण में बांडीपोरा और बारामूला के किसानों ने भाग लिया। किसानों को मखाना की खेती, फसल प्रबंधन, कटाई, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी दी गई। केंद्र के प्रमुख डॉ. तारिक सुल्तान ने बताया कि कमल और सिंघाड़े जैसी जलीय फसलों के साथ मखाना को भी आजीविका के विकल्प के रूप में विकसित करने की संभावनाएं हैं।

यह पहल राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा के साथ हुए समझौते के बाद शुरू की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कश्मीर के रखस एवं फार्म विभाग के निदेशक अजब सिंह अजीब ने आर्द्रभूमियों के वैज्ञानिक उपयोग और फसल विविधीकरण पर जोर दिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को केंद्र के फार्म में मखाना, कमल और सिंघाड़े के प्रदर्शन प्लॉट भी दिखाए गए। वैज्ञानिकों ने स्थानीय परिस्थितियों में इन फसलों की उपयुक्तता और खेती की तकनीकों पर जानकारी साझा की।

आयुष निदेशालय के 19 चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं अर्ध-स्थायी घोषित

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने आयुष निदेशालय में कार्यरत 19 चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को अर्ध-स्थायी घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में इस संबंध में मंजूरी दी गई है। सरकारी आदेश संख्या 744-जेके (एचएमई) 2026 के तहत यह निर्णय जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है। आदेश में सिविल सेवा विनियमों के खंड-दो की अनुसूची-नौ का भी उल्लेख किया गया है। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों, आम आयुष सुविधाओं और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों पर लागू होगा।

कैग ने जम्मू-कश्मीर की वित्तीय व्यवस्था में गंभीर खामियां कीं उजागर

बजट आवंटन के बिना बने 158 करोड़ रुपए के बिल, वित्तीय प्रणाली में मिलीं गंभीर खामियां

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर में सरकारी धन के आवंटन और भुगतान की निगरानी के लिए बनाई गई एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की कार्यप्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में संबंधित बजट आवंटन के बिना ही 158.29 करोड़ रुपये के बिल तैयार किए गए। रिपोर्ट में वित्तीय रिकॉर्ड में अंतर, डिजिटल बदलावों का अधूरा ब्योरा, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट संख्या तीन, वर्ष 2026, 30 सितंबर को विधानसभा में पेश की गई थी।

कैग के अनुसार, वर्ष 2021-22 में पांच आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 47 योजनाओं के तहत 75.06 करोड़ रुपये के बिल तैयार किए, जबकि संबंधित बजट आवंटन दर्ज नहीं था। वर्ष 2022-23 में छह अधिकारियों ने 51 योजनाओं के तहत 83.23 करोड़ रुपये के बिल बनाए। इस तरह दोनों वर्षों में कुल 158.29 करोड़ रुपये के बिल बिना संबंधित बजट आवंटन के तैयार किए गए। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस पूरी राशि का भुगतान हुआ था या नहीं। लेखापरीक्षा ने इस स्थिति को बजट नियंत्रण और वित्तीय निगरानी की प्रभावशीलता से जुड़ी गंभीर कमी माना।

रिपोर्ट में एक ही बिल की राशि अलग-अलग सरकारी प्रणालियों में दर्ज होने के मामले भी सामने आए। दो बिलों की रकम जम्मू-कश्मीर भुगतान प्रणाली में 17,090 और 25,800 रुपये थी, जबकि कोषागार नेटवर्क प्रणाली में यही राशि 17,190 और 48,512 रुपये दर्ज मिली।

जम्मू-कश्मीर में डेंगू का बढ़ता प्रकोप मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंची

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



जम्मू-कश्मीर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक डेंगू के 1004 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 297 लोगों की जांच की गई, जिनमें 59 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू, डोडा और सांबा जिले डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

पिछले 24 घंटों में जम्मू जिले में सबसे अधिक 29 नए मामले सामने आए, जबकि डोडा में 23 और सांबा में दो मरीज मिले। इसके अलावा रियासी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया। एक मरीज दूसरे प्रदेश से आया है।अब तक जम्मू जिले में डेंगू के 560 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। डोडा में 143 और सांबा में 134 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सांबा में डेंगू से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त कठुआ में 35, उधमपुर में 26, राजौरी में 23, रामबन में 17, रियासी में 13, पुंछ में 10 और किश्तवाड़ में आठ मामले सामने आए हैं। कश्मीर में छह और दूसरे प्रदेशों से आए लोगों में 20 मामले दर्ज किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस वर्ष अब तक 17,736 लोगों की डेंगू जांच की जा चुकी है। वर्ष 2025 में इसी अवधि तक 16,831 लोगों की जांच में 1,483 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इस बार कुल मामले पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं, लेकिन कुछ जिलों में स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

गांदरबल में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए श्रीनगर के लड़के रायिल के पास मिले

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

खराब मौसम बना रास्ता भटकने की वजह



मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में ट्रेकिंग के दौरान लापता हुए श्रीनगर के दो युवकों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। खराब मौसम और अंधेरा होने के कारण दोनों जंगल में रास्ता भटक गए थे। उन्होंने मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने तलाश अभियान शुरू किया। हालांकि, अभियान के दौरान ही दोनों युवक खुद रायिल गांव पहुंचने में सफल रहे।

अधिकारियों के अनुसार, परिमपोरा श्रीनगर निवासी उजैर किरमानी (19), पुत्र गौहर सैयद और मलबाग निवासी मिनाम एजाज (19), पुत्र एजाज अहमद शेख, गत गुरुवार को गांदरबल जिले के ऊपरी इलाके में ट्रेकिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान मौसम खराब हो गया और अंधेरा होने के कारण उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला।

दोनों युवकों की ओर से मदद मांगे जाने पर एसडीआरएफ की गुंड इकाई, गुंड पुलिस स्टेशन और डायल 112 की टीमों ने संबंधित क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी। हालांकि, दोनों के मोबाइल फोन बंद हो जाने के कारण उनसे संपर्क स्थापित करने में परेशानी आई।

बडगाम में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने की पहल शुरू

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर में कचरा प्रबंधन को प्रभावी बनाने और स्वच्छता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए बडगाम में पहली बार थोक कचरा उत्पादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्तरां, स्कूलों और अन्य बड़े संस्थानों को अपने यहां पैदा होने वाले कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का संदेश दिया गया। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ बाजारों को बढ़ावा देने के साथ कचरे के वैज्ञानिक निपटान और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना है।

आवास एवं शहरी विकास विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बड़े कचरा उत्पादकों को अपने कचरे के प्रसंस्करण और निपटान की व्यवस्था करनी होगी। बाजार बंद होने के बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने परिसर में खाद बनाने और कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकृत निजी एजेंसियों या नगर निकायों की सेवाएं भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रतिष्ठान के कचरे की पूरी जिम्मेदारी केवल नगर निकायों पर नहीं छोड़ी जा सकती।

मंदीप कौर ने बताया कि कचरा प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे सम्मेलन सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने व्यापारिक संगठनों, संस्थानों और स्थानीय समुदायों से कचरे को स्रोत पर अलग करने तथा उसके उचित निपटान की व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। बडगाम के उपायुक्त अतहर आमिर ने संस्थागत क्षमता मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही दूधपथरी और शालीगंगा जैसी प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण की आवश्यकता भी रेखांकित की।

स्वच्छ भारत मिशन जम्मू-कश्मीर के प्रबंध निदेशक देवांश यादव ने प्रतिभागियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण और अधिकृत कचरा प्रबंधन एजेंसियों की जानकारी दी।

आरएस पुरा में आसमानी बिजली गिरने से गरीब परिवार का मकान क्षतिग्रस्त

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू के आरएस पुरा क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी दौरान बडेयाल ब्राह्मणा की बस्ती प्रेम नगर में आसमानी बिजली गिरने से एक गरीब परिवार का कच्चा मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद परिवार के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल प्रभावित परिवार को किसी अन्य व्यक्ति के घर में शरण लेनी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार, जोगिंदर कुमार पुत्र डिप्टी नाथ के मकान पर अचानक आसमानी बिजली गिर गई। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि मकान के ऊपर लगा शेड उखड़कर दूर जा गिरा। इसके अलावा आंगन में लगे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों में दहशत फैल गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार, जोगिंदर कुमार का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और इस हादसे ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रभावित परिवार ने करीब तीन वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे मकान उपलब्ध नहीं हो पाया है। कच्चे मकान को नुकसान पहुंचने के बाद परिवार के पास सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

विस्तार कुपवाड़ा के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण पूरा, कई बस्तियों में काम शुरू

कुपवाड़ा के 29 पहाड़ी गांवों में पहुंचेगी बिजली, 1936 घर होंगे रोशन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। आजादी के दशकों बाद भी बिजली की सुविधा से वंचित कई बस्तियों को अब रोशन करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने जिले के 29 पहाड़ी गांवों के 1936 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई है। इसके लिए 14 करोड़ 74 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत अक्टूबर 2027 तक सभी चिन्हित घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अब तक शाम ढलने के बाद रोशनी के लिए लालटेन और दूसरे पारंपरिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

सरकार की इस योजना में कुपवाड़ा जिले के 13 क्षेत्रों की 29 पहाड़ी बस्तियों को शामिल किया गया है। इनमें मोरी, मनिगाह, कुमकाडी, टंगधार, रिडे चौकीबल, वावोरा, मचिल, केरन, हेहामा, कारूस, टीटवाल, सोगम, कादिराबाद, राशनपोरा, मील्याल, वारनौ और मैदानपोरा सहित अन्य इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले 1936 परिवारों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार के अनुसार, संबंधित बस्तियों का सर्वेक्षण और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब बिजली के खंभे, तार और अन्य जरूरी उपकरण जुटाने का काम किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ अन्य कार्यों की निविदा प्रक्रिया भी जारी है।

विद्युतीकरण योजना के तहत सोगम और कादिराबाद की 10 बस्तियों में काम शुरू होने की जानकारी दी गई है। यहां अब तक लगभग 86 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। विभाग का कहना है कि नए क्षेत्रों में बिजली लाइनें पहुंचाने के साथ आपूर्ति को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिले के उन गांवों में भी व्यवस्था सुधारने की योजना है, जहां कम वोल्टेज, पुरानी तारों और बिजली ढांचे से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। इसके लिए 14 अन्य कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कुल 169 करोड़ 55 लाख रुपये खर्च करने की योजना है। इन कार्यों में नई बिजली लाइनें बिछाना, कुपवाड़ा कस्बे में मौजूदा लाइनों पर भार कम करना, चेक द्रुगमुला और कलारूस में नए बिजली घर बनाना तथा पुराने तारों को बदलना शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन उपलब्ध कराया जाएगा।

लालटेन की रोशनी से बल्ब तक पहुंचने की उम्मीद

बिजली से वंचित बस्तियों के लोगों को उम्मीद है कि योजना पूरी होने के बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। स्थानीय निवासी अब्दुल अजीज ने कहा कि जिन गांवों में लोगों ने वर्षों तक बिजली के बिना जीवन बिताया, वहां बच्चों को जल्द बल्ब की रोशनी में पढ़ने का अवसर मिल सकता है। वहीं, मोहम्मद फहीम ने बताया कि उन्होंने अपना जीवन लालटेन की रोशनी में गुजारा है और उनके दादा भी इसी तरह रहे। उन्हें उम्मीद है कि अब आने वाली पीढ़ी को अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। सरकार ने अक्टूबर 2027 तक सभी 29 बस्तियों के 1936 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मोबाइल टावर और

बिजली की लाइनों से पक्षियों के अस्तित्व पर बढ़ता संकट



प्रकृति ने पृथ्वी को असंख्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों से सजाया है। इनमें पक्षियों का संसार अत्यंत सुंदर, आकर्षक और महत्वपूर्ण माना जाता है। पक्षी केवल आकाश की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वे बीजों का प्रसार करते हैं, कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, फसलों की रक्षा करते हैं तथा जैव विविधता को बनाए रखते हैं। यदि पृथ्वी से पक्षियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो प्रकृति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ जाएगा। दुर्भाग्यवश आधुनिक तकनीकी विकास और मानव की बढ़ती सुविधाओं ने पक्षियों के जीवन पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। विशेष रूप से मोबाइल टावरों, बिजली की उच्च वोल्टेज लाइनों और उनसे निकलने वाले विद्युत-चुंबकीय विकिरण का दुष्प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। आज गांव से लेकर शहर तक मोबाइल टावरों और बिजली की लाइनों का जाल तेजी से फैल चुका है। संचार और विद्युत व्यवस्था आधुनिक जीवन की आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव पर्यावरण और जीव-जगत पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें पक्षियों की जैविक संरचना और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पक्षियों की दिशा पहचानने की क्षमता, प्रजनन प्रणाली और तंत्रिका तंत्र इन तरंगों से प्रभावित होते हैं। अनेक प्रवासी पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लेकिन कृत्रिम विद्युत-चुंबकीय तरंगें उनके प्राकृतिक संकेतों में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। परिणामस्वरूप वे रास्ता भटक जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या अत्यधिक थकान के कारण मर जाते हैं। भारत में कभी घरों के आंगन में चहकने वाली गौरैया आज दुर्लभ होती जा रही है। गांवों और शहरों में गिद्ध, तोते, मैना, कबूतर और उल्लू जैसे पक्षियों की संख्या लगातार घट रही है।

माना जाता है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाला विकिरण इनके अंडों और बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। अंडों का विकास रुक जाता है और बच्चों के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। गौरैया जैसी छोटी पक्षियों पर इसका प्रभाव अधिक देखा गया है, क्योंकि वे मानव बस्तियों के आसपास रहती हैं जहां मोबाइल टावरों की संख्या अधिक होती है। बिजली की उच्च वोल्टेज लाइनें भी पक्षियों के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो रही हैं। बड़े पक्षी जैसे गिद्ध, चील, सारस और हंस जब बिजली के तारों पर बैठते हैं या उड़ते समय दो तारों के संपर्क में आ जाते हैं, तब उन्हें करंट लग जाता है। कई पक्षी तुरंत मर जाते हैं, जबकि अनेक घायल होकर बाद में दम तोड़ देते हैं। कोहरे, बारिश और अंधेरे के समय पक्षियों को बिजली की तारें स्पष्ट दिखाई नहीं देतीं, जिससे टकराव की घटनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लाखों पक्षी बिजली की लाइनों से टकराकर या करंट लगने से मारे जाते हैं।

मोबाइल टावरों और बिजली की लाइनों का प्रभाव केवल पक्षियों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यवहार पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि विकिरण के कारण पक्षियों की चहचहाहट, घोंसला बनाने की आदत और भोजन खोजने की क्षमता प्रभावित होती है। कई पक्षी मोबाइल टावरों के आसपास घोंसला बनाने से बचते हैं।

उनकी प्रतिरक्षा क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरीकरण और पेड़ों की कटाई ने भी पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिए हैं। जहां पहले घने जंगल और पेड़ होते थे, वहां अब मोबाइल टावर और बिजली के खंभे दिखाई देते हैं। जब प्राकृतिक आवास कम होते हैं और ऊपर से विकिरण तथा बिजली की तारों का खतरा बढ़ता है, तब पक्षियों के अस्तित्व पर दोहरा संकट उत्पन्न हो जाता है।



सुभाष चंद काशव
गांव जौवा, डाकघर गैहरा, तहसील व जिला चंबा (हि.प्र.)

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

पहाड़ों की प्यास और विकास की अंधी दौड़

हिमाचल प्रदेश को देवभूमि और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन आज जिस प्रकार राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह एक पहाड़ी राज्य है।

हिम और आंचल से बने हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व अब पर्यावरणीय संकट के कारण खतरे में दिखाई देने लगा है। हर वर्ष बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, जंगलों की कटाई और जल स्रोतों का सूखना इस संकट को और गंभीर बना रहे हैं।

राज्य में विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण और अवैध खनन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों का कटाव बढ़ रहा है और जंगल तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। पेड़ों की लगातार घटती संख्या के कारण वर्षा का चक्र भी प्रभावित हो रहा है। समय पर बारिश न होने से किसानों की फसलें सूखे की भेंट चढ़ रही हैं और लोग खेती-बाड़ी से विमुख होते जा रहे हैं। जल संरक्षण आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जल स्रोतों, तालाबों, कुओं और वाटर टैंकों का निर्माण तो करवा रही हैं, लेकिन जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण इनका अपेक्षित लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। कई हैंडपंप, नलकूप और वाटर सप्लाई योजनाएं बिना पानी के सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। गर्मियों के आते ही प्रदेश के कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा जाता है।

जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। जगह-जगह पाइपों से पानी का रिसाव होता रहता है, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की जाती। ऐसे में जल संरक्षण अभियानों की सार्थकता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। पानी की एक-एक बूंद आज अमूल्य बन चुकी है, फिर भी हम उसके महत्व को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे।



एआई निर्मित चित्र।

अवैध खनन भी जल संकट का एक बड़ा कारण बन चुका है। खड्डों और नदियों में अत्यधिक खनन के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी वर्षभर पानी बहता था, वहां अब सूखी धरती दिखाई देती है। नहरों, कूहलों और नलकूपों में पानी की कमी के कारण खेती की सिंचाई प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो भविष्य में लोगों को पानी भी सीमित मात्रा में खरीदकर लेना पड़ सकता है। जंगलों में हो रही अवैध कटाई और आगजनी ने भी पर्यावरण संतुलन बिगाड़ दिया है। पेड़ केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि पहाड़ों को मजबूती से बांधे रखने का कार्य भी करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कटने से बचाती हैं। जब जंगल कम होते हैं, तो भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पेड़ों का संरक्षण केवल पर्यावरण ही नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और जनता मिलकर जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गंभीर प्रयास करें। स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी इकाइयों के माध्यम से नियमित पौधरोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। जल शक्ति विभाग को सार्वजनिक स्थानों पर व्यर्थ बह रहे पानी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने होंगे। साथ ही ऐसे पेड़ों के रोपण को बढ़ावा देना चाहिए जो जल संरक्षण में सहायक हों।



सुखदेव सिंह
स्वतंत्र लेखक

हिमाचल प्रदेश का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब जल स्रोतों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए। पेड़ों की कटाई और अवैध खनन पर कठोर रोक लगाकर ही बिगड़ते पर्यावरण और जल संकट से मानवता को बचाया जा सकता है। यदि आज हम नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

यदि दयालुता हमारा स्वभाव है, तो हिंसा कहां से आती है?

हर व्यक्ति का स्वाभाविक स्वरूप दयालु, प्रेमपूर्ण, करुणामय और आनंदमय होता है। कोई भी बच्चा बिना किसी कारण के नहीं रोता। वह तभी रोता है, जब उसे भूख लगी हो, नींद आ रही हो या वह किसी बात से भयभीत हो। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति हिंसक व्यवहार करता है, तो उसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि किसी व्यक्ति में करुणा का अभाव है, तो उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। जब हम उसकी समस्या की जड़ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ अक्सर अकेलापन, भय, अस्वीकृति की भावना और अपनेपन का अभाव दिखाई देता है।



एआई निर्मित चित्र।

जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होता है, तो हम उसे अस्पताल भेजते हैं। लेकिन जब उसके व्यवहार में विकृति आ जाती है, तो हम उसे जेल भेज देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जेल में भी उसे ऐसे साधन और तकनीकें नहीं मिल पातीं, जिनकी सहायता से वह अपने व्यवहार को सुधार सके, अपनी भावनाओं को समझ सके और उनमें सकारात्मक परिवर्तन ला सके।

आज दुनिया में होने वाली हिंसा के पीछे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ भी एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं। मानसिक स्वास्थ्य विश्व के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों में से एक है। विकासशील और विकसित देशों से लेकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों और शांतिपूर्ण समाजों तक, यह समस्या सभी को प्रभावित करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हर 42 सेकंड में एक व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर रहा है। असंख्य युवा या तो आक्रामक और हिंसक होते जा रहे हैं या अवसाद का शिकार बन रहे हैं। भारत अपनी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और ध्यान की विधियों के माध्यम से इस संकट से निपटने में विश्व की सहायता कर सकता है।

सामान्यत: न तो घर में और न ही विद्यालय में हमें अपनी भावनाओं को संभालना सिखाया जाता है। कभी-कभी अकेलापन महसूस करना स्वाभाविक है। धन, परिवार और मित्रों की मौजूदगी के बावजूद व्यक्ति भीतर से उदास और अकेला महसूस कर सकता है। आज अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य की एक गंभीर चुनौती बन गया है, क्योंकि हमने स्वयं के साथ रहना और अपने भीतर शांति बनाए रखना नहीं सीखा है। यदि हम अपने भीतर शांति और आनंद अनुभव करना सीख लें, तो हमारी सकारात्मकता आसपास के लोगों तक भी पहुँचने लगेगी।

यहाँ हमारी श्वास स्वस्थ मन की कुंजी बन सकती है। स्वस्थ मन का लक्षण है चेहरे पर ऐसी मुस्कान, जिसे कोई छीन न सके, और भीतर ऐसा आत्मविश्वास, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। स्वस्थ मन आलोचना को स्वीकार करने के साथ-साथ रचनात्मक आलोचना करने का साहस भी देता है। यह निर्भय होने के साथ विनम्र बने रहने की क्षमता है।



गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

हर भावना हमारे शरीर में विशेष संवेदनाएँ उत्पन्न करती है और उसका संबंध हमारी श्वास से भी होता है। उदासी में हमारी श्वास का ढंग अलग होता है, जबकि प्रसन्नता में वह अलग होता है। क्रोध, निराशा और ईर्ष्या जैसी भावनाओं को हम अक्सर भीतर दबाकर रखते हैं। ऐसे में श्वास पर ध्यान देना हमें अपने मन को समझने और भावनाओं को संतुलित करने में सहायता कर सकता है।

दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने सरल श्वास तकनीकों और ध्यान को अपनाया है। सुदर्शन क्रिया जैसी विधियों ने अनेक लोगों को चिंता और निराशा से उबरने में सहायता दी है। ये तकनीकें हमें अपने मन का स्वामी बनना सिखाती हैं, ताकि हम अपनी भावनाओं के शिकार बनने के बजाय उन्हें समझकर जीवन में संतुलन, शांति और आनंद ला सकें।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

वाणी का माधुर्य ही व्यक्तित्व की असली पहचान



एआई निर्मित चित्र।

वाणी मनुष्य को मिला वह अनमोल वरदान है, जो उसे अन्य जीवों से अलग कर श्रेष्ठ बनाता है। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और संबंधों की नींव भी है। मधुर वाणी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण मानी जाती है, क्योंकि यही वह गुण है जो उसे समाज में सम्मान, प्रेम और स्वीकार्यता दिलाता है।

वाणी के माध्यम से मनुष्य अपने मित्र बना सकता है, बिगड़े संबंध सुधार सकता है और कठिन परिस्थितियों को भी सरल बना सकता है। इसके विपरीत कटु वचन सबसे मजबूत संबंधों को भी तोड़ने की क्षमता रखते हैं।

मृदुभाषी व्यक्ति समाज में सदैव आकर्षण का केंद्र होता है। उसका व्यवहार लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और उसके प्रति विश्वास स्वत: उत्पन्न हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी या सक्षम क्यों न हो, यदि उसकी वाणी में मधुरता नहीं है, तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। वास्तव में वाणी ही किसी व्यक्ति के संस्कार, चरित्र और मानसिकता का दर्पण होती है, जिससे उसके व्यक्तित्व का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है।

इतिहास और धर्मग्रंथ भी वाणी के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। रामायण में कुंभकर्ण का प्रसंग यह सिखाता है कि गलत समय पर बोले गए शब्द जीवन की दिशा बदल सकते हैं। माता सरस्वती के प्रभाव से उसकी वाणी भ्रमित हो गई और इच्छित वरदान के स्थान पर कुछ और ही मांग निकल गई, जिससे उसका भाग्य बदल गया। यह घटना बताती है कि वाणी पर नियंत्रण और स्पष्टता कितनी आवश्यक है।

इसी प्रकार महाभारत के भीषम द्वारा दिया गया उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बाण और मुख से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि एक बार कही गई बात संबंधों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। महान संत तुलसीदार ने भी अपनी चौपाई में मधुर वाणी को एक वशीकरण मंत्र बताया है।



धर्म देवा
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक

उनके अनुसार मीठे शब्द न केवल वातावरण को शांत और सुखद बनाते हैं, बल्कि कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति रखते हैं। वास्तव में, मधुर वाणी वह साधन है जिससे प्रेम, सौहार्द और सहयोग का वातावरण निर्मित होता है। आज के समय में, जब जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता लगातार बढ़ रही है, तब मधुर वाणी का महत्व और भी अधिक हो जाता है। एक विनम्र और सौम्य भाषा न केवल व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि समाज में विश्वास, सहयोग और सद्भाव का वातावरण भी बनाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



कविता

याद आता है...

डॉ. अशोक चौबे

यादों के सिलसिले में
गांव याद आता है।
मौन है गांव का
हर शख्स याद आता है।
लूट गया गांव गांव
के कुछ हाथों से।
यह लूट देखकर बस लुटेरे याद आते हैं।
कफन में लिपट सबको
एक दिन यात्रा पर जाना है।
खामोश होकर
जिस रास्ते से जाना है।
गांव की टूटी सड़क बस
अब याद आती है।
हाथों में शराब की बोतल लिए।
कुछ बिगड़े युवा
गांव के याद आते हैं।
गांव के सब बूढ़े मौन हो गए।।
उनका गूंगा हो जाना याद आता है।
कुछ कंबल पर
कुछ एक चादर पर।
बिकते गांव के आदमी याद आते हैं।
चुनाव में कौन पैसे पर,
शराब पर बिकेगा।
हर शख्स मेरी आंखों में नजर आता है।
अपनों को धोखा देने वाले अपने याद आते हैं।

संपादकीय

मरीज या मुनाफा?

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) और सरकारी खरीद मूल्य के बीच बड़े अंतर को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। जब 2,700 रुपये की खुदरा बिक्री वाली कैंसर की दवा पर 27,000 रुपये एमआरपी अंकित होने की बात सामने आई तो अदालत ने इसे पहले 'दिन-दहाड़े डकैती' और फिर अगली सुनवाई में 'कत्लेआम' यानी सामूहिक संहार तक कह दिया। दवा कारोबारियों, निजी अस्पतालों और सरकारी दवा खरीद से जुड़े जिम्मेदार लोगों के लिए इससे तीखी टिप्पणी शायद ही कोई हो सकती है। अदालत का यह सवाल भी बेहद अहम है कि आखिर इतना पैसा कहां जा रहा है और इसका फायदा किसे मिल रहा है? यह सवाल केवल किसी एक दवा या कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दवा और स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

विडंबना यह है कि केंद्र सरकार फरवरी 2025 में एक दवा, एक मूल्य और एक गुणवत्ता से जुड़ी व्यवस्था लागू कर चुकी है। इसके तहत दवा विक्रेताओं और ई-फार्मेसी के लिए मूल्य-सूची सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है, ताकि मरीजों को तय कीमत पर उचित गुणवत्ता वाली मानक दवाएं मिल सकें। इसके बावजूद यदि दवाओं की एमआरपी और वास्तविक खरीद कीमत में कई गुना अंतर बना हुआ है तो यह साफ संकेत है कि कानून और व्यवस्था के बीच कहीं गंभीर खाई मौजूद है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी इसलिए बढ़ जाती है कि मरीज की मजबूरी किसी भी स्थिति में मुनाफे का माध्यम न बने।

अधिकांश बड़े कारपोरेट अस्पताल अब सेवा संस्थान से आगे बढ़कर उद्योग का रूप लेते दिखाई देते हैं। कई अस्पताल मरीजों को अपने परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। यदि कोई मरीज बाहर से दवा लाने की बात करता है तो उपचार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति भी सामने आती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब ऐसे अस्पताल आयुष्मान भारत और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के तहत उपचार भी करते हैं। सवाल उठता है कि जब दवाएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में आती हैं तो एमआरपी की ऐसी व्यवस्था क्यों बनी हुई है, जिसमें अंकित कीमत और वास्तविक कीमत के बीच इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है?

कुछ समय पहले कंपनी मामलों के मंत्रालय की एक सर्वे रिपोर्ट ने भी सरकार को आगाह किया था कि दवाएं आम आदमी की पहुंच से जानबूझकर बाहर की जा रही हैं। रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि दवाओं की महंगाई का कारण केवल उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री का महंगा होना नहीं है, बल्कि दवा कंपनियों के अत्यधिक मुनाफे की प्रवृत्ति भी इसके पीछे है। आरोप है कि कई कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं करतीं और दवाओं की कीमत कई गुना तक अधिक रख देती हैं। यहां तक कि नामी-गिरामी कंपनियों के कुछ उत्पादों की कीमतों में भी वास्तविक लागत की तुलना में भारी अंतर सामने आया है। महंगी दवाओं की सरकारी अस्पतालों में खरीद और आपूर्ति में यदि भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनती है तो यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

इससे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग भी देसी-विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठा चुका है। कंपनियों ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पाद शुल्क संबंधी छूट का लाभ तो लिया, लेकिन उसका लाभ दवाओं की कीमतों में कमी के रूप में आम मरीजों तक कितना पहुंचा, यह बड़ा सवाल रहा है। दवाओं की कीमतों में यह गोलमाल केवल मरीजों की जेब पर असर नहीं डालता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

सरकार ने सीजीएचएस के अस्पतालों, जांच केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और जन-औषधि केंद्रों में एक दवा, एक मूल्य लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन किसी भी योजना की सफलता केवल घोषणा से नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। इसके लिए मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह नेटवर्क बनाना होगा। दवा वितरण में बोली के आधार पर भागीदारी करने वाले विक्रेताओं की केवल तकनीकी योग्यता ही नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता भी प्रमुख मानदंड होनी चाहिए। दवा खरीद समितियों को ऐसी दवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो उपचार में प्रभावी होने के साथ आम आदमी की पहुंच में भी हों।

चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए राज्यों को भी ऐसी व्यवस्था में भागीदार बनाया जाना चाहिए। इससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ अधिक रोगियों तक पहुंच सकेगा। चिकित्सा केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि जीवन रक्षा और मानवीय संवेदना से जुड़ा पेशा है। लाचार मरीज चिकित्सक के पास स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद लेकर जाता है, न कि दवा उद्योग के मुनाफे को बढ़ाने के लिए। जब इलाज और दवा के नाम पर आर्थिक शोषण बढ़ता है तो चिकित्सकों और अस्पतालों के प्रति भरोसा भी कमजोर होता है।

-शिवांश धाकड़

आज की प्रमुख हस्ती

रेखा की अलग पहचान

रेखा भारतीय सिनेमा की उन महान अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अभिनय, सौंदर्य, व्यक्तित्व और संवाद अदायगी से कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनका जन्मदिन 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। रेखा का फिल्मी सफर कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा में एक ऐसी पहचान बनाई, जो आज भी कायम है। शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ उन्होंने अपने अभिनय को लगातार निखारा और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए खुद को एक बहुआयामी अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया।



रेखा
जन्म : 10 अक्टूबर 1954

रेखा ने अपने करियर में रोमांटिक फिल्मों से लेकर सामाजिक और गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों तक में प्रभावशाली अभिनय किया। उनकी फिल्मों में उनकी भावनात्मक अभिव्यक्ति, संवाद बोलने की शैली और पर्दे पर प्रभावशाली उपस्थिति ने उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग पहचान दिलाई। 'उमराव जान' में उनके अभिनय को विशेष रूप से याद किया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया, जिसकी संवेदनाओं, संघर्ष और भावनाओं को उन्होंने बेहद प्रभावशाली ढंग से पर्दे पर उतारा। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

रेखा का नाम हिंदी सिनेमा की कई यादगार फिल्मों से जुड़ा है। 'खूबसूरत', 'सिलसिला', 'खून भरी मांग', 'इजाजत' और 'उत्सव' जैसी फिल्मों में उनके अलग-अलग रूप दर्शकों को देखने को मिले। उन्होंने ग्लैमर से आगे बढ़कर ऐसे किरदार भी निभाए, जिनमें महिला जीवन की जटिलताओं, भावनाओं और संघर्षों को प्रमुखता मिली। उनकी अदाकारी ने यह साबित किया कि एक अभिनेत्री केवल सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अभिनय कौशल और किरदारों की गहराई से भी लंबे समय तक दर्शकों के बीच अपनी जगह बना सकती है।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

राज्यपाल ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का किया आह्वान

ज्ञान के साथ कौशल, संवेदनशीलता, नैतिक मूल्य और उत्तरदायित्व की भावना भी आवश्यक: कविंद्र गुप्ता

भारतेन्दु संवाददाता, सोलन



राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सोलन जिले में बाहरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 577 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कीं। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान और कौशल के साथ नैतिक मूल्यों, संवेदनशीलता तथा उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए नवाचार और नए अवसरों को अपनाएं।

राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा की पूर्णता नहीं, बल्कि अवसरों, चुनौतियों और जिम्मेदारियों से भरे नए जीवन की शुरुआत है। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों में माता-पिता और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने सितंबर 2010 में बाहरा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय की प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में 10 स्कूलों, 16 विभागों और 60 से अधिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से लगभग 4,000 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। यह संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।

तेजी से बदलती तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के कल्याण तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार सृजित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया।

युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की राज्यपाल की नसीहत

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग समाज की समस्याओं के समाधान तथा देश के विकास के लिए करना चाहिए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बदलते समय में नई तकनीकों को सीखना और अपने कौशल को लगातार विकसित करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के सहयोग को हमेशा याद रखना चाहिए। समारोह के अंत में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने राज्यपाल और अन्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

पत्रकारों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा की मांग, जेपी नड्डा को सौंपा ज्ञापन



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर, बिलासपुर ने एम्स में पत्रकारों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन अध्यक्ष कश्मीर सिंह ठाकुर सहित अन्य पत्रकारों ने ओपीडी पंजीकरण और चिकित्सकीय परामर्श के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया।

ज्ञापन में मांग की गई कि एम्स में कार्यरत एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाई जाए। इससे ओपीडी पंजीकरण, चिकित्सकीय परामर्श और अन्य औपचारिकताओं को सरल बनाया जा सकेगा। फेडरेशन ने कहा कि पत्रकार जनहित से जुड़े समाचारों के संकलन और प्रसारण के लिए लंबे समय तक काम करते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी हैं। पत्रकारों ने प्रेस पहचान-पत्र के आधार पर पारदर्शी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया।

साथ ही, आम मरीजों के अधिकारों और आपातकालीन मामलों की प्राथमिकता बनाए रखने पर भी जोर दिया। फेडरेशन ने कहा कि हेल्प डेस्क बनने से पत्रकारों को चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी और पंजीकरण की प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा। इससे वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

न्यूज ब्रीफ

कांगड़ा में 6.24 ग्राम चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार, स्कूटी जब्त



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। जिला कांगड़ा पुलिस की सीआईए टीम ने वीरता के सामने गर्ग कॉलोनी के भट्ठा रोड पर नाकाबंदी के दौरान स्कूटी सवार दो व्यक्तियों को 6.24 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्कूटी को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार, वीरवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर जांच की जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान रमन सहगल (48) निवासी रिहालपुरा, कांगड़ा और विकास धीमान (43) निवासी रजहूँ, तहसील धीरा के रूप में हुई है। पुलिस थाना कांगड़ा में दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस चिट्टे के स्रोत और इसकी सप्लाई के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

ड्रग्स के खिलाफ उत्तर भारत में बड़ा एक्शन प्लान 6 राज्यों के राज्यपालों का होगा महामंथन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को एनआईटी हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ 6.0 का शुभारंभ करने के बाद नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में फैले नशे के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए छह राज्यों के राज्यपाल अगले महीने चंडीगढ़ में संयुक्त बैठक करेंगे। कटारिया ने बताया कि बैठक में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के राज्यपाल शामिल होंगे। बैठक की तारीख जल्द तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इसे खत्म करने के लिए सभी राज्यपाल मिलकर रणनीति बनाएंगे। बैठक में लिए जाने वाले संयुक्त फैसलों को जमीन पर शत-प्रतिशत लागू करवाया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में सभी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

भटोली-मल्यावर सड़क पर 150 फीट गहरी खाई में गिरी जेसीबी, चालक व बेलदार घायल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। भटोली-मल्यावर-बल्ह संपर्क मार्ग पर एक जेसीबी अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट नीचे गहरे नाले में जा गिरी। हादसे में चालक राम सिंह निवासी सुंदरनगर, मंडी और बेलदार जगदीश कुमार घायल हो गए। लोक निर्माण विभाग के कंदरौर अनुभाग के कनिष्ठ अभियंता संजीव कुमार की शिकायत पर थाना घुमारवीं में चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में बीएनएस की धारा 281 और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। भराड़ी घुमारवीं उपमंडल के गांव हम्बोट में पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने जेठ सुरेश कुमार और जेठानी पर रास्ता रोककर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं, सुरेश कुमार ने राजेश कुमार पर उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट व धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, दोनों मामलों में आरोपों की जांच की जा रही है। वहीं, भटोली-मल्यावर-बल्ह मार्ग पर हुए हादसे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

साइलेंट इंडिकेटर से हादसों का खतरा अधिवक्ता विश्व चक्षु ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू



दोपहिया वाहनों में साइलेंट इंडिकेटर से सड़क हादसों का खतरा बढ़ने का मुद्दा उठाते हुए धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने जनहित में पहल की है। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (रूथ, II) के सचिव सहित देश की चार प्रमुख दोपहिया निर्माता कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो लिमिटेड को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 और 91 के तहत विधिक नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान दोपहिया वाहनों में टर्न इंडिकेटर के साथ श्रव्य बजर अलर्ट और ऑटो-कट या सेल्फ-कैंसलिंग प्रणाली का अभाव है। चालक मोड़ लेने के बाद कई बार इंडिकेटर बंद करना भूल जाता है, जिससे वह सैकड़ों मीटर तक जलता रहता है। इससे आगे और पीछे से आने वाले वाहन चालकों को गलत संकेत मिल सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अधिवक्ता के अनुसार, हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर हो सकती है। विश्व चक्षु ने कहा कि चार पहिया वाहनों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जबकि दोपहिया वाहनों में ऐसी तकनीक की कमी पर ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने दावा किया कि इस तकनीक की लागत लगभग 50 से 150 रुपये है। उन्होंने इसे सड़क सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि ऐसी सुविधा की अनदेखी पर विचार किया जाना चाहिए। नोटिस में सभी दोपहिया वाहनों में 10 से 15 सेकंड का बजर अलर्ट और ऑटो-कट सिस्टम अनिवार्य करने, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने और पहले से चल रहे वाहनों में भी यह सुविधा लगाने पर विचार करने की मांग की गई है।

जोगेंद्रनगर में हिम आंचल पेंशनर संघ की बैठक में करीब 200 पेंशनरों ने लिया भाग

जितेन्दर कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, जोगेंद्रनगर। हिम आंचल पेंशनर संघ जिला मंडी की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को जोगेंद्रनगर के सामुदायिक भवन में जिला प्रधान बली राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिले के विभिन्न खंडों से करीब 200 पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया।

जिला प्रधान बली राम ठाकुर ने कहा कि संघ के पदाधिकारियों ने पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों की वेतन संशोधन संबंधी राशि का भुगतान लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन चिकित्सा बिलों, महंगाई भत्ते की किस्तों और एरियर का भुगतान लंबित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिवाली पर पेंशनरों को राहत देंगे। वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया देनदारियां जल्द चुकाने की मांग भी उठाई। बैठक में जिला प्रधान बली राम ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित गोपाल चंद शर्मा और शंभू राम जसवाल को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश मुख्य सलाहकार हरनाम सिंह ठाकुर ने संघ के संस्थापक सदस्यों बेली राम वर्मा और दान सिंह ठाकुर सहित सक्रिय सदस्यों को सम्मानित किया।



जोगेंद्रनगर में पेंशनर संघ की बैठक, पदाधिकारियों और वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान

यूएई में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पदों पर भर्ती, 16 से साक्षात्कार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर, बिलासपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि एम/एस वर्तिव गल्फ एलएलसी में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पदों पर भर्ती की जाएगी।

संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा धारक 20 से 45 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर और अनुभवी दोनों पात्र होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 1,100 से 1,300 एईडी वेतन मिलेगा। ड्यूटी आठ घंटे प्रतिदिन होगी और नियमानुसार ओवरटाइम का भुगतान किया जाएगा। आवास, परिवहन, चिकित्सा, वीजा और भोजन अथवा भोजन भत्ते सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है। साक्षात्कार 16 और 17 अक्टूबर को होंगे। आवेदन के लिए वैध पासपोर्ट जरूरी है। चयनित युवाओं को दो वर्ष के अनुबंध पर नौकरी मिलेगी।

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के विद्यार्थियों ने भांग उखाड़कर परिसर को बनाया स्वच्छ

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य गेट से लड़कों के हॉस्टल तक सड़क के दोनों किनारों पर उगी भांग एवं अन्य झाड़ियों को काटकर परिसर को साफ-सुथरा किया। इस अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने कहा कि महाविद्यालय के सभी विभागों के विद्यार्थी पूर्व निर्धारित स्थानों पर सफाई का पूरा ध्यान स्वयं रखते हैं, जिस कारण समस्त महाविद्यालय साफ-सुथरा और सुंदर दिखाई देता है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को सफाई का काम देकर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करवाना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ती है और वे अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने एक दिवसीय भांग उखाड़ो अभियान के अंतर्गत सफाई की।



मुख्य गेट से हॉस्टल तक सड़क के किनारों की सफाई की

इस अभियान में हिंदी विभाग के कला स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य गेट से लड़कों के हॉस्टल तक सड़क के दोनों किनारों पर उगी भांग एवं अन्य झाड़ियों को हटाकर सफाई की। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों ने महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दिया। इस सफाई अभियान का आयोजन हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंजु शर्मा, डॉ. श्यामलाल और डॉ. हेमा देवी ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में किया गया।

इस अभियान से विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से कार्य करने और स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा मिली। विभाग के शिक्षकों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान महाविद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और श्रम के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करते हैं।

लाहौल-स्पीति को स्वास्थ्य अनुसंधान की बड़ी सौगात 12 अक्टूबर को शिलान्यास

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति और सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केलांग में 12 अक्टूबर को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की प्रस्तावित परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इससे दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में चिकित्सा अनुसंधान को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रवि ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से शिलान्यास कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मंडी की सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के शामिल होने का कार्यक्रम है। रवि ठाकुर ने कहा कि परियोजना के लिए भूमि पहले ही चिन्हित की जा चुकी है।

दिनेश कुमार पंचायत समिति अध्यक्ष और अमिता देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग

पंचायत समिति लाहौल-स्पीति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए आयोजित निर्वाचन प्रक्रिया में दिनेश कुमार को अध्यक्ष तथा अमिता देवी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। निर्वाचन के बाद उपमंडलाधिकारी (ना.) एवं प्राधिकृत अधिकारी पंचायती राज चुनाव लाहौल स्थित केलांग कुनिका ऐकर्स ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

◆ दिनेश कुमार अध्यक्ष और अमिता देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण करते हुए



प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनेश कुमार पुत्र राम किशन, निवासी गांव एवं डाकघर मूरिंग, उपतहसील उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति को पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं, अमिता देवी पत्नी रमण, निवासी गांव एवं डाकघर शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल-स्पीति को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपमंडलाधिकारी कुनिका ऐकर्स ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश कुमार और उपाध्यक्ष अमिता देवी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पदाधिकारी अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए सौंपे गए दायित्वों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।

उन्होंने कहा कि पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देना और क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई गई कि वे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान तथा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे।

एसआईआर का विरोध कर कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठा रही सवाल : राकेश शर्मा

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयानों की कानूनी जांच कर कार्रवाई की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला



भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर जैसी संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद बनाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयानों को देशद्रोह से कम नहीं बताते हुए उनकी कानूनी जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। राकेश शर्मा ने धर्मशाला से जारी प्रेस बयान में कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है। देश में वर्ष 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया था। इनमें से कई अवसरों पर केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस के शासनकाल में यह प्रक्रिया स्वीकार्य थी, तो अब इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। मृत व्यक्तियों के नाम, दोहरी प्रविष्टियों, स्थानांतरित मतदाताओं के पुराने विवरण और अन्य त्रुटियों का नियमानुसार परीक्षण कर सुधार करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में बने रहना चाहिए और अपात्र प्रविष्टियों की जांच नियमों के अनुसार होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मतदाता सूची की शुद्धता के मुद्दे पर भी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर की किसी प्रक्रिया या निर्णय पर आपत्ति होने पर कांग्रेस को तथ्यों, दस्तावेजों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। बिना प्रमाण चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है। राकेश शर्मा ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस मतदाता सूचियों में संभावित त्रुटियों का सुधार नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची, पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पूरे लोकतंत्र से जुड़े विषय हैं।

पॉलिटेक्निक कॉलेज कांगड़ा में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। आयुष विभाग, हिमाचल प्रदेश के उपमंडल पुराना कांगड़ा की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांगड़ा में नशा मुक्ति अभियान एवं युवा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के तहत परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और तनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन उपमंडल आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, पुराना कांगड़ा, डॉ. बबीता गौतम के मार्गदर्शन में किया गया।

◆ परामर्श शिविर में विद्यार्थियों को तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश

शिविर में डॉ. मृदुला शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, एएचसी घीन ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। तनाव की स्थिति में उचित परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और मानसिक संतुलन बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

योग प्रशिक्षिका श्रीमती सोनिया ने विद्यार्थियों को योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान संबंधी गतिविधियां करवाईं। उन्होंने नियमित योग को दैनिक जीवन में शामिल करने के लाभ बताते हुए कहा कि योग और ध्यान तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं।

कल्लू के पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए सरकार द्वारा 3 करोड रुपए स्वीकृत

कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही सरकार

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने शुक्रवार को सोलंग नाला में फर्स्ट एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2026 का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने सोलंगी नाक मंदिर में पूजा-अर्चना की। मनाली पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। धर्माणी ने कहा कि सोलंग घाटी प्रदेश की सुंदर घाटियों में से एक है।







सोलंग घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में नई पहल।

यहां के लोग पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ अतिथि सत्कार के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार हिमाचल को विश्व का बेहतरीन पर्यटन राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कौशल विकास निगम कुल्लू जिले में युवाओं को निशुल्क प्रशिक्षण देगा। इसके तहत 210 युवाओं को असिस्टेंट राफ्टिंग गाइड, 90 को होमस्टे संचालन, 60 को स्ट्रीट फूड वेंडर, 60 को नेचर गाइड और 30 को साहसिक पर्यटन गाइड का प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने युवाओं से स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज कुल्लू के लिए तीन करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में विधायक भुवनेश्वर गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित गाइड और पर्यटन सेवाएं विकसित होने से पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

रेवाड़ी नगर परिषद में 26 वर्षीय निखिल मांढैया बने सबसे युवा वाइस चेयरमैन

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन चुनाव में वार्ड-12 के पार्षद और भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल मांढैया ने जीत दर्ज की। 26 वर्षीय निखिल ने विरोधी खेमे के प्रत्याशी चेतराम सैनी को पांच वोट से हराया। निखिल को 19, जबकि चेतराम को 14 वोट मिले। इस जीत के साथ निखिल नगर परिषद के सबसे युवा वाइस चेयरमैन बन गए। चुनाव परिणाम को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि निखिल उनकी पसंद माने जाते हैं। हालांकि, चुनाव से पहले राव समर्थक खेमे में 21 पार्षदों के समर्थन की चर्चा थी, लेकिन निखिल को 19 वोट ही मिले। इससे दो वोट कम मिलने पर क्रॉस वोटिंग और भीतरघात की चर्चाएं शुरू हो गईं। वहीं, चेतराम को मिले 14 वोट ने परिषद में विरोधी खेमे की मौजूदगी और राजनीतिक समीकरणों को भी उजागर किया।

पानीपत में स्कूल बस ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कूचला, मौके पर मौत

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में 35 वर्षीय शिक्षिका शीतल की मौत हो गई। वह स्कूटी पर सवार होकर स्कूल जा रही थीं। गोहाना बाईपास के पास तेज रफ्तार स्कूल बस ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर के बाद वह बस के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गईं। लोगों ने शोर मचाकर बस रुकवाई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसे देखकर चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हादसे के स्थान पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। दुर्घटना के कारण करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। शीतल एक बेटी की मां थीं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे दो बदमाशों की सीआईए-1 से मुठभेड़, दोनों गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के पलवल गांव में ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे दो बदमाशों और सीआईए-1 की टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से चार से पांच राउंड फायरिंग हुई। गोली लगने से पानीपत निवासी यशपाल (59) घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी गांव में ट्रांसफार्मर चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस टीम से उनका सामना हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि ट्रांसफार्मर चोरी की अन्य वारदातों और उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

फरीदाबाद में 10वीं के छात्र की मौत पर बवाल, लड़की के घर में तोड़फोड़

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में दसवीं कक्षा के छात्र अर्जुन की मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्र गुरुवार देर रात अपनी सहपाठी के घर गया था। बाद में परिजनों को सूचना मिली कि उसने लड़की के घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद परिजन और अन्य लोग लड़की के घर पहुंच गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने किसी तरह स्थिति संभाली और शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेजा। वहीं, लड़की के परिवार ने छात्र पर बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पानी के लिए प्रदर्शन करने पर नौ साल चला मुकदमा, 600 रुपए जुर्माने पर खत्म

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। हरियाणा के झज्जर में पानी की किल्लत को लेकर सड़क जाम करने के मामले में करीब नौ साल बाद कार्रवाई पूरी हुई। वर्ष 2017 में मातनहेल गांव में पानी की भारी कमी के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान सड़क जाम करने के मामले में केस दर्ज किया गया था। अब आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद 600 रुपये जुर्माना भरने पर मामला समाप्त हो गया। लंबे समय तक चले इस मामले का निपटारा होने से कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई। उस समय ग्रामीणों ने पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। गांव में पानी की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रदर्शन की फाइल तस्वीर भी सामने आई है।

मां की तेरहवीं पर हत्यारोपी जानवी के नए दावे, विशाल पर लगाए गंभीर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत। रामेश्वरी उर्फ बबीता हत्याकांड में आरोपी इन्फ्लुएंसर बेटी जानवी ने मां की तेरहवीं के बाद नए दावे किए हैं। उसने अपने कथित बॉयफ्रेंड विशाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उसने उससे ढाई लाख रुपये उधार लिए थे। जानवी का दावा है कि सोनीपत पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। उसने यह आशंका भी जताई कि जिस दिन उसकी मां की हत्या हुई, उस दिन विशाल नशे में हो सकता था। हालांकि, ये सभी जानवी के अपने दावे हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती। रामेश्वरी की हत्या के मामले में जांच जारी है। जानवी लगातार पुलिस की कार्रवाई और विशाल की भूमिका को लेकर सवाल उठा रही है। मामले में आरोपों की सच्चाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले से जुड़े वित्तीय लेन-देन, घटनाक्रम और दोनों पक्षों के बयानों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को लेकर कई सवाल बने हुए हैं।

100% दिव्यांग शिक्षिका के हक पर हाई कोर्ट सख्त

वैकल्पिक पद पर समायोजन, वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ की मांग, तीन दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



स्कूल जाते समय सड़क हादसे में 100 प्रतिशत दिव्यांग हुई हरियाणा की शिक्षिका वंदना अग्रवाल को सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि दिव्यांगता के बाद उन्हें न तो वैकल्पिक पद पर समायोजित किया गया और न ही पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा पूर्ण पेंशन सहित अन्य लाभ दिए गए। मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर, 2026 को निर्धारित की गई है। याचिका में शिक्षिका ने दिव्यांगता के बावजूद सेवा से जुड़े लाभ नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए अपने अधिकारों की मांग की है।

याचिकाकर्ता वंदना अग्रवाल के अनुसार, उनकी नियुक्ति 27 नवंबर, 1995 को प्राथमिक शिक्षिका के पद पर हुई थी। नौकरी के दौरान स्कूल जाते समय हुए सड़क हादसे में वह 100 प्रतिशत दिव्यांग हो गईं। इसके बाद उनके सामने सेवा जारी रखने और संबंधित लाभ प्राप्त करने का सवाल खड़ा हुआ। शिक्षिका का आरोप है कि दिव्यांगता के बाद उन्हें नियमानुसार वैकल्पिक पद पर समायोजित नहीं किया गया और न ही सेवा से संबंधित अन्य लाभ दिए गए। शिक्षिका ने अपनी याचिका में कहा है कि दिव्यांगता के बावजूद उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि जैसे लाभ नहीं मिले। इसके साथ ही उन्होंने पूर्ण पेंशन सहित अन्य सेवा लाभों की भी मांग की है। उनका कहना है कि इन लाभों से वंचित रहने के कारण उन्हें न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। याचिका में सेवा संबंधी लाभों का मुद्दा उठाते हुए शिक्षिका ने अदालत से उचित राहत देने की मांग की है। मामला इस बात से जुड़ा है कि दिव्यांगता के बाद कर्मचारी को सेवा में किस प्रकार के लाभ दिए जाने चाहिए और संबंधित विभाग की ओर से इस संबंध में क्या कदम उठाए गए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

अब मामले की अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष सामने आने की उम्मीद है। इसके बाद याचिका में उठाए गए मुद्दों पर आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। फिलहाल, अदालत ने याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। सेवा लाभों को लेकर शिक्षिका की मांगों पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान शिक्षिका की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। सरकार के जवाब के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल शिक्षिका को सेवा लाभ दिलाने की मांग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सीजेपी प्रदर्शन से पहले दिल्ली-हरियाणा में हलचल तेज

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली और हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। संगठन की ओर से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं, सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शन को लेकर पाबंदियां लगाने और पदाधिकारियों की निगरानी करने के आरोप लगाए हैं। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर सांगवान का दावा है कि संगठन के कई पदाधिकारियों को सीआईडी की ओर से फोन किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पदाधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और एक पदाधिकारी को हिरासत में लेने का प्रयास भी किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की तैयारी कर रहा है। प्रदर्शन से पहले सामने आए इन आरोपों के कारण दिल्ली और हरियाणा में संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

त्योहारों पर रेलवे ने बढ़ाई एसी कोचों की संख्या

साबरमती-दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन का संचालन

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी



आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यात्रियों को आरामदायक सफर उपलब्ध करवाने और ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जोधपुर-दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त एसी कोच जोड़ने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साबरमती और दिल्ली के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा।

रेलवे के इस निर्णय से त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग अपने घरों तक पहुंचने, परिवार के सदस्यों से मिलने और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का सहारा लेते हैं। ऐसे में नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है और यात्रियों को आरक्षित टिकट मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंडोर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त एसी कोच जुड़ने से इस ट्रेन की यात्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

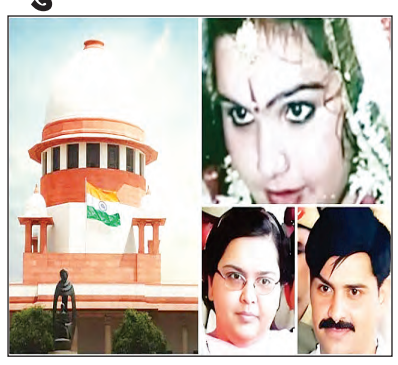
जानकारी के अनुसार, जोधपुर से चलने वाली ट्रेन में 10 अक्टूबर से और दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में 11 अक्टूबर से अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दोनों दिशाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त साबरमती-दिल्ली के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने का निर्णय भी त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की मांग को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष ट्रेन से यात्रियों को यात्रा के लिए एक और विकल्प मिलेगा। इससे नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

रेलवे की ओर से त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प उपलब्ध होंगे। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले आरक्षण और ट्रेन संबंधी जानकारी अवश्य जांच लें।

रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक, तीन शराब ठेकों पर लूटपाट और तोड़फोड़

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। जिले के बावल क्षेत्र में हथियारों से लैस बदमाशों ने तीन शराब ठेकों पर लूटपाट और तोड़फोड़ की। आरोपियों ने सेल्समैन को हथियार दिखाकर बीयर की पेटियां लूट लीं और विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। इस दौरान एक दुकानदार पर हमला कर उसे घायल कर दिया गया। ठेकेदार सुरेंद्र की शिकायत के अनुसार, बुधवार शाम करीब पांच बजे दो कारों और दो बाइकों पर सवार होकर आठ से दस बदमाश पावटी, किशनपुर और नांगल उगरा स्थित शराब ठेकों पर पहुंचे थे। आरोपियों के पास डंडे, रॉड और पिस्टल थीं। नांगल उगरा ठेके पर अन्य शराब, पेटीएम मशीन और सामान को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप है। ठेकेदार ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान होने का दावा करते हुए पुलिस को शिकायत और फुटेज सौंपी है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेलूराम हत्याकांड: सोनिया और संजीव की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला



भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के आठ सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी सोनिया और संजीव कुमार की समय पूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दोनों की रिहाई से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार है।

रेलूराम पूनिया हत्याकांड हरियाणा के चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल है। इस मामले में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया सहित उनके परिवार के आठ सदस्यों की हत्या की गई थी। सोनिया और संजीव कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। उनकी समय पूर्व रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता ने क्षमाशील रवैये को लेकर गंभीर टिप्पणी की। अदालत में दोषियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत के अंतिम फैसले से ही स्पष्ट होगा कि दोषियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ मिलेगा या नहीं।

◆ भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेते डिप्टी स्पीकर

अश्लील अफवाहों के चलते पुजारी की पीट पीटकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस

भारतेन्दु संवाददाता, सोनीपत



गोहाना क्षेत्र के गांव कथूरा में देवी मंदिर के 25 वर्षीय पुजारी सचिन की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने उसके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों के आधार पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक के भाई अमन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, सचिन पिछले तीन वर्षों से गांव के देवी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा कर रहा था। उसके खिलाफ कुछ अश्लील अफवाहें फैलाई जा रही थीं। आरोप है कि इन्हीं अफवाहों के चलते ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई अमन ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि सचिन के खिलाफ फैलाई जा रही अश्लील अफवाहों के कारण उसकी हत्या की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या में शामिल आरोपितों की पहचान और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बरौदा थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े लोगों के बयान लेकर तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने अफवाहों के आधार पर हिंसा किए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। किसी भी आरोप या अपुष्ट जानकारी की पुष्टि किए बिना कानून अपने हाथ में लेना गंभीर अपराध है। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। ग्रामीणों से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पुजारी के खिलाफ अफवाहें किसने फैलाई थीं और मारपीट में कौन-कौन शामिल था।

जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने जस्टिस टावर में की नारेबाजी

गुरुग्राम कोर्ट में वकीलों की हड़ताल, न्यायिक कार्य ठप

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम



अधिवक्ता परवीन बूरा के साथ मारपीट के विरोध में शुक्रवार को गुरुग्राम जिला अदालत में न्यायिक कार्य स्थगित रहा। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने जस्टिस टावर में हड़ताल कर नारेबाजी की और हमले के आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। वकीलों ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की। जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, उपप्रधान साहिल यादव, सचिव प्रशांत ठाकरान और संयुक्त सचिव विक्रम यादव सहित अन्य अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

इस दौरान गजेंद्र तंवर, रणजीत सिंह भ्याना, ज्योति शर्मा, अंबुज श्रीवास्तव, योगिता, ज्योति पिपलानी और कपिल गलिया सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता पर हमला गंभीर मामला है और इस पर पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, परवीन बूरा 16 सितंबर की रात अपने गांव से संबंधित बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के केंद्र पर गए थे। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

वकीलों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होती है। अधिवक्ताओं ने मांग की कि पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करे और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शुक्रवार को हड़ताल के चलते जिला अदालत में न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और आरोपितों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में वकीलों ने एकजुटता दिखाते हुए पुलिस से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से मामले की जांच या आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान शामिल नहीं है। वकीलों ने चेतावनी दी कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पहलवान नितेश के सम्मान समारोह में चोर का हाथ साफ, 96 हजार से ज्यादा रुपए गायब

भारतेन्दु संवाददाता, गोहाना



सोनीपत के गोहाना क्षेत्र के गांव जागसी में पहलवान नितेश सिवाच के सम्मान समारोह के दौरान चोरी की वारदात सामने आई है। समारोह में एक व्यक्ति की जेब से 96,300 रुपये चोरी हो गए। यह राशि गांव के लोगों ने नितेश को उपहार देने के लिए चंदे के रूप में एकत्र की थी। घटना के बाद पीड़ित ने बुटाना चौकी में शिकायत देकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, जापान में आयोजित एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे पहलवान नितेश सिवाच के सम्मान में छह अक्टूबर को गांव जागसी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समारोह गांव के शहीद स्मारक के पास हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और अन्य लोग शामिल हुए। गांव के लोगों ने पहलवान की उपलब्धि पर खुशी जताने और उन्हें सम्मान स्वरूप उपहार देने के लिए आपस में चंदा एकत्र किया था। पीड़ित जयभगवान ने बताया कि ग्रामीणों से एकत्र किए गए चंदे की कुल राशि 96,300 रुपये उसके पास रखी हुई थी।

कार्यक्रम में काफी भीड़ होने के कारण लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई थी। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर भीड़ का फायदा उठाया और जयभगवान की जेब से पूरी रकम निकाल ली। कुछ समय बाद जब उसे रुपये चोरी होने का पता चला तो समारोह में मौजूद लोगों के बीच इस घटना की चर्चा होने लगी। घटना के बाद जयभगवान ने पुलिस चौकी बुटाना में शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस से अज्ञात व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

चोरी हुई रकम गांव के लोगों ने मिलकर एकत्र की थी और इसका इस्तेमाल पहलवान नितेश सिवाच को उपहार देने के लिए किया जाना था। ऐसे में चंदे की पूरी राशि चोरी होने से ग्रामीणों की योजना प्रभावित हुई है। गांव में पहलवान के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया।

फर्जीवाड़ा दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अभिमन्यु चौधरी की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला

जींद रियासत की रानी समेत पांच पर जमीन धोखाधड़ी का केस

भारतेन्दु संवाददाता, जींद



जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने और दस एकड़ जमीन की दोबारा रजिस्ट्री करवाने के कथित प्रयास के मामले में जींद रियासत की रानी इंद्रजीत कौर, उनकी पुत्रवधू हरसिमरन कौर समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहर थाना पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिमन्यु चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में नगर परिषद के सचिव सुमित दहिया, पटवारी नरेश चहल और गांव रामराय निवासी सुभाष ठेकेदार को भी नामजद किया गया है।

शिकायत के अनुसार, जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं और दोबारा रजिस्ट्री कराने के प्रयास को लेकर पुलिस से शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दस एकड़ जमीन को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में जींद रियासत की रानी इंद्रजीत कौर और उनकी पुत्रवधू हरसिमरन कौर के अलावा नगर परिषद के सचिव सुमित दहिया, पटवारी नरेश चहल और गांव रामराय निवासी सुभाष ठेकेदार के नाम शामिल हैं। शिकायत में इन सभी पर जमीन के दस्तावेज तैयार करने और रजिस्ट्री से संबंधित कथित धोखाधड़ी में भूमिका होने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

मामले की शिकायत दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिमन्यु चौधरी ने पुलिस को दी थी। शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जमीन से जुड़े विवाद में दस्तावेजों की वैधता और रजिस्ट्री प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होगा कि जमीन से संबंधित दस्तावेज किस प्रकार तैयार किए गए और रजिस्ट्री कराने के कथित प्रयास में किन लोगों की क्या भूमिका रही। शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, जमीन से संबंधित दस्तावेजों और रजिस्ट्री प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या जमीन की रजिस्ट्री पहले हो चुकी थी और क्या उसे दोबारा दर्ज कराने का प्रयास किया गया था। इस मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच का हिस्सा हो सकती है। जमीन के दस्तावेजों से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड का सत्यापन और संबंधित पक्षों के बयान जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच जारी है। मामले में नामजद पांचों लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी शिकायत के आधार पर हैं। पुलिस जांच पूरी होने और संबंधित साक्ष्यों के सत्यापन के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

दस एकड़ जमीन की दोबारा रजिस्ट्री का प्रयास

पुलिस मामले से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेजों और अन्य संबंधित कागजात की जांच करेगी। इसके साथ ही शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान किया जाएगा। जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है।

दिल्ली के रघुबीर नगर में अतिक्रमण पर एक्शन, नाले के निर्माण का रास्ता साफ

रघुबीर नगर में 42 ढांचे टूटे, 505 वर्गमीटर जमीन कराई मुक्त

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के पश्चिमी इलाके रघुबीर नगर में शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से नाले के ऊपर बने अवैध निर्माणों को हटाते हुए करीब 505 वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस दौरान लगभग 42 ढांचों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य नाले के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करना था। वहीं, कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने अपनी परेशानियां बताते हुए निगम प्रशासन के कदम पर सवाल उठाए।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र की टीम ने रघुबीर नगर स्थित बी-1 और के ब्लॉक में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया। इस कार्रवाई में निगम के फील्ड स्टाफ के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। प्रशासन ने नाले के ऊपर बने करीब 42 अवैध ढांचों को हटाया और लगभग 505 वर्गमीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई नियमानुसार की गई। पुलिस और निगम कर्मचारियों के सहयोग से अतिक्रमण हटाने का अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रशासन का कहना है कि जमीन खाली होने से नाले के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।



नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, पश्चिमी जोन के रघुबीर नगर वार्ड में सीएमडीएफ फंड से नाले का निर्माण कराया जाना था। हालांकि, नाले के ऊपर बड़ी संख्या में बहुमंजिला ढांचे बनाए जाने के कारण निर्माण कार्य में बाधाएं आ रही थीं। अतिक्रमण की वजह से नाले का काम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। प्रशासन का कहना है कि नाले का निर्माण क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन नाले की जमीन पर अवैध निर्माण होने से परियोजना प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से निगम ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। निगम अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासन ने उन्हें नाले के ऊपर बने निर्माणों को स्वयं हटाने का अवसर दिया था।

हालांकि, नोटिस जारी होने के बावजूद अवैध ढांचों को नहीं हटाया गया। इसके बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की सहायता से बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत नाले के ऊपर बने लगभग 42 ढांचों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के बाद निगम प्रशासन ने करीब 505 वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक, अब नाले के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

20 अक्टूबर तक बुक करें टिकट छात्रों को एअर इंडिया दे रही खास छूट

एजेंसी ,नई दिल्ली

कॉलेज की पढ़ाई, सेमेस्टर ब्रेक, इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट के लिए हवाई सफर करने वाले छात्रों के लिए एअर इंडिया एक खास ऑफर लेकर आई है। एयरलाइन अपने स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को घरेलू उड़ानों के बेस फेयर पर 10 प्रतिशत की सीधी छूट दे रही है। इसके साथ छात्रों को अतिरिक्त सामान ले जाने और यात्रा की तारीख में बदलाव जैसी कई सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा।



एअर इंडिया में छात्रों की बचत, टिकट पर 10% डिस्काउंट

यह ऑफर उन विद्यार्थियों के लिए खास है, जिन्हें पढ़ाई के सिलसिले में बार-बार यात्रा करनी पड़ती है। एअर इंडिया का यह सीमित अवधि का ऑफर 20 अक्टूबर 2026 तक की जाने वाली बुकिंग पर लागू है। इसके तहत छात्र वन-वे और राउंड-ट्रिप, दोनों तरह की घरेलू उड़ानों के टिकट बुक कर सकते हैं। पात्र यात्रियों को बेस फेयर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इससे घर और कॉलेज के बीच सफर करने वाले विद्यार्थियों को हवाई टिकट पर बचत करने का मौका मिलेगा।

हालांकि, छूट का लाभ लेने के लिए एयरलाइन की निर्धारित पात्रता और बुकिंग संबंधी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। एअर इंडिया के स्टूडेंट प्रोग्राम की एक प्रमुख विशेषता अतिरिक्त बैगेज अलाउंस है। इसके तहत पात्र छात्रों को निर्धारित सामान सीमा के अतिरिक्त 10 किलोग्राम सामान ले जाने की सुविधा मिलती है।

यह सुविधा खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो घर से हॉस्टल या कैंपस लौटते समय किताबें, कपड़े और पढ़ाई से जुड़ा जरूरी सामान साथ लेकर चलते हैं। इससे उन्हें सामान की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के कार्यक्रमों में बदलाव हो सकता है।

त्योहारी भीड़ से निपटने की तैयारी, रेलवे ने बढ़ाए एसी कोच; दिल्ली रूट पर स्पेशल ट्रेन

एजेंसी ,नई दिल्ली

आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस में दो अतिरिक्त वातानुकूलित कोच जोड़े जाएंगे। इस फैसले से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है और अधिक लोगों को आरामदायक सफर का विकल्प मिल सकेगा।

रेलवे का उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानी कम करना और उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ाना है। अतिरिक्त एसी कोच जुड़ने से खासकर वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिल सकता है। त्योहारों में घर जाने और वापस लौटने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रमुख रेल मार्गों पर आरक्षण की मांग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती और दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की भी जानकारी दी गई है। इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त रेल सेवा का विकल्प मिलेगा और नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।

एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब



एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगी है। गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज किया गया। यह स्तर हवा की खराब स्थिति को दर्शाता है, जिससे स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

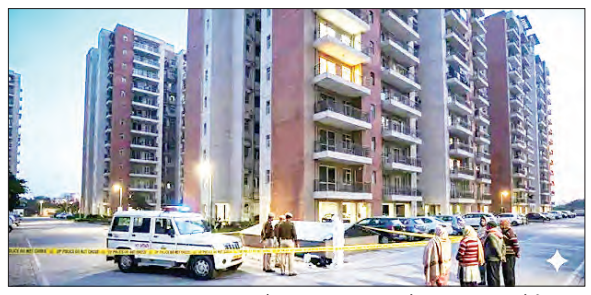
लोनी में प्रदूषण बढ़ने के पीछे अवैध फैक्ट्रियों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इन इकाइयों से निकलने वाला धुआं और प्रदूषक तत्व वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। संबंधित विभागों की ओर से समय-समय पर कार्रवाई किए जाने के बावजूद इलाके में प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है।

स्थानीय स्तर पर प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों की नियमित जांच और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। लोनी की हवा खराब होने के बीच दिल्ली-एनसीआर के अन्य इलाकों की वायु गुणवत्ता पर भी लोगों की नजर बनी हुई है।

ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: 12वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरे टेक कर्मी, मौत

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट (नोएडा एक्सटेंशन) की हाईराइज सोसायटियों में बहुमंजिला इमारतों से कूदकर खुदकुशी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार तड़के बिसरख कोतवाली क्षेत्र के तहत आने वाली बहुचर्चित ऐस डिविनो सोसायटी में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। यहां 12वीं मंजिल की बालकनी से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे कूदकर 36 वर्षीय एक टेक कर्मी ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।



मृतक युवक की पहचान अनिल कुमार (36) के रूप में हुई है। वह एक निजी आईटी कंपनी में काम करते थे और मूल रूप से नोएडा के सेक्टर-121 के निवासी थे। उनके परिवार में पत्नी और एक छोटी बेटी हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच और परिजनों के बयान के मुताबिक, अनिल पिछले कुछ समय से गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी बिगड़ती मानसिक स्थिति और डिप्रेशन को देखते हुए ही उनके रिश्तेदार उन्हें कुछ समय पहले ऐस डिविनो सोसायटी स्थित अपने फ्लैट पर लेकर आए थे, ताकि उनका मन बहल सके और वे तनाव से बाहर निकल सकें। हालांकि, शुक्रवार तड़के जब घर के लोग सो रहे थे या टहलने की तैयारी कर रहे थे, तभी अनिल ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरते ही सोसायटी के सुरक्षा गार्ड और आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्र हो गए। अनिल को तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बिसरख थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिसरख थाना पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डिप्रेशन ही मुख्य वजह सामने आ रही है, लेकिन पुलिस वित्तीय तनाव, कर्ज और पारिवारिक कारणों के कोणों से भी मामले की गहराई से जांच कर रही है।

'वर्दी के पीछे भी एक इंसान है', दिल्ली पुलिस की भावुक अपील चर्चा में

एजेंसी, नई दिल्ली

विश्व डाक दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने नागरिकों के नाम एक भावुक खुला पत्र लिखकर समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। राजधानी में चल रहे प्रदर्शनों के बीच पुलिस की इस चिट्ठी में कर्तव्य, संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं को प्रमुखता से सामने रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने अपने संदेश में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। पुलिसकर्मी दिन-रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की रक्षा करने के लिए काम करते हैं। हालांकि, वर्दी पहनने वाले पुलिसकर्मी भी आम इंसान हैं, जिनकी अपनी भावनाएं, जिम्मेदारियां और परिवार होते हैं। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि वर्दी के पीछे एक ऐसा इंसान है, जो अपने परिवार से दूर रहकर भी दूसरों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी निभाता है। उसके जीवन में भी खुशियां, चिंताएं और निजी परेशानियां होती हैं।

न्यूज ब्रीफ

नोएडा में नवजात चोरी से मचा हड़कंप, बच्चे की तलाश में जुटी पुलिस

एजेंसी, नई दिल्ली। नोएडा के सेक्टर-110 स्थित भंगेल मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल (एमसीएच विंग) से शुक्रवार सुबह तीन दिन के नवजात शिशु की चोरी का मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। आरोपी महिला नवजात को लेकर फरार हो गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला को एक युवक के साथ बाइक पर भागते हुए देखा गया है। जानकारी के मुताबिक, भंगेल निवासी सपना अपने पति गौतम के साथ डॉक्टर के पास गई थीं। उस समय उनका तीन दिन का नवजात गौतम की सास रक्षा देवी के पास था। रक्षा देवी भी स्वास्थ्य केंद्र से छुट्टी मिलने के बाद अपना सामान पैक कर रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात महिला मौके का फायदा उठाकर नवजात को लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में अफरा-तफरी मच गई और बच्चे की तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला एक युवक के साथ बाइक पर जाती दिखाई दे रही है। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। परिवार बच्चे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा है।



प्रयागराज नगर निगम हादसे में लापरवाही के आरोपी अभियंता को ही बनाया जांच टीम का सदस्य

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रयागराज के नगर निगम के खुल्दाबाद जोनल कार्यालय में निर्माणाधीन भवन का पोर्च गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नगर निगम के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया, जब कथित लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहे सहायक अभियंता को ही हादसे की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय टीम में शामिल कर लिया गया। जानकारी के अनुसार, खुल्दाबाद जोनल कार्यालय में अर्द्धनिर्मित भवन का पोर्च अचानक गिर गया था। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना के बाद जिम्मेदारी तय करने और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई। हालांकि, आरोपित अभियंता को जांच टीम में शामिल किए जाने से जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। इस फैसले की आलोचना होने के बाद संबंधित अभियंता को टीम से हटाने की बात कही गई। अब मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है।

प्रयागराज: गाय ढूंढ रहे युवक पर हमला, मोबाइल तोड़ नकदी लूटी; जांच में जुटी पुलिस



एजेंसी ,नई दिल्ली

तीर्थनगरी प्रयागराज के संगम क्षेत्र स्थित परेड मैदान में एक हैरान कर देने वाली हिंसक वारदात सामने आई है। यहाँ अपनी लापता गाय की तलाश करने गए शुभम नामक युवक पर दबंगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित शुभम जब परेड मैदान के पास अपनी गाय ढूंढ रहा था, तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया।

देखते ही देखते दबंगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया और लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से निर्दयतापूर्वक पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान हमलावरों ने शुभम का मोबाइल फोन पटककर तोड़ दिया और उसके पास मौजूद नकदी भी जबरन छीन ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में शुभम को गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में पीड़ित ने तत्काल दारागंज थाने पहुँचकर पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई और मामले की लिखित शिकायत दी। शुभम की तहरीर के आधार पर दारागंज थाना पुलिस ने नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है।

पुलिस का कहना है कि पीड़ित का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है और वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व स्थानीय लोगों से पूछताछ के जरिए हमलावरों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मौत का तांडव, ट्रॉले में जिंदा जला चालक

एजेंसी ,नई दिल्ली

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर शुक्रवार अलसुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मसानी बराज के समीप दो ट्रालों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद एक ट्रॉले में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे ट्रॉले में फंसे चालक को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे में दूसरे ट्रॉले का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। आग की चपेट में आए ट्रॉले के चालक को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अलर्ट, सीमाओं पर बढ़ाई गई निगरानी

एजेंसी ,नई दिल्ली

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, इसके बावजूद संभावित विरोध-प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 23 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है।

पुलिस ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करते हुए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।



मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर भी असर

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा कारणों के चलते दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद करने की जानकारी सामने आई है। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, दिल्ली आने और यहां से रवाना होने वाली कई ट्रेनों को भी रद्द किए जाने की सूचना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मेट्रो और रेलवे की आधिकारिक सूचनाओं की जांच कर लें। दिल्ली पुलिस ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है।

गंगा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर, ग्रेटर नोएडा में नई सड़क की तैयारी

एजेंसी, नई दिल्ली

ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) तक पहुंचना जल्द ही आसान हो सकता है। इसके लिए 105 मीटर चौड़ी सड़क को ईपीई से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजना के तहत आठ गांवों की करीब 63 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगा। ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) तक पहुंचना जल्द ही आसान हो सकता है। इसके लिए 105 मीटर चौड़ी सड़क को ईपीई से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

परियोजना के तहत आठ गांवों की करीब 63 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) करेगा। परीचौक से जुनपत तक 105 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है। अब जुनपत से बील अकबरपुर के समीप ईपीई तक



लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-34 (एनएच-34) से जोड़ने की भी योजना है। पूरी परियोजना के तहत यह सड़क आगे हापुड़ बाइपास तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई करीब 37 किलोमीटर होगी।

इस सड़क को गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले चरण में निर्माण कार्य ईपीई तक पूरा करने की योजना है। परियोजना पूरी होने के बाद ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से एक्सप्रेसवे तक पहुंचना सुविधाजनक हो सकता है।

दिल्ली में भारी जाम की आशंका, शनिवार दोपहर तक रेल सेवाओं पर असर

10 अक्टूबर को दिल्ली में जाम का खतरा, रेल सेवाएं प्रभावित

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर, शनिवार को भारी ट्रैफिक जाम की आशंका के बीच रेलवे ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए कई रेल सेवाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से दिल्ली आने-जाने वाले हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। दिल्ली में 10 अक्टूबर को दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी यातायात जाम की आशंका जताई गई है।

ऐसी स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है। सड़क मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों को स्टेशन पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इसी संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रेलवे ने शुक्रवार को दोपहर दो बजे से नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से प्रस्थान करने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, शनिवार को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक इन दोनों स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनों को भी निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य संभावित यातायात अव्यवस्था के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना और रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखना है।

हालांकि, किसी विशेष ट्रेन के संबंध में अंतिम जानकारी के लिए यात्रियों को रेलवे की आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए। रेलवे के फैसले के अनुसार, शनिवार, 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे तक नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में दिल्ली पहुंचने वाली संबंधित ट्रेनों को उनके मूल प्रस्थान स्टेशन से ही रद्द करने का निर्णय लिया गया है।



दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट से रेल सेवाएं प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द

इसका मतलब है कि यात्रियों को केवल दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने के बाद ही ट्रेन रद्द होने की जानकारी मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए।

संबंधित ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन पर ही सेवा निरस्त किए जाने के कारण यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले स्थिति की जांच करना जरूरी होगा। इस फैसले से दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों, दूसरे शहरों से राजधानी आने वाले लोगों और दिल्ली से आगे की यात्रा करने की योजना बना रहे यात्रियों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं, उन्हें अपनी ट्रेन के नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

सावधान! मेरठ में रंगीन रसायनों से हरी की जा रहीं सब्जियां

एजेंसी ,नई दिल्ली

मेरठ में सब्जियों को ताजा, हरा और आकर्षक दिखाने के लिए मैलाकाइट ग्रीन जैसे रसायनों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। प्रयोगशाला जांच में सब्जियों में इस रसायन की मौजूदगी की पुष्टि होने की जानकारी दी गई है। इससे बाजार में बिकने वाली सब्जियों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, पालक, धनिया, मटर, हरी मिर्च, भिंडी और सेम जैसी हरी सब्जियों को चमकीला दिखाने के लिए रंगों और रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखने में ताजी और स्वस्थ लगने वाली ये सब्जियां वास्तव में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मैलाकाइट ग्रीन एक औद्योगिक रंग है, जिसका उपयोग ऊन रंगने और अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है।

पालमपुर में सीएम-विधायक के बीच संवादहीनता से विकास प्रभावित : कपूर

भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता बोले—2027 के चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयार है संगठन; कांग्रेस की गारंटियों और विकास कार्यों पर उठाए सवाल

रीत वशिष्ठ, भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पालमपुर से पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल त्रिलोक कपूर ने वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का दावा करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और पालमपुर के विकास कार्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के नेतृत्व में पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है और कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि पालमपुर में भाजपा संगठन की स्थिति प्रदेश के 66 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बेहतर रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसकी सराहना की है।

कांग्रेस की गारंटियों पर साधा निशाना: त्रिलोक कपूर ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई गारंटियां देकर सत्ता हासिल की, लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रही। उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपए देने, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), युवाओं को पांच वर्षों में पांच लाख नौकरियां देने, दूध की खरीद के लिए निर्धारित दरों और गोबर खरीदने जैसी घोषणाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन वादों को पूरा नहीं किए जाने से जनता में निराशा है। कपूर ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक परिणाम मिलेंगे।



टिकट का फैसला सर्वे और चुनाव समितियों के आधार पर

मुलाकात जो बदले हालात

पालमपुर में टिकट को लेकर उठने वाली चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिलोक कपूर ने कहा कि भाजपा में टिकट वितरण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। उनके अनुसार, पार्टी विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण करवाती है और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर प्रदेश चुनाव समिति तथा राष्ट्रीय चुनाव समिति में विचार के बाद निर्णय लिया जाता है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को अपना मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहता है। कपूर ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा, जनजातीय मोर्चा तथा प्रदेश महामंत्री जैसे दायित्वों पर काम किया। वर्तमान में वह पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

भाजपा के ऐतिहासिक परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री और विधायक के बीच तालमेल की कमी का आरोप: पालमपुर के विकास पर सवाल उठाते हुए त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक के बीच राजनीतिक तालमेल की कमी को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री का मुंह पूर्व की तरफ होता है और पालमपुर के जनप्रतिनिधि का मुंह पश्चिम की तरफ होता है।' उनके अनुसार, संवाद की कमी का असर क्षेत्र के विकास पर पड़ रहा है। कपूर ने आरोप लगाया कि पिछले चार वर्षों में पालमपुर में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र को लेकर किए गए वादों और पालमपुर को जिला बनाने की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय विधायक की राजनीतिक प्राथमिकताओं और मुख्यमंत्री के साथ संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए।

2027 में भाजपा की जीत का दावा: त्रिलोक कपूर ने कहा कि पालमपुर में भाजपा का संगठन मजबूत है और युवा, महिलाएं तथा बुद्धिजीवी वर्ग क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पालमपुर को विकास की नई दिशा देना है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के संकल्पों का भी उल्लेख किया।

जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील: इंटरव्यू के अंत में त्रिलोक कपूर ने पालमपुर की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जनता को निराशा हाथ लगी है और लोग विकास की अपेक्षा कर रहे हैं। कपूर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भविष्य में हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश तथा पालमपुर में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है।

न्यूज ब्रीफ

पांवटा साहिब के वाई-प्वाइंट पर हादसा, महिला गंभीर



भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। पांवटा साहिब के वाई-प्वाइंट पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में साइकिल सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान के शटर से जा टकराई। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार ने साइकिल सवार महिला को टक्कर मारी, जिसके बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की पहचान और हादसे के कारणों की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

ब्लू स्टार लिमिटेड में 100 पदों पर भर्ती

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। जिला कांगड़ा के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। ब्लू स्टार लिमिटेड, काला अंब में पीआईएमआईएस ट्रेनिंग/अप्रेंटिस के तहत 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 12 अक्तूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा में साक्षात्कार होंगे। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि आईटीआई फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, आरएसी, मशीनिस्ट, प्लंबर, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सहित संबंधित ट्रेडों के पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 16,000 से 20,800 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पहले https://eemis.hp.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। उम्मीदवार दो पासपोर्ट साइज फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा और उपलब्ध होने पर अनुभव प्रमाण पत्र साथ लाएं। साक्षात्कार में आने के लिए यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए 01892-224892 पर संपर्क करें।

कोट, डवाहन में कल बंद रहेगी बिजली

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के विद्युत उपमंडल साईंगलू के अंतर्गत 33/22 केवी सब-स्टेशन साईंगलू में 22 केवी कोटला फीडर की विद्युत क्षमता बढ़ाने तथा नये जोओ स्विच लगाने स्थापित करने के कार्य के चलते 11 अक्तूबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल साईंगलू विनीत कुमार ने बताया कि इस कार्य के कारण कोट, डवाहन, तरयासल, माहन, कून, कडकोह, लागधार, सताहन, खलाणू, बरनोट कोटली, सुराडी, सैण ,सेतलर, हार्ट, साईंगलू तथा आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

भविष्य संवारने के गुर सीखेंगे विद्यार्थी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भविष्य सेतु कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जड़ोल में जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल करियर सेंटर मंडी की ओर से करियर काउंसलिंग एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर आयोजित किया गया। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों, सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रवक्ता जोगिंदर सिंह और भौतिक विज्ञान प्रवक्ता राम लाल ने भी करियर चयन को लेकर मार्गदर्शन दिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जानकारी साझा की। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के प्रतिनिधियों ने कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों से अवगत करवाया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

बुनाई-डिजाइनिंग प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र, शास्त्री नगर, कुल्लू में चार माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण 2 नवंबर, 2026 से शुरू होगा। प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य अभ्यर्थियों को बुनाई एवं डिजाइनिंग के कार्य में दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कार्यदिवसों में उपस्थिति के आधार पर 125 रुपये प्रतिदिन वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। इसमें महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी आयु, पहचान, नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता तथा बुनाई एवं डिजाइनिंग के अनुभव से संबंधित विवरण सहित आवेदन 29 अक्तूबर, 2026 को शाम 5 बजे तक बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र, शास्त्री नगर, कुल्लू में जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार 30 अक्तूबर, 2026 को प्रातः 11 बजे प्रशिक्षण केंद्र, शास्त्री नगर, कुल्लू में आयोजित होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र, शास्त्री नगर, कुल्लू के दूरभाष नंबर 01902-225915 पर संपर्क किया जा सकता है।

वीबीवाईएलडी क्विज में मंडी के 31,600 युवाओं ने लिया भाग, 998 अगले चरण में चयनित

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मेरा युवा भारत (मेरा भारत), जिला मंडी की ओर से आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (वीबीवाईएलडी) 2027 की ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में जिले के करीब 31,600 युवाओं ने भाग लिया। प्रथम चरण के बाद 998 प्रतिभागियों का चयन ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जिला युवा अधिकारी भारती मोंगरा ने बताया कि वीबीवाईएलडी युवाओं को राष्ट्र निर्माण, विकसित भारत के संकल्प और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। उन्होंने चयनित प्रतिभागियों से अगले चरण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की बड़ी भागीदारी उनकी नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ती रुचि को दर्शाती है। मेरा भारत कार्यालय की ओर से प्रतिभागियों को आगामी चरणों के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। चयनित युवाओं को 15 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य है।

टिहरा में पीडब्ल्यूडी कार्यालय का 4 घंटे किया घेराव

10 साल से बंद अस्पताल का मार्ग, किसान सभा ने किया प्रदर्शन, जेई के आश्वासन पर धरना समाप्त

रितेश चौहान, भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। हिमाचल किसान सभा ने टिहरा में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर करीब चार घंटे तक धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टिहरा अस्पताल के संपर्क मार्ग को बहाल करने, रेनशेल्टर का निर्माण पूरा करने और नए अस्पताल भवन का लोकार्पण जल्द करने की मांग उठाई। जेई के सड़क को दो दिन में बहाल करने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ।

किसान सभा के जिला सचिव एवं पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अस्पताल का संपर्क मार्ग पिछले दस वर्षों से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इस संबंध में सभा ने एसडीएम धर्मपुर को मांगपत्र सौंपकर 30 सितंबर तक सड़क बहाल करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन किया गया।



प्रदर्शनकारियों के कार्यालय पहुंचने पर एसडीओ और जेई मौजूद नहीं थे, जिस पर उन्होंने नारेबाजी की। बाद में जेई के पहुंचने और आश्वासन देने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ।

भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सड़क बंद होने से मरीजों, विशेषकर बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है। उन्होंने टिहरा बस स्टैंड के रेनशेल्टर का निर्माण जल्द पूरा करने की भी मांग की, जिसे तीन साल पहले गिराया गया था।

सभा ने अस्पताल के नए भवन का शीघ्र लोकार्पण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, लैब, एक्सरे और एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई। इसके अलावा बंद बस रूट बहाल करने तथा सार्वजनिक शौचालय की नियमित सफाई और रखरखाव का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन में सुरिंदर पठानिया, हरजीत सिंह, अरुण अत्री, प्रवीण चौहान, सत्तपाल चौहान, रुपलाल, प्रकाश सकलानी, मनोहर लाल, तारा चंद और अन्य किसान सभा कार्यकर्ता शामिल रहे।

नूरपुर में 116 ग्राम चरस व 10.47 ग्राम चिट्टे के साथ, तीन गिरफ्तार



अशोक कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में 116 ग्राम चरस और 10.47 ग्राम चिट्टा बरामद करने के साथ दो वाहनों को भी कब्जे में लिया है।

एएसपी धर्म चंद वर्मा ने बताया कि पहले मामले में सीआईए विंग की टीम को पलीण, जौंटा के समीप एनएच-154 पर एक वाहन में चरस होने की गुप्त सूचना मिली। तलाशी के दौरान स्टीयरिंग के नीचे छिपाई गई 116 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चंबा निवासी 33 वर्षीय काकू को गिरफ्तार कर वाहन नंबर एचपी 81-5184 कब्जे में लिया। इस संबंध में नूरपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दूसरे मामले में कंडवाल में नाकाबंदी के दौरान टाटा अल्ट्रोज कार से 10.47 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने राकेश कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार किया तथा कार नंबर एचपी 28सी-3330 जब्त की।

पुलिस ने दोनों मामलों में जांच जारी होने की बात कही है और लोगों से नशे की तस्करी संबंधी सूचना देने की अपील की है।

स्पीति पहुंचने पर जिप अध्यक्ष थिनले दिचेन का किया स्वागत

भारतेन्दु संवाददाता, काजा। जिला परिषद लाहौल-स्पीति की नवनिर्वाचित अध्यक्ष थिनले दिचेन के स्पीति आगमन पर टकचा में भारतीय जनता पार्टी स्पीति मंडल के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।



भाजपा स्पीति मंडल ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में थिनले दिचेन की जिम्मेदारी पूरे लाहौल-स्पीति जिले के विकास, जनकल्याण और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद है। मंडल के अनुसार, यह स्वागत केवल एक जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं, बल्कि स्पीति की जनता के विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्र के विकास की आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। जिला परिषद ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके माध्यम से स्थानीय लोगों की जरूरतों एवं समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाया जा सकता है।

भाजपा स्पीति मंडल ने विश्वास जताया कि थिनले दिचेन अपने कार्यकाल में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगी तथा लाहौल-स्पीति के समग्र विकास के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी। मंडल ने उन्हें पुनः बधाई देते हुए सफल एवं जनहितकारी कार्यकाल की कामना की।

वंदना ने मां अवाह देवी नवरात्र महोत्सव के लिए नड्डा दंपति को दिया निमंत्रण

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। मां अवाह देवी जी के पावन मंदिर परिसर में 11 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले तृतीय शारदीय दुर्गा पूजा एवं नवरात्र महोत्सव के लिए भाजपा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वंदना गुलेरिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, जगत प्रकाश नड्डा एवं उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा को सादर आमंत्रित किया।



◆ 11 से 20 अक्तूबर तक मां अवाह देवी मंदिर में होगा शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव

इस अवसर पर वंदना गुलेरिया ने नड्डा दंपति को मां अवाह देवी जी के पावन धाम में आयोजित होने वाले इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य मां अवाह देवी जी के प्रति श्रद्धा एवं आस्था को प्रगाढ़ करना तथा भारतीय धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। वंदना गुलेरिया ने मां अवाह देवी जी से नड्डा दंपति के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सुख-समृद्धि की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके आगमन से इस पावन आयोजन की गरिमा और बढ़ेगी।

मां अवाह देवी जी के पावन मंदिर परिसर में आयोजित होने वाला यह दस दिवसीय नवरात्र महोत्सव श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक उल्लास का प्रतीक होगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भक्तिमय वातावरण का सृजन किया जाएगा।

एम्स बिलासपुर और प्रदेश के तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन: राजीव बिंदल

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रस्तावित कुल्लू दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल कुल्लू पहुंचे। यहां पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बिंदल ने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा की तैयारियों की समीक्षा की तथा आयोजन को लेकर आवश्यक चर्चा की।

बैठक के दौरान राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर स्थित एम्स और प्रदेश में तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन हैं। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के प्रयासों को दिया। बिंदल ने कहा कि अटल टनल और लेह की ओर बन रही सुरंगों से हिमाचल प्रदेश की सामरिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।



कल पतलीकूहल में आयोजित होगी जनसभा

राजीव बिंदल ने बताया कि 11 अक्तूबर को पतलीकूहल में जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जनसभा के सफल आयोजन के लिए तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वह कुल्लू पहुंचे हैं। बैठक में जनसभा की रूपरेखा, आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। भाजपा की ओर से जनसभा को सफल बनाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि सड़क और सुरंग परियोजनाओं से प्रदेश में आवागमन सुगम हुआ है और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हुआ है। उन्होंने फोरलेन सड़क का उल्लेख करते हुए कहा कि कीरतपुर से कुल्लू तक का सफर अब करीब ढाई घंटे में पूरा किया जा रहा है। बेहतर सड़क संपर्क से प्रदेश के पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को लाभ मिल रहा है।

बारिश से किसान और पशुपालक परेशान

भागमल ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बरोट। मौसम के बदले मिजाज के कारण चौहार घाटी और छोटा भंगाल घाटी में रुक-रुककर हो रही बारिश ने किसानों और पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते जहां किसानों के खेतीबाड़ी संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, वहीं खेतों और घासणियों में काटकर रखी गई घास भी गीली हो रही है।

दोनों घाटियों के लोग सर्दियों में अपने पालतू पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए नवंबर से मार्च तक इस्तेमाल होने वाली घास का भंडारण करते हैं। ऐसे में लगातार बारिश के कारण काटी गई घास के खराब होने और खेतों में सड़ने का खतरा बढ़ गया है। लोग घास को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल डालकर सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि मौसम साफ न होने से खेतीबाड़ी के कार्यों में देरी हो रही है। इससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं, दोनों घाटियों की ऊंची पर्वतमालाओं में भारी हिमपात होने से दुर्गम गांवों में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन पर मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है।

कार्यक्रम धनोटू में किसानों और बाजार प्रतिनिधियों के बीच संवाद, बेहतर विपणन पर मंथन

किसानों को दिया बाजारोन्मुख खेती का संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-II) की जायका इकाई मंडी की ओर से कृषि उपज बाजार समिति के मार्केट यार्ड धनोटू में लोकल मार्केट स्टेकहोल्डर्स फोरम का आयोजन किया गया। स्मॉलहोल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन अप्रोच के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वहाव सिंचाई योजना रोपा से नलवारी उपपरियोजना के करीब 30 लाभार्थी किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप फसल उत्पादन, कृषि उत्पादों के विपणन और बेहतर दाम प्राप्त करने के लिए जागरूक करना था।



कार्यक्रम के दौरान किसानों ने बाजार से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान सब्जियों की बाजार में मांग, उपभोक्ताओं की पसंद, फसलों के विपणन और कृषि उत्पादों को बेचने में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही किसानों को उत्पादन के साथ-साथ बाजार की जरूरतों को समझने और उसके अनुसार खेती की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, कृषि मशीनरी डीलरों और अन्य प्रतिनिधियों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में उपलब्ध उत्पादों, संसाधनों और सुविधाओं की जानकारी दी गई।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-II), जायका मंडी के खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश जसवाल ने कहा कि स्मॉलहोल्डर हॉर्टिकल्चर एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन अप्रोच का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक 'उगाओ और बेचो' की सोच से आगे बढ़ाकर 'बेचने के लिए उगाओ' की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले बाजार की मांग, उपभोक्ताओं की पसंद और प्रचलित कीमतों का आकलन करना चाहिए तथा इसके बाद उसी के अनुसार फसल उत्पादन की योजना बनानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसानों और बाजार से जुड़े हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने से कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों की आय में स्थायी सुधार लाने और बागवानी एवं कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

इस अवसर पर डॉ. अनुपमा, बागवानी विकास अधिकारी मंडी, भूपेंद्र ठाकुर, कृषि विपणन सचिव मंडी, रोहित गलोटिया, इफको इंचार्ज, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक धनोटू के प्रबंधक, कृषि उत्पादक संगठन मंडी के अध्यक्ष टंकेन्दर ठाकुर, हंस राज वालिया, कृषि विकास अधिकारी, अमित, कृषि विशेषज्ञ, नीरज भारद्वाज और रवीना नायक, कृषि प्रसार अधिकारी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को बाजारोन्मुख खेती अपनाने, विपणन संबंधी जानकारी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का संदेश दिया गया।

बिलिंग में सुपर-7 क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, नशामुक्त समाज का दिया संदेश



भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। ग्राम बिलिंग में यंग फार्मर क्लब बिलिंग की ओर से सुपर-7 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद उपाध्यक्ष लाहौल-स्पीति सुरेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। डीएसपी के.डी. शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

सुरेश कुमार ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि खेल गतिविधियों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है। उन्होंने नशे के खिलाफ समाज के सभी वर्गों से एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया। डीएसपी के.डी. शर्मा ने भी युवाओं को खेलों और फिटनेस से जोड़ने पर जोर दिया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जल शक्ति विभाग केलांग और स्नो पीक पुलिस टीम के बीच हुआ। जल शक्ति विभाग ने सात ओवर में 53 रन बनाए, जबकि पुलिस टीम 36 रन ही बना सकी। इस तरह जल शक्ति विभाग केलांग ने जीत दर्ज की।

दूसरे मुकाबले में एचआरटीसी केलांग ने वाईएफसी पयूकर के सामने 56 रनों का लक्ष्य रखा। समाचार लिखे जाने तक पयूकर की टीम तीन ओवर में 16 रन बनाकर तीन विकेट गंवा चुकी थी।

आयोजकों ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना, फिटनेस को बढ़ावा देना और नशामुक्त समाज का संदेश देना है।

हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 55,103 करोड़ का निवेश : जेपी नड्डा

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में सड़क, रेल, स्वास्थ्य, ऊर्जा और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार से लंबित कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के विकास के लिए व्यापक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।

प्रेसवार्ता में नड्डा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 25 राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल नेटवर्क 2,592 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की परियोजनाओं में 55,103 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में सड़कें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, बागवानी और आपदा प्रबंधन के लिए जीवनरेखा हैं। उन्होंने कीरतपुर-मनाली, पठानकोट-मंडी, परवाणू-शिमला-रोहड़ू



और शिमला-मटौर जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। कीरतपुर-मनाली मार्ग के पंडोह-कटौला खंड को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परवाणू-सोलन खंड सितंबर 2027 और शिमला बाईपास सितंबर 2028 तक पूरा करने की अपेक्षा है। पठानकोट-मंडी फोरलेन परियोजना के विभिन्न हिस्सों को वर्ष 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रेल संपर्क की समीक्षा के दौरान भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन और चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना पर चर्चा हुई। नड्डा ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी समय पर उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल संपर्क से उद्योग, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, ऊना स्थित पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट स्वीकृत होने के साथ आधुनिक सुविधाओं, जांच सेवाओं और विशेषज्ञ उपचार की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, रेणुकाजी बांध, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना, जलविद्युत परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी योजनाओं की समीक्षा की गई।

मार्च 2027 तक पूरी हों नौ सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 26,506 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का उल्लेख करते हुए नड्डा ने प्रथम चरण की शेष नौ सड़कों को मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत स्वीकृत 25 कार्यों के टेंडर शीघ्र आवंटित करने पर भी जोर दिया।

नड्डा ने कहा कि विकास कार्यों की सफलता का आकलन परियोजनाओं के पूरा होने और आम जनता को मिलने वाले वास्तविक लाभ से होना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में मंडी की सांसद कंगना रनौत, विधायक रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण चंद चंदेल, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रता संख्या सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सांसद के बयान से खींची राजनीति की शमशीरें!

सुखराम परिवार ने सांसद कंगना रनौत को घेरा, बयानबाजी पर कसे तंज

रूप लाल कौंडल, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल के कारण केंद्र पर बोझ पड़ने के बयान पर मंडी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ राजनैतिक घमासान शुरू हो गया है। स्वर्गीय पंडित सुखराम के परिवार ने सांसद के खिलाफ एक बार फिर खुलेआम विरोध करके उन्हें हाशिए धकेलने का प्रयास किया गया। उधर, सांसद के खिलाफ परिवार के सार्वजनिक रूप से विरोध के रवैय्ये के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री को अनुशासन की नसीहत देनी पड़ गई है। बहरहाल सांसद और पंडित सुखराम परिवार के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है।



◆ अनुशासन की अनदेखी पर पूर्व सीएम की नसीहत

हिमाचल और मंडी जिला में विकास के कार्यों को लेकर सांसदों पर निष्क्रियता बारे आरोप लगाते रहे पंडित सुखराम के बेटे एवं वर्तमान में सदर से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा नित नये बयान देकर कंगना रनौत को निशाने पर ले रहे है। बीते दिनों उन्होंने मंडी सदर से जुड़ी कुछ परियोजनाओं को पूरे करने के लिए सांसद पर सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके इस रवैय्ये पर टिप्पणी करते हुए हाल ही में उन्हें इस तरह के मामले सार्वजनिक रुप से न उछाल पर पार्टी के भीतर उचित मंच पर उठाने के नसीहत दी थी। लेकिन राजनीतिक रूप से अलग पहचान रखने वाले इस परिवार ने मंडी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मुद्दों पर विरोध करने का क्रम यहीं नहीं रोका बल्कि हाल ही में कंगना रनौत ने जब कांग्रेस सरकार को घेरते हुए हिमाचल की वजह से केंद्र पर बोझ बढ़ने की बात की तो फिर से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय पंडित सुखराम की राजनैतिक विरासत संभाल रहे उनके पोते ने आश्रय शर्मा ने सांसद के इस बयान पर कहा कि हिमाचल केन्द्र पर बोझ नहीं बल्कि देश के लिए अमूल्य है।

काबिलेगौर है कि आश्रय शर्मा इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हार के बाद आश्रय शर्मा बीजेपी में शामिल हो गये। उनके पिता अनिल शर्मा भी वर्तमान में भाजपा के टिकट पर सदर मंडी से विधायक हैं। ऐसे में इस परिवार द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ घेराबंदी किया जाना एक बड़े राजनैतिक लक्ष्य को भेदने की दिशा में उठाया कदम भी हो सकता।

गौर रहे कि भाजपा के भीतर अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधियों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की परंपरा कम ही रही है। ऐसे में पार्टी गाइडलाईन को नजरअंदाज कर खुलेआम घेराबंदी किया जाने के प्रयास को महज इत्तेफाक समझ कर अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस घेराबंदी के परिणाम भविष्य में देखने को मिले इस बात की आशंका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।

न्यूज ब्रीफ

कोठी निवासी पूर्व हवलदार अर्जुन सिंह का निधन, सैनिक सम्मान से दी अंतिम विदाई

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। कोठी निवासी हवलदार अर्जुन सिंह का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने आर्मी मेडिकल कोर रेजिमेंट में 24 वर्ष तक



अपनी सेवाएं दी। उनके निधन पर उनके बेटे नायब सूबेदार सुशील कुमार ने मुखाग्नि दी तथा एक्स सर्विसमैन लीग, सरकाघाट ने रीत चढ़ा कर उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की। इस मौके पर एक्स सर्विसमैन लीग, सरकाघाट के पदाधिकारियों में चेयरमैन कैप्टन प्यार चन्द बन्याल, सचिव कैप्टन बलदेव राज, सूबेदार मेजर विजय चौहान, सूबेदार मेजर विजय ठाकुर, नायब सूबेदार गुरदीप सिंह, नायब सूबेदार अजय सिंह, लीग के कई सदस्य तथा स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। क्षेत्र के लोगों में बिहारी लाल, श्रवण भारद्वाज, विजय कुमार व सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चन्द भारद्वाज ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया तथा परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की।

प्रियानी शर्मा अध्यक्ष, तृप्ता बनीं उपाध्यक्ष

भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। राजकीय महाविद्यालय रिवालसर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केंद्रीय छात्र संघ (सीएससीए) का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। छात्र संघ सलाहकार समिति की संयोजक प्रो. अंजलि परमार ने बताया कि कार्यकारिणी का गठन विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों, मेरिट और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। कार्यकारिणी में बीए तृतीय वर्ष की प्रियानी शर्मा को अध्यक्ष, बीकॉम तृतीय वर्ष की तृप्ता देवी को उपाध्यक्ष, बीए द्वितीय वर्ष के नीतिश कुमार को सचिव और बीए प्रथम वर्ष की प्रिया को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों के हितों और कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह में प्राध्यापक, सलाहकार समिति के सदस्य और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मंडी के सेरी मंच पर सेवा सेतु शिविर 13 से

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड की ओर से मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर 13 से 15 अक्टूबर तक तीन दिवसीय 'सेवा सेतु' जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी और मौके पर पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। उप मुख्य अभियंता अरुण शर्मा ने बताया कि शिविर में तकनीकी सहायक, सूचीबद्ध सोलर वेंडर और भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उपभोक्ता सोलर प्लांट की लागत, ऋण, सब्सिडी, पात्रता और नेट मीटरिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शिविर प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। उपभोक्ताओं से नवीनतम बिजली बिल और आधार कार्ड साथ लाने की अपील की गई है। विभाग ने पात्र लोगों से शिविर का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा अपनाने और बिजली बिल में बचत करने का आग्रह किया है।

एआई-करियर संभावनाओं पर किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। रबीन्द्रनाथ टैगोर राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट के करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की ओर से विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। चितकारा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स गौतम सुशांत ने 'स्नातक विद्यार्थियों के लिए भविष्य में करियर की संभावनाएं' विषय पर विचार साझा किए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते महत्व और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करियर में सफलता के लिए शैक्षणिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल, प्रभावी संचार और आत्मविश्वास जरूरी हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के माध्यम से अनुभव हासिल करने के लिए प्रेरित किया। व्याख्यान के दौरान उन्होंने एमबीए कार्यक्रमों में करियर की संभावनाओं पर भी चर्चा की और विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। चितकारा विश्वविद्यालय के सीनियर मैनेजर शुभम जैन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्लेसमेंट सेल की संयोजक सहायक आचार्य अंजू कुमारी ने आभार व्यक्त किया।

यूनिटी स्कूल रिवालसर में मनाया वायुसेना दिवस

योगराज शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, रिवालसर। यूनिटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिवालसर में भारतीय वायुसेना दिवस पर विशेष प्रातःकालीन सभा आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को वायुसेना के गौरवशाली इतिहास, वीरता, अनुशासन और राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, तेजस और मिराज-2000 जैसे लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे, चिनूक और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की विशेषताओं पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने आधुनिक सैन्य तकनीक और वायुसेना की कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को महिला लड़ाकू पायलटों की उपलब्धियों से परिचित करवाया गया। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह के योगदान का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में देशभक्ति, अनुशासन, साहस और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करना रहा।

बिलासपुर के युवाओं को यूएई में नौकरी का मौका

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर बिलासपुर के माध्यम से युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रोजगार का अवसर मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता के अनुसार, वर्तिव गल्फ एलएलसी में इलेक्ट्रीशियन और फिटर के पदों पर भर्ती होगी। आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 20 से 45 वर्ष आयु के फ्रेशर और अनुभवी युवा आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 1,100 से 1,300 एईडी मासिक वेतन के साथ नियमानुसार अन्य सुविधाएं मिलेंगी पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर, 2026 है। साक्षात्कार 16 और 17 अक्टूबर को होंगे। इच्छुक युवा । अधिक जानकारी के लिए 01978-222450 पर संपर्क करें।

जलवायु वित्त दान नहीं, विकसित देशों का दायित्व : अनुराग

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व जलवायु अनुकूलन के लिए वैश्विक सहयोग की अपील

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने तंजानिया के अरूशा में आयोजित अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) महासभा में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त उपलब्ध करवाना उनका दायित्व है, न कि दान या परोपकार।

नेपाल की संसद के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में ठाकुर ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों सहित संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चरम मौसमी घटनाएं, जैव विविधता का नुकसान, खाद्य एवं जल असुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरे गंभीर वैश्विक चुनौतियां बन चुके हैं। इनका प्रभाव विकासशील देशों और कमजोर समुदायों पर अधिक पड़ रहा है। भारत के लिए जलवायु अनुकूलन सतत विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। अनुराग ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय और पेरिस समझौते का उल्लेख करते हुए विकसित देशों से अपनी जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताएं पूरी करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वैश्विक अनुकूलन आयोग के आकलन के अनुसार, जलवायु अनुकूलन उपायों में 1.8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश लगभग 7.1 ट्रिलियन डॉलर का लाभ दे सकता है। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे, कृषि और जल संसाधन प्रबंधन में निवेश को महत्वपूर्ण बताया। हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए ठाकुर ने कहा कि हिमालयी क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने सांसदों से विधायी निगरानी, पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेही मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि वैश्विक सहयोग से वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं टिकाऊ भविष्य बनाया जा सके।



वोट चोरी के आरोपों पर पांवटा साहिब में कांग्रेस का हल्ला बोल

भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसजनों ने शहर में रोष रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और नारेबाजी करते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया।

प्रदर्शन की शुरुआत पांवटा साहिब स्थित विश्राम गृह से हुई। यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन के चलते शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं।

इस प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, सिरमौर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एम.आर. भारद्वाज, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद परमार और पांवटा साहिब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरप्रीत सिंह रतन सहित पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की।

कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोपों को उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवाया।

विश्राम गृह से शुरू हुई रैली पांवटा साहिब के मुख्य बाजार से होकर गुजरी और एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगों और विरोध को सार्वजनिक रूप से सामने रखा। प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया।

रखोटा-माहुनाग-चंदेश सड़क चार साल से बदहाल, पैचवर्क 15 दिन में उखड़ा

भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। उपमंडल सरकाघाट के अंतर्गत रखोटा-माहुनाग-चंदेश सड़क की खस्ताहालत से भदरोता क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले चार वर्षों से सड़क की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह मार्ग जाहू, बिलासपुर, शिमला, बद्दी और चंडीगढ़ आने-जाने के लिए महत्वपूर्ण है। लोगों के अनुसार, करीब दो महीने पहले सड़क पर एक किलोमीटर तक पैचवर्क किया गया था, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी खराब रही कि 15 दिनों के भीतर ही पैचवर्क उखड़ने लगा। इससे वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय निवासी विनीत ठाकुर, पवन कुमार, राकेश शर्मा, संतोष, सुनील और राजेश ने विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत करवाने तथा पैचवर्क की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है।

इस संबंध में सहायक अभियंता सरकाघाट राज कुमार ने बताया कि मामला उनके ध्यान में है। जल्द ही मौके का निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी और सड़क की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

पार्बती-III पावर स्टेशन कुल्लू अस्पताल को देगा 15 लाख का लैप्रोस्कोपिक सिस्टम

धनेश गौतम , कुल्लू। एनएचपीसी के पार्बती-III पावर स्टेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एंड एसडी) के तहत जिला कुल्लू की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू को लैप्रोस्कोपिक सिस्टम उपलब्ध करवाने के लिए 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस संबंध में शुक्रवार, 9 अक्तूबर को पार्बती-III पावर स्टेशन के प्रशासनिक भवन बिहाली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पावर स्टेशन प्रमुख सुधीर कुमार की उपस्थिति में पार्बती-III पावर स्टेशन की ओर से समूह वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन) जीटीएस राजू और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की ओर से चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सपना शर्मा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर महाप्रबंधक (यांत्रिक) रंजीत कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरिता खुराना तथा उप महाप्रबंधक (वित्त) पवन कुमार राजपूत भी उपस्थित रहे।



एनएचपीसी की सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा

एनएचपीसी की ओर से सीएसआर एवं सतत विकास के तहत उठाया गया यह कदम स्थानीय समुदाय के कल्याण और स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के अधिकारियों ने इस सहयोग को स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए उम्मीद जताई कि नई सुविधा से जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा।

पार्बती-III पावर स्टेशन की इस पहल का उद्देश्य जिला कुल्लू और आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहयोग करना है। लैप्रोस्कोपिक सिस्टम की उपलब्धता से अस्पताल में दूरबीन के माध्यम से की जाने वाली शल्य चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे मरीजों को आधुनिक चिकित्सा तकनीक का लाभ उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।

शाख मंडी महोत्सव में जयराम ठाकुर ने सांस्कृतिक संध्या का किया शुभारंभ

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सोसाइटी ऑफ हिमाचल आर्ट, कल्चर, नॉलेज एंड हेरिटेज (शाख) की ओर से आयोजित शाख मंडी महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने किया। उन्होंने आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रदेश की कला, संस्कृति और लोक परंपराओं के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, मंडी नगर निगम की महापौर सुमन ठाकुर और भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार दीपक चौहान और गीता भारद्वाज ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं, राजेश कुमार, संजय कुमार, राजेश जजुआ और विवेक शर्मा ने भी गीतों से समां बांधा। खचाखच भरे पंडाल में दर्शक कलाकारों की प्रस्तुतियों पर झूमते नजर आए। युवाओं और बच्चों को प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के उद्देश्य से जूनियर एवं सीनियर वर्ग की नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें 14 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रसिद्ध कथक नर्तक दिनेश गुप्ता, सुमन पंडित और सुनील ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने हिमाचल फिल्म नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई थी। उन्होंने सत्ता में आने पर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने की बात कही। उनके अनुसार, फिल्म नीति के माध्यम से प्रदेश के फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर हिमाचल की लोक कला एवं संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई जा सकती है।

हिमाचल की नौ विभूतियों को शाख सम्मान

महोत्सव के दौरान शाख की ओर से साहित्य, कला, संगीत, खेल और लोक संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तित्वों में दिवंगत डॉ. नीलमणि उपाध्याय, नरेश पंडित, देवेंद्र नाथ कैथ, सोम देव कश्यप, रविकांता कश्यप, अमित भाटिया, इंद्रराज इंदु, पोमिला ठाकुर और जगदीश मांडवी शामिल रहे। इन विभूतियों ने साहित्य, इतिहास, चित्रकला, खेल, संगीत, नाटक और लोक संस्कृति के माध्यम से हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। शाख का यह प्रयास प्रदेश की प्रतिभाओं और उनके योगदान को पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रहा।



मंथन आध्यात्मिक मूल्यों व वैज्ञानिक सोच से बनेगा विकसित भारत : कटारिया

एनआईटी हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ का आगाज

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में तीन दिवसीय शिक्षा महाकुंभ 6.0 का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस का मुख्य विषय 'आध्यात्मिक भारत-विकसित भारत' रहा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजन में शिक्षा, अध्यात्म, विज्ञान, अनुसंधान और उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. एचएम सूर्यवंशी ने अतिथियों और देशभर से आए शिक्षाविदों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को एक मंच पर लाना विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

विशेष पैनल परिचर्चा में स्वामी तन्महिमानंद, डॉ. के. वासुदेव राव, डॉ. अर्चना संतोष ननोटी, बनवीर सिंह और प्रो. वीर सिंह रांगड़ा ने आध्यात्मिकता, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे।



राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा उसकी पहचान और शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिकता, संस्कार, संवेदनशीलता, कर्तव्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना भी होना चाहिए। उन्होंने समग्र शिक्षा की इस अवधारणा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप बताया। महाकुंभ के पहले दिन वाइस चांसलर एवं डायरेक्टर कॉन्क्लेव में विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 45 कुलपतियों एवं निदेशकों ने हिस्सा लिया। वहीं, साइंटिस्ट कॉन्क्लेव में लगभग 40 वैज्ञानिकों और शोध विशेषज्ञों ने अनुसंधान, विज्ञान तथा नवाचार से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

इस बार स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी शुरू किया गया, जिसमें करीब 38 स्टार्टअप्स और 11 निवेशकों ने भाग लिया। स्टार्टअप्स को निवेश के अवसरों के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन और मेंटॉरशिप उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। इस दौरान एनआईटी हमीरपुर और विभिन्न संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किए गए। आयोजन में विद्यार्थियों की लगभग 85 परियोजनाएं प्रदर्शित की गईं। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के शोध एवं नवाचार आधारित प्रकल्प शामिल रहे। इसके अलावा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े करीब 35 प्रदर्श भी लगाए गए।

प्रथम दिवस का समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ। आगामी दिनों में भी विभिन्न राष्ट्रीय कॉन्क्लेव, शोध सत्र, विशेषज्ञ परिचर्चाएं, प्रदर्शनियां और विद्यार्थी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महाकुंभ का उद्देश्य शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए विकसित भारत के संकल्प पर सार्थक संवाद को आगे बढ़ाना है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली बनाकर दिया राष्ट्रभक्ति का संदेश



भारतेन्दु संवाददाता, शाहपुर। भाजपा शाहपुर मंडल की ओर से 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री कमल कुमार शर्मा रहे। इस दौरान महिलाओं ने रंगोली बनाकर कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक राकेश

लॉर बोउलेउ की फिटनेस लाजवाब

फ्रांस की लॉर बोउलेउ शानदार खिलाड़ी हैं और इनकी फिटनेस लाजवाब है। वे नेशनल टीम में डिफेंडर के तौर पर खेलती हैं। महज 1.6 मीटर लंबी होने के बावजूद, इस महिला खिलाड़ी का चेहरा आकर्षक है और शरीर सुगठित है।



स्पोर्ट्स विंडो

मेगन शट वनडे में 150 विकेट लेने वाली तीसरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

एजेंसी, ब्रिसबेन। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट ने शुक्रवार को बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ पहले एकदिवसीय



अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 150 विकेट पूरे कर लिए। वह महिला वनडे क्रिकेट में इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया की तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। एलन बॉर्डर फील्ड में खेले गए तीन मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 33 वर्षीय शट को 150 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए दो विकेट की जरूरत थी। उन्होंने श्रृंखला की पहली ही गेंद पर फरगाना हक को आउट किया और फिर तीसरे ओवर में शर्मिन सुल्ताना का विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल कर ली। शट ने फरगाना को शानदार गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराया। गेंद पिच पर पड़ने के बाद अंदर की ओर आई और बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़ी फीबी लिचफील्ड के हाथों में चली गई। इसके बाद तीसरे ओवर में शट की अंदर की ओर स्विंग होती गेंद शर्मिन सुल्ताना के बल्ले को चकमा देते हुए उनके पैड पर लगी और अंपायर ने उन्हें पगबाधा आउट करार दिया।

मानुष शाह और मानव ठक्कर चीन स्मैश के सेमीफाइनल में हारे

एजेंसी, बीजिंग। भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर को शुक्रवार को विश्व टेबल टेनिस स्मैश प्रतियोगिता 2026 के पुरुष युगल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओह जुनसुंग ने भारतीय जोड़ी को सीधे गेमों में 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

हिमाचल की पुरस्कार सूची से ऋतु नेगी का नाम हटाने पर विवाद

प्रदेश सरकार ने एक करोड़ के नकद पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों की सूची से अंतिम समय में हटा दिया था नेगी का नाम

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ भाजपा ने फैसले को हिमाचल की बेटी का अपमान दिया करार

अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान और जापान में हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की सदस्य ऋतु नेगी का नाम हिमाचल प्रदेश सरकार की पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों की सूची से हटाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ऋतु हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की रहने वाली हैं और उनकी शादी हरियाणा के पानीपत में हुई है। हिमाचल सरकार ने एक करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों की सूची से अंतिम समय में उनका नाम हटा दिया, जिससे ऋतु और उनका परिवार निराश है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एशियाई खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्य रही हिमाचल प्रदेश की तीन खिलाड़ियों पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर तथा भारतीय महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर के लिए एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की थी।

वहीं, ऋतु के पिता भवन सिंह नेगी ने सवाल उठाया कि क्या किसी लड़की की शादी दूसरे राज्य में हो जाने से वह अपने गृह राज्य की बेटी नहीं रह जाती। उन्होंने बताया कि ऋतु को 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद हिमाचल सरकार से नकद पुरस्कार मिला था, जबकि उनकी शादी हरियाणा में हुई थी।

उधर, पुरस्कारों की सूची से ऋतु का नाम हटाए जाने के मामले को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के गौरव और राज्य की बेटी के सम्मान से जोड़ दिया है। शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक और भाजपा के राज्य प्रवक्ता बलदेव सिंह तोमर ने कहा कि हिमाचल सरकार ने न केवल हिमाचल की एक बेटी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि पुरस्कार सूची से ऋतु का नाम हटाकर राज्य के गौरव को भी धूमिल किया है। उन्होंने हिमाचल सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा और 'हिमाचल की बेटी' को उचित सम्मान देने की अपील की।

ऋतु ने सरकार के इस कदम को बेहद अपमानजनक बताया



ऋतु नेगी ने मीडिया से कहा, ''एक सप्ताह पहले तक मैं हिमाचल की बेटी थी और मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर बधाई संदेश साझा किया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने मुझे बधाई देने के लिए फोन किया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि दो दिन में अचानक क्या बदल गया।' ऋतु ने कहा कि एक ऐसी खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जिसने लगातार तीन एशियाई खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और दो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। उन्होंने बताया कि वह भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने घरेलू प्रतियोगिताओं में हरियाणा का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने पूछा, 'मेरे करियर के इस पड़ाव पर हिमाचल प्रदेश सरकार मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है।'

हिमाचल सरकार को हरियाणा सरकार के फैसले का इंतजार

हिमाचल की कांग्रेस सरकार के सूत्रों ने बताया कि सरकार इस मामले पर हरियाणा सरकार के रुख पर बारीकी से नजर रख रही है। हरियाणा सरकार ने अभी तक ऋतु के लिए किसी भी प्रकार के नकद पुरस्कार की घोषणा नहीं की है, इसलिए हिमाचल सरकार बाद में निर्णय ले सकती है। हिमाचल प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि नकद पुरस्कार पाने वाले हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की सूची में बदलाव का कारण उन्हें पता नहीं है और वह इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे।

एशियन गेम्स में भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

15 स्पर्धाओं में लिया भाग; छह स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य पदक जीते

एजेंसी, नई दिल्ली



भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुए आइची-नागोया एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 पदक जीते। भारत के 501 सदस्यीय दल में सेना के 62 खिलाड़ी शामिल थे जिन्होंने 15 स्पर्धाओं में भाग लिया तथा छह स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य पदक जीते। भारत ने कुल 85 पदक जीते जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, ''भारत के कुल पदकों में से 23.52 प्रतिशत पदक सेना के खिलाड़ियों ने जीते। उन्होंने देश के 85 पदकों में से 20 पदक जीते। उनके छह स्वर्ण पदक भारत के 21 स्वर्ण पदकों का 29 प्रतिशत है।'

सेना के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया उनमें नायब सूबेदार नीरू ढांडा प्रमुख हैं, जिन्होंने ट्रैप निशानेबाजी में दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। लंबी दूरी के धावक नायब सूबेदार गुलवीर सिंह ने भी दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया। गुलवीर ने किसी एक एशियाई खेल में तीन व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बनकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में सेना के चार निशानेबाजों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने तीन स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। भारतीय सेना के खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी में एक स्वर्ण और दो कांस्य पदक सहित तीन पदक जीते। सेना के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और एशियाई खेलों के रिकॉर्ड भी बनाए। हवलदार सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में दो घंटे, 11 मिनट, 37 सेकेंड के समय के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सूबेदार धीरज बोम्मादेवरा ने पुरुषों की रिकर्व तीरंदाजी में 698 के स्कोर के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। हवलदार कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में 484.6 के स्कोर के साथ जबकि नीरू ने महिलाओं की ट्रैप निशानेबाजी में 118 अंक के साथ एशियाई खेलों के नए रिकॉर्ड बनाए। रोइंग में नायब सूबेदार सलमान खान ने पुरुषों की डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत के लिए एशियाई खेलों का पहला पदक जीता।

महिला खिलाड़ियों ने सेना के कुल पदकों में 15 प्रतिशत और स्वर्ण पदकों में 33 प्रतिशत का योगदान दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है, 'एशियाई खेल 2026 में सेना का प्रतिनिधित्व भी काफी बढ़ गया है। भारतीय दल में सेना के खिलाड़ियों की संख्या 12.6 प्रतिशत थी, जबकि 2023 के एशियाई खेलों में यह नौ प्रतिशत थी।' इसके अनुसार, 'सेना के 62 खिलाड़ियों में नौ महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीता।'

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान ने वापस लिया नाम

एजेंसी, इस्लामाबाद

◆ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने की मांग खारिज होने पर लिया फैसला

भारत में 27 अक्टूबर से होने वाली एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने दोनों देशों के बीच जारी राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए अपने मुकाबले तटस्थ स्थल पर कराने की मांग की थी। हालांकि, भारत ने



टूर्नामेंट को किसी दूसरे देश में आयोजित कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। छह टीमों के इस टूर्नामेंट के मुकाबले पांच नवंबर तक जालंधर और मोहाली में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान के हटने से प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। इस बीच, एक अक्टूबर को जापान के काकामीगहारा में एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी

खिलाड़ियों की सुरक्षा एवं सम्मान को बताया सर्वोच्च

पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन से अपने मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध किया था। फेडरेशन का कहना था कि मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान प्राथमिकता है। पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि उसकी टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से जुड़ी किसी भी टीम, यहां तक कि भारत के खिलाफ भी खेलने को तैयार है, लेकिन मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि पाकिस्तान की टीम का भारत दौरा उसकी सरकार से मंजूरी मिलने पर निर्भर था। अब एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की गैरमौजूदगी के बीच बांग्लादेश को मौका मिलने से प्रतियोगिता में नई चुनौती देखने को मिलेगी।

सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने आई थीं।

भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने मुकाबले में अपनी बढ़त साबित की।

भारत का टूर्नामेंट का वेन्यू बदलने से इनकार

भारत ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की और टूर्नामेंट को तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित करने का रुख अपनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। एशियन हॉकी फेडरेशन ने उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल किया।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बढ़ा ईंधन शुल्क

एजेंसी, नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण विमानन ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम पिछले एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। बढ़ती लागत के दबाव के बीच एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और इंडिगो जैसी प्रमुख विमानन कंपनियों ने ईंधन अधिभार में बढ़ोतरी की है। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। संशोधित शुल्क के अनुसार, घरेलू उड़ानों में 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 375 से 400 रुपये, जबकि 2,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर 1,200 से 1,300 रुपये तक अतिरिक्त ईंधन अधिभार लिया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी गंतव्य के आधार पर शुल्क बढ़ाया गया है।

अक्टूबर में एपल के नए मैकबुक और आईपैड मिनी पर होगी नजर

एजेंसी, मुंबई। एपल अक्टूबर में दो बड़े उत्पाद कार्यक्रमों के जरिए नए उपकरण बाजार में उतारने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 अक्टूबर को कंपनी स्मार्ट होम उत्पाद पेश कर सकती है, जबकि महीने के आखिरी सप्ताह में मैकबुक और आईपैड के नए मॉडल सामने आ सकते हैं। संभावित रूप से 27 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में एपल का पहला टचस्क्रीन मैकबुक प्रो, नए मैकबुक और आईमैक मॉडल तथा नया आईपैड मिनी पेश किया जा सकता है।

◆ टचस्क्रीन मैकबुक से स्मार्ट होम हब तक एपल की नई तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, टचस्क्रीन मैकबुक प्रो में ओएलईडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें आईफोन की तरह डायनेमिक आइलैंड सुविधा भी मिल सकती है, जो सूचनाओं, कॉल और अन्य गतिविधियों को स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में प्रदर्शित करती है। नए मैकबुक प्रो और आईमैक में एम6 चिपसेट मिलने की संभावना है। कंपनी का ध्यान वीडियो निर्माण, फोटो संपादन और संगीत निर्माण से जुड़े पेशेवरों पर रहेगा। नए आईपैड मिनी में पहली बार ओएलईडी स्क्रीन दी जा सकती है।

एपल के नए उत्पादों पर टिकीं निगाहें

एपल ने आईपैड मिनी को पिछली बार 2024 में अद्यतन किया था। इससे पहले 13 अक्टूबर के कार्यक्रम में डिस्प्ले वाला स्मार्ट होम हब, नया होमपॉड मिनी और अद्यतन एपल टीवी पेश किए जाने की चर्चा है। इन उपकरणों को नियंत्रित करने में सिरी की अहम भूमिका हो सकती है। नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन टर्नस के नेतृत्व में यह कंपनी का पहला बड़ा उत्पाद पेश करने का चरण होगा। हालांकि, इन उत्पादों और कार्यक्रमों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

रेनो डस्टर स्ट्रांग हाइब्रिड 17 अक्टूबर को होगी पेश, बुकिंग शुरू

एजेंसी, मुंबई। रेनो ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय इकाई रेनो इंडिया ने अपनी नई एसयूवी डस्टर स्ट्रांग हाइब्रिड ई-टेक



नई रेनो डस्टर

160 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इसे आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर को बाजार में पेश करेगी। ग्राहक 21 हजार रुपये में इस गाड़ी की बुकिंग करा सकते हैं। नई रेनो डस्टर में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 किलोवाट आवर की बैटरी दी गई है। यह हाइब्रिड प्रणाली संयुक्त रूप से 160 पीएस की शक्ति प्रदान करती है। कंपनी के अनुसार, गाड़ी का माइलेज 29 किलोमीटर प्रति लीटर है। ऐसे में यह उन ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकती है, जो बेहतर माइलेज के लिए डीजल वाहन पसंद करते हैं। इसमें इंटेलिजेंट मल्टी-मोड ट्रांसमिशन दिया गया है, जो ड्राइविंग की परिस्थितियों के अनुसार पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच अपने आप बदलाव करता है। यह प्रणाली गति कम करने और ब्रेक लगाने के दौरान ऊर्जा बचाने में भी मदद करती है।

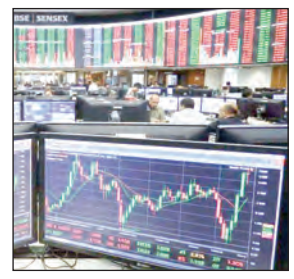
सेंसेक्स 879 और निफ्टी 288 अंक चढ़ा

विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच शेयर बाजार में जोरदार तेजी

एजेंसी, मुंबई

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 9 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,472 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 289 अंक चढ़कर 22,520 के स्तर पर पहुंच गया। आईटी और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बाजार में तेजी के पीछे तीन प्रमुख कारण रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान पर हमला नहीं करने के बयान से पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ी।

इसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपये की मजबूती ने भी निवेशकों का भरोसा



बढ़ाया। ब्रेंट क्रूड 103 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 96.65 प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शेयर करीब पांच प्रतिशत चढ़कर 2,171 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 13,884 करोड़ रुपये हो गया।

घरेलू संस्थानों ने संभाला बाजार

हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। गुरुवार को उन्होंने करीब 12,944 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। पिछले 30 दिनों में विदेशी निवेशकों की शुद्ध बिकवाली लगभग 82,170 करोड़ रुपये रही। इसके विपरीत घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया। एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार रहा, जबकि अमेरिकी बाजारों में भी अलग-अलग रुझान देखने को मिले। कल एक हजार अंक से अधिक की गिरावट के बाद आई इस तेजी ने निवेशकों को राहत दी।

सुविधा | जियो, वनवेब और स्टारलिंक के बाद अब अमेजन की भी भारतीय उपग्रह संचार बाजार में दस्तक

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का दायरा बढ़ाने की तैयारी में अमेजन

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत में उपग्रह संचार सेवाओं का दायरा बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी तेज होने की संभावना है। एलन मस्क की स्टारलिंक के बाद अब अमेरिकी कंपनी अमेजन ने भी भारत में अपनी उपग्रह संचार सेवा शुरू करने में रुचि दिखाई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को बताया कि अमेजन इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहता है। इससे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार और दूरदराज के क्षेत्रों तक संचार सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है।

संचार मंत्री ने यहां यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रिलायंस जियो, भारती एंटरप्राइजेज की



ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय संचार मंत्री।

वनवेब और अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। अब एक अन्य कंपनी भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक है। उन्होंने अमेजन का उल्लेख करते हुए कहा कि कंपनी को इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अमेजन अपनी उपग्रह इंटरनेट सेवा को अमेजन लियो के नाम से संचालित करने की योजना पर काम कर रही है। इस सेवा के माध्यम से उपग्रहों की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देता है। इसी सोच के तहत उपग्रह संचार के क्षेत्र में भी अलग-अलग कंपनियों को अवसर देने की नीति अपनाई गई है। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। हालांकि, किसी भी कंपनी को सेवा शुरू करने से पहले सरकार की ओर से निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा।

मंत्री के अनुसार, राजस्व शुल्क संबंधी व्यवस्था को अंतिम रूप देने के साथ सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और अन्य निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है। संबंधित कंपनियों को इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। उपग्रह संचार सेवाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा और नेटवर्क की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए सरकार की ओर से लाइसेंस जारी करने और परिचालन की अनुमति देने की प्रक्रिया में इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का उद्देश्य केवल भारत में उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में तकनीक की रूपरेखा तैयार करने, उसका विकास करने और उत्पादन करने की क्षमता को भी मजबूत करना है। इसी क्रम में 'मेड इन इंडिया' से आगे बढ़कर 'डिजाइन-डेवलप्ड मेड इन इंडिया' की दिशा में काम करने पर जोर दिया जा रहा है। उपग्रह संचार सेवाओं के विस्तार से देश के डिजिटल ढांचे को मजबूती मिल सकती है।

दूरदराज के इलाकों तक पहुंचेगा इंटरनेट

सिंधिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इस दिशा में उपग्रह संचार को ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। जहां पारंपरिक संचार नेटवर्क स्थापित करना कठिन या महंगा होता है, वहां उपग्रह आधारित तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपग्रह संचार सेवाओं की कीमत सरकार तय करेगी। इससे इस क्षेत्र में सेवाओं की दरों और उपभोक्ताओं की पहुंच को लेकर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इससे पहले अपने संबोधन में संचार मंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में संचार नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब आगामी दस वर्षों में संचार सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने और तकनीकी क्षमताओं के विकास पर जोर रहेगा।

अमेरिकी प्रतिबंध से बेअसर रहेगी टीसीएस, शेयर में 6.2 प्रतिशत उछाल

एजेंसी, मुंबई

देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने कहा है कि अमेरिका द्वारा विदेशी कर्मचारियों की स्थायी भर्ती पर रोक लगाने के फैसले का उसके कारोबार और कार्यबल संबंधी रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पिछले दो वर्षों में स्थायी श्रमिक प्रमाणन (पीईआरएम) कार्यक्रम के तहत उसके आवेदनों की संख्या 10 से भी कम रही है।

अमेरिका ने आठ कंपनियों के लिए पीईआरएम कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की है। इसके तहत इन कंपनियों के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और पहले से लंबित आवेदन भी रद्द कर दिए जाएंगे। प्रतिबंधित कंपनियों में भारतीय कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और विप्रो शामिल हैं।

टीसीएस का शेयर 6.2 प्रतिशत चढ़ा

अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ सोंडर्लिंग ने आरोप लगाया कि संबंधित कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर उनकी जगह विदेशी नागरिकों को नौकरी दे रही हैं। वहीं, टीसीएस ने शेयर बाजारों को दिए बयान में कहा कि उसने अमेरिकी सरकार के आदेश पर गौर किया है और उसका पूरी तरह पालन करेगी। कंपनी के अनुसार, अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती उसकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पहले ही 15 हजार अमेरिकियों को नौकरी देने की योजना घोषित कर चुकी है। इस बीच, टीसीएस का शेयर शुक्रवार को 6.2 प्रतिशत चढ़कर 2,204 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर लाभ में 7.6 प्रतिशत और राजस्व में 11.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 12 रुपये प्रति शेयर लाभांश देने की भी घोषणा की है।